प्रेरणा

कभी-कभी हमें, उन लोगों से शिक्षा मिलती है, जिन्हें हम अभिमान वश अज्ञानी समझते हैं।- प्रेमचंद

संपादकीय

कोर्ट का निर्देश प्रजातंत्र के भरोसे को पुख्ता करता है

बिहार में जारी विशेष सघन पुनरीक्षण के खिलाफ तमाम याचिकाओं पर कई दिनों की सुनवाई के बाद एससी ने चुनाव आयोग को कुछ निर्देश दिए हैं जिनके अमल में आने के बाद इस प्रक्रिया पर होने वाले लगभग सभी संदेह दूर हो जाएंगे। विपक्ष ने एक दिन पहले ही पुनरीक्षण की प्रक्रियात्मक खामी और आयोग की मंशा को लेकर आंदोलन के दौरान कहा था कि मांगें न मानी जाने पर सभी विपक्षी दल चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। कोर्ट ने आयोग की दलील खारिज करते हुए कहा कि वोटर्स लिस्ट में नाम की पात्रता के लिए आयोग द्वारा तय 11 दस्तावेजों के अलावा आधार को भी एक दस्तावेज माना जाए। साथ ही कोर्ट ने आयोग से सभी प्रमुख अखबारों, वेबसाइट्स और सरकारी सोशल मीडिया पर जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनके नाम हटाने जाने के कारण स्पष्ट करने को कहा है। एससी का निर्देश प्रजातंत्र के उस भरोसे को पुख्ता करता है, जिससे किसी एक संस्था पर भरोसा कम होने की स्थिति में भले ही वह संस्था कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, स्वतंत्र न्यायपालिका उठ खड़ी होती है। कभी-कभी इस संस्था की प्रतिक्रिया में प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण भले ही देरी हो, लेकिन भारतीय समाज ने देखा कि चुनावी बांड के वर्षों अस्तित्व में रहने के बावजूद एक समय आया, जब एससी ने इसे खत्म किया। धन्यवाद, सर्वोच्च न्यायालय!

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

उदासीन हो जाएं, पर उदास ना हों... इन दोनों में फर्क है

उदास होने की स्थितियां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के जीवन में अधिक होती हैं। आजकल भारतीय घरों में अधेड़ उम्र की माताओं-बहानों के मुंह से सुना जाता है कि अब हमारे हाथ-पैर नहीं चलते। कुछ देवियां तो अधेड़ उम्र और वृद्धावस्था में रोटी बनाने का अभ्यास कर रही हैं, ताकि यह भी ना छूट जाए। एक बात और जानकारी में आती है कि प्रसव काल में जिन माताओं-बहनों के आसपास सास-ससुर, माता-पिता और जीवनसाथी रहे हैं, उनको गर्भावस्था के पश्चात उदासी नहीं घेरती। कामकाजी महिलाएं और गृहणी महिलाओं की तुलना भी दोनों को ही उदास करती है। इसलिए महिलाओं को विशेष रूप में एक निर्णय लेना चाहिए कि उदासीन हो जाएं, पर उदास ना हों। इन दोनों में फर्क है। उदासीन शब्द का अर्थ है उद्-आसीन। जो अपने भीतर बैठा हो, वो उदासीन। जिसने स्वयं की ओर यात्रा की हो, जो अपने में स्थित हो। और ऐसा होता है योग और ध्यान से। इसलिए माताओं-बहनों को ध्यान-योग से अवश्य जुड़ना चाहिए।

•Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

दूरदृष्टि • चीन का ट्रम्प कार्ड बन गए हैं रेयर-अर्थ

रेयर-अर्थ तत्वों को लेकर चीन की बराबरी मुश्किल है

टेक्नोलॉजी
एंजेला झांग
हांगकांग यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर

अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता में चीन द्वारा रेयर-अर्थ का हथियार के तौर पर इस्तेमाल एक प्रमुख मसला बन गया है। ये महत्वपूर्ण तत्व, खासतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले चुम्बक, इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टरबाइन, औद्योगिक रोबोटिक्स और अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के लिए बेहद जरूरी हैं। रेयर-अर्थ निर्यात पर चीन के इस कठोर नियंत्रण के परिणास्वरूप अमेरिका ने टैरिफ में काफी कमी कर दी। एआई चिप पर निर्यात प्रतिबंधों में रियायत दी और यहां तक कि चीनी छात्रों के लिए वीजा प्रतिबंधों में भी राहत दे दी।

इसी के साथ अमेरिका वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था भी बनाने में जुटा है। जुलाई में ही रक्षा विभाग ने अमेरिका के फ्लैगशिप रेयर-अर्थ प्रोजेक्ट की कर्ता-धर्ता कंपनी एमपी मैटेरियल को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर के ऐतिहासिक निवेश पैकेज की घोषणा की। लेकिन क्या होगा यदि भारी सब्सिडी और वर्षों की मेहनत के बाद भी अमेरिका चीनी रेयर-अर्थ पर निर्भरता खत्म ना कर सके?

इसमें जापान की कहानी एक सबक देती है। 2010 में सेंकाकू द्वीप को लेकर एक समुद्री टकराव के बाद चीन ने जापान को रेयर-अर्थ का निर्यात रोक दिया था। इसके जवाब में जापान सरकार ने कई सारे रणनीतिक कदम उठाए। इसमें ऑस्ट्रेलियाई उत्पादक 'लिनास रेयर-अर्थ' में निवेश, री-साइकलिंग में घरेलू शोध में बढ़ोतरी, चीनी चुंबक निर्माताओं के साथ व्यावसायिक साझेदारी बनाना और भविष्य में आपूर्ति की किल्लत से बचने के लिए रणनीतिक भंडार बनाना शामिल था। लेकिन एक दशक बीतने के बावजूद जापान आज भी अपने आयात का 70% रेयर-अर्थ चीन से ले रहा है।

रेयर-अर्थ में चीन का दबदबा रातोंरात नहीं बना। चीन की ताकत कच्चे माल के संचय नहीं, उनके शोधन, प्रसंस्करण और बड़े पैमाने पर उत्पादन की औद्योगिक क्षमता में निहित है। वैश्विक रेयर-अर्थ प्रसंस्करण क्षमता के 85% से 90% हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। वह दुनिया के उच्च गुणवत्ता वाले रेयर-अर्थ चुंबकों का लगभग 90% हिस्सा उत्पादित करता है। यही एकमात्र देश है, जिसके पास रेयर-अर्थ के खनन से लेकर रासायनिक पृथक्करण और चुंबक निर्माण तक की पूर्ण एकीकृत सप्लाई चेन है।

विनिर्माण में चीन की श्रेष्ठता ने ना केवल उसे औद्योगिक बढ़त दी, बल्कि तकनीकी तौर पर उसे अभेद सुरक्षा भी प्रदान की है। 1950 से 2018 के बीच, चीन ने रेयर-अर्थ संबंधी 25 हजार से अधिक पेटेंट दायर किए, जो अमेरिका में दायर पेटेंट से दोगुने हैं। रेयर-अर्थ प्रसंस्करण की जटिल केमिस्ट्री और धातु विज्ञान में दशकों के व्यावहारिक अनुभव ने चीन को ऐसी विशेषज्ञता दी है, जिसके बराबर पश्चिमी कंपनियां आसानी से नहीं पहुंच पाएंगी। अपनी बढ़त को और मजबूत करने के लिए चीनी सरकार ने दिसंबर 2023 में रेयर-अर्थ उत्खनन, पृथक्करण और चुंबक उत्पादन तकनीकों पर व्यापक निर्यात प्रतिबंध भी लगा दिए।

चीन के लचर पर्यावरणीय नियमों ने भी उसे पश्चिमी प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाई है। 2002 में कैलिफोर्निया के माउंटेन पास रेयर-अर्थ माइन को एक विषाक्त कचरे के रिसाव के बाद शोधन कार्य रोकने पड़े थे। इसके विपरीत, चीन के उदार नियामकों ने कम देरी और बहुत कम लागत के साथ रेयर-अर्थ उत्पादन को तेजी से बढ़ने का मौका दिया है।

अधिक महत्वपूर्ण यह है कि रेयर-अर्थ संबंधी समस्याएं फिक्स नहीं हैं। वे प्रौद्योगिकी के साथ पनपती रहती हैं। चीन इसे समझ गया और उसने धैर्यपूर्वक

अमेरिकी तकनीक पर चीन की निर्भरता जितनी बढ़ेगी, दोनों देशों की सप्लाई चेन उतनी ही आपस में गुंथती चली जाएंगी। और तब चीन के लिए रेयर-अर्थ समेत किसी भी रणनीतिक सम्पत्ति का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना कठिन होगा।

प्रतीक्षा की। वैश्विक हरित बदलावों के साथ रेयर-अर्थ पर पश्चिम की निर्भरता बढ़ी तो इसने ईवी और विंड टरबाइनों की भारी मांग पैदा कर दी।

इसलिए अमेरिका को इस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि रेयर-अर्थ के मामले में चीन का प्रभुत्व अभी बना रहेगा। सप्लाई चेन के विविधीकरण जैसी रक्षात्मक रणनीतियां कुछेक जोखिमों का हल हो सकती हैं। लेकिन सही मायनों में अनुकूलन तो एक आक्रामक रणनीति से ही संभव है। हालांकि अभी भी अमेरिका के हाथ में कई तुरुप के पत्ते हैं। जब तक उसकी एडवांस चिप, अग्रणी एआई मॉडल्स और डॉलर आधारित वित्तीय तंत्र जैसी तकनीक और बुनियादी ढांचे पर पकड़ बरकरार है, चीन को रेयर-अर्थ की आपूर्ति करनी होगी। कई वर्षों तक अमेरिका चीन को प्रमुख तकनीकों की आपूर्ति रोक कर उल्टी चाल चलता रहा है।

ट्रम्प द्वारा चीन को एनवीडिया के एच-20 चिप्स की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में राहत देना बताता है कि सोच अब प्रतिबंधों से हटकर संतुलित जुड़ाव की ओर बढ़ रही है। यह जोखिम कम करने का स्मार्ट तरीका हो सकता है। (© प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

मुद्दा • पर्वतीय क्षेत्र तेजी से अपनी बर्फ खो रहे हैं

दुनिया की तुलना में एशिया अधिक तेजी से गर्म हो रहा है

क्लाइमेट
सीमा जावेद
पर्यावरणविद्
dr.seemajaved@gmail.com

विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट 'स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024' के मुताबिक एशिया वैश्विक औसत की तुलना में लगभग दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। इसका असर अब सिर्फ वैज्ञानिक आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकीय तंत्र तक गहराई से महसूस किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, 2024 में वैश्विक सतही औसत तापमान 1850-1900 के पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। यह 2023 के 1.45 डिग्री रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब तक का सबसे गर्म वर्ष बन गया। रिपोर्ट में शामिल छह वैश्विक डेटा सेट्स में से सभी ने इस रिकॉर्ड को मान्यता दी है।

साथ ही यह रेखांकित किया गया कि 2015 से 2024 तक के सभी वर्ष अब तक के 10 सबसे गर्म वर्षों में शामिल हैं। इस निरंतर प्रवृत्ति को देखते हुए अब वैज्ञानिकों की चिंता केवल भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि वर्तमान में जलवायु से जुड़ी आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को लेकर है। रिपोर्ट के अनुसार, एशिया का औसत तापमान 2024 में 1991-2020 के औसत से 1.04 डिग्री अधिक रहा। भूभागीय विस्तार के कारण एशिया वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहा है, क्योंकि भूमि का तापमान महासागरों की तुलना में तेजी से बढ़ता है।

पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के कई हिस्सों में लगातार महीनों तक भीषण गर्मी देखने को मिली। म्यांमार में 48.2 डिग्री का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज हुआ, जबकि चीन, कोरिया और जापान जैसे देशों में महीना-दर-महीना तापमान रिकॉर्ड टूटते रहे। 2024 में एशिया के समुद्री क्षेत्र में अब तक की सबसे व्यापक और तीव्र समुद्री हीटवेव दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, समुद्री सतह का तापमान हर दशक में 0.24 डिग्री बढ़ रहा है- यह दर वैश्विक औसत 0.13 डिग्री से लगभग दोगुनी है।

अगस्त और सितंबर 2024 के बीच, एशिया के लगभग 15 मिलियन वर्ग किमी समुद्री क्षेत्र- जो पृथ्वी के महासागरों का लगभग 10% है- भीषण गर्मी से प्रभावित रहा। विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी हिंद महासागर, जापान के समीपवर्ती क्षेत्र और येलो व ईस्ट चाइना सी में हीटवेव की तीव्रता सबसे अधिक रही।

इसका असर न केवल समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र पर पड़ा, बल्कि तटीय आजीविका, मछली पालन और समुद्री जैव विविधता पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है।

हाई माउंटेन एशिया क्षेत्र, जिसमें हिमालय, तिब्बती पठार और तियान शान पर्वतमाला शामिल हैं, अब तेजी से बर्फ खो रहा है। यह क्षेत्र धरती का तीसरा ध्रुव माना जाता है क्योंकि यहां दुनिया का सबसे बड़ा गैर-ध्रुवीय हिम-भंडार स्थित है। 2023-2024 में 24 में से 23 ग्लेशियरों में द्रव्यमान हानि दर्ज की गई। मध्य हिमालय और तियान शान क्षेत्रों में सर्दियों में कम बर्फबारी और गर्मियों में अत्यधिक तापमान ने इस स्थिति को और बिगड़ा। उरुमची ग्लेशियर नंबर 1, जो 1959 से मॉनिटर किया जा रहा है, ने अब तक का सबसे नकारात्मक द्रव्यमान संतुलन दर्ज किया।

ग्लेशियरों के पिघलने से उत्पन्न हो रही झीलें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, भूस्खलन और जल संकट जैसे खतरों को जन्म दे रही हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि 2024 में एशिया को कई चरम मौसम संबंधी आपदाओं का सामना करना पड़ा। नेपाल में सितंबर में भारी बारिश और बाढ़ से 246 लोगों की मौत हुई, 94 करोड़ से अधिक का नुकसान

जलवायु संकेतकों में आ रहे परिवर्तन समाजों, अर्थव्यवस्थाओं, पारिस्थितिकी के लिए जोखिम बन चुके हैं। अब यह पहले से कहीं अधिक आवश्यक है कि नीति निर्माता जलवायु अनिश्चितताओं से निपटने के लिए कदम उठाएं।

हुआ। भारत के केरल में जुलाई में 48 घंटे के भीतर 500 मिमी से अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण बड़े स्तर पर भूस्खलन हुआ और 350 से अधिक मौतें दर्ज की गईं। चीन में 4.8 मिलियन लोग सूखे से प्रभावित हुए, 3.35 लाख हेक्टेयर फसलें नष्ट हुईं, 400 करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ। यूएई में 24 घंटे में 259.5 मिमी बारिश हुई, जो 1949 से अब तक की सबसे अधिक है। कजाकिस्तान व दक्षिणी रूस में 70 वर्षों की सबसे भीषण बाढ़ आई, जिससे 1.18 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा। इसके अलावा, ट्रॉपिकल साइक्लोन यागी ने वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और चीन में तबाही मचाई।

जलवायु संकेतकों में आ रहे परिवर्तन अब समाजों, अर्थव्यवस्थाओं, पारिस्थितिकी के लिए गंभीर जोखिम बन चुके हैं। अब यह पहले से कहीं अधिक आवश्यक है कि मौसम विज्ञान एजेंसियां, नीति निर्माता और समुदाय मिलकर जलवायु अनिश्चितताओं से निपटने के लिए कदम उठाएं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

16 अगस्त के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में
इकोनॉमिस्ट ने कवर स्टोरी में दुर्लभ खनिजों पर चीन द्वारा रोक की रणनीति की पड़ताल की है। मैग्जीन ने वीडियो गेमिंग में ब्रिटेन की स्थिति का आकलन किया है।

The Economist

दैनिक भास्कर
अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

फाइनेंस

हार्वर्ड, येल ने 15 हजार करोड़ के बॉण्ड जारी किए

अमेरिका के नामी विश्वविद्यालयों (आईवी लीग) के लिए पिछला साल आर्थिक दृष्टि से मुश्किल रहा है। आईवी लीग के सभी आठ कॉलेज एसएंडपी-500 इंडेक्स में कम से कम दस अंक पीछे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ लड़ाई में उलझे कोलंबिया और हार्वर्ड विवादों को निपटाने के लिए करोड़ों रुपए चुका रहे हैं। उनका निवेश पाने का एनडोमेंट मॉडल कठिनाई में है। भारी फीस, धन की कमी और धन जुटाने की रणनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। येल सहित कुछ कॉलेजों, विश्वविद्यालयों ने नगद धन जुटाने के लिए इक्विटी बेचने की पेशकश की है। वे बॉण्ड जारी कर रहे हैं। जनवरी के बाद से आईवी लीग विश्वविद्यालयों ने लगभग 15 हजार करोड़ रुपए के बॉण्ड जारी किए हैं। यह 2020 के बाद सबसे अधिक है। उन्होंने ऐसी दरों पर कर्ज लिया है, जो कई कंपनियों, सरकारों और दूसरी यूनिवर्सिटीज को नहीं मिलता है। हार्वर्ड, प्रिंसटन और येल द्वारा जारी महंगे बॉण्ड 0.34 परसेंटेज पाइंट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यह ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी द्वारा जारी बॉण्ड के बराबर है। भारी-भरकम फंड के कारण आईवी लीग के संस्थानों का मैनेजमेंट राहत की सांस ले सकता है। हार्वर्ड के पास 4.64 लाख करोड़ रुपए का फंड है। लंबी अवधि में कम जोखिम के अलग -अलग इन्वेस्टमेंट का उनका एनडोमेंट मॉडल छोटे शिक्षण संस्थानों के मुकाबले बेहतर साबित हुआ है। कर्ज तक उनकी पहुंच अच्छी है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

कूटनीति • मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स जैसी कई जरूरी चीजों के निर्यात में रोक से चीन कर रहा है खेल

अपने दबदबे के लिए चीन की निर्यात पर रोक की नीति, 700 जरूरी वस्तुएं लाइसेंस के दायरे में

पिछले कुछ समय से चीन व्यापार के जरिये अपने रणनीतिक हित साध रहा है। उसने आर्थिक हथियारों के बूते दुनिया पर नियंत्रण कायम कर रखा है। अमेरिका-चीन में हुआ व्यापार युद्धविराम इसका ताजा उदाहरण है। चीन ने अप्रैल में दुर्लभ खनिजों का निर्यात रोका तो विश्व में हड़कंप मच गया था। दुनियाभर में दहशत फैल गई। अमेरिका की पहल पर सप्लाई बहाल हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को चीन के आधुनिक चिप्स की सप्लाई पर रोक हटाना पड़ी है।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन के प्रभाव से फायदा उठाने के लिए निर्यात पर नियंत्रण का सिस्टम लागू किया है। पिछले साल दिसंबर से मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और जरूरी खनिजों सहित 700 से अधिक वस्तुओं को लाइसेंस के दायरे में लाया गया है। चीनी अधिकारी प्रोडक्ट के कंज्यूमर का बारीकी से पता लगाकर लायसेंस जारी करते हैं। दुर्लभ खनिजों का निर्यात शुरू हो गया है लेकिन पश्चिमी देशों के हथियार निर्माताओं को सप्लाई अब भी बंद है।

दुर्लभ खनिजों का हथियार के तौर पर उपयोग कारगर साबित हुआ है। ट्रम्प ने चीन को एनवीडिया के कुछ चिप्स की बिक्री पर लगी रोक हटा दी। भारी आयात शुल्कों को टाल दिया। 11 अगस्त को अमेरिका-चीन ने टैरिफ व कारोबार से जुड़े अन्य फैसलों पर 90 दिन के लिए अमल रोक दिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है, दुर्लभ खनिजों का चीनी हथियार लंबे समय तक काम नहीं करेगा। सभी देश विकल्प तैयार कर लेंगे।

चीन सप्लाई चेन पर उसके कंट्रोल को दूसरे देशों पर प्रभाव जमाने के साधन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि चीन पर निर्भरता से दूसरे देश काबू में रहेंगे। किसी भी वस्तु की कमी से उस पर इनोवेशन ज्यादा होने लगता है। अमेरिका ने चिप पर कंट्रोल लगाया तो हुआवे और डीपसीक ने नई तकनीक खोज ली। 2022 में कोबाल्ट की कमी के बाद ईवी निर्माताओं ने कोबाल्ट का विकल्प खोज लिया। पश्चिमी देशों में नई कंपनियां दुर्लभ खनिजों की रिसाइक्लिंग कर रही हैं। उनके बिना मैग्नेट्स और मोटर बनाने का तरीका विकसित किया जा रहा है। यूरोपीय कार कंपनियां बीएमडब्लू और रेनॉल्ट ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन बेच रही हैं, जिनकी मोटरों में दुर्लभ खनिजों का इस्तेमाल नहीं होता है। चीन दुर्लभ खनिजों के हथियार का जितना अधिक इस्तेमाल करेगा, वह उतना ही कमजोर होगा।

कार इंडस्ट्री में दहशत फैल गई थी

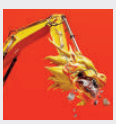

चीन दुनिया की जरूरत के 90 प्रतिशत दुर्लभ खनिजों का निर्यात करता है। इनसे बने मैग्नेट्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर, वैक्यूम क्लीनर, कारों, जेट विमानों से लेकर सैनिक साज-सामान के निर्माण में होता है। सप्लाई पर रोक का हर जगह असर देखा गया। शिकागो में फोर्ड की फैक्ट्री बंद हो गई थी। भारत, जापान में कार निर्माताओं ने प्रोडक्शन में कटौती कर दी। एक कंपनी के बॉस ने कहा, कार इंडस्ट्री दहशत में है।

पहले भी लगाई है रोक

चीन की नई रोक बताती है कि उसका आर्थिक शस्त्रागार कितना असरदार है। वह कई वर्षों से आर्थिक हथियार का उपयोग कर रहा है। 2010 में राजनीतिक विवाद के बाद उसने जापान को दुर्लभ खनिजों की सप्लाई कुछ समय के लिए बंद कर दी थी। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के बीफ पर ड्यूटी बढ़ा दी। जिनपिंग चाहते हैं कि चीन को जरूरी चीजों के लिए प्रतिद्वंद्वी देशों पर निर्भर न रहना पड़े।

देश तलाश रहे विकल्प

चीन की रोक के बाद दुर्लभ खनिजों के विकल्पों की तलाश शुरू हो गई है। 2010 के बाद जापान ने खदानों में निवेश किया है। पहले चीन पर उसकी निर्भरता 90% थी। अब 60% रह गई है। इस साल पेंटागन ने कैलिफोर्निया में दुर्लभ खनिज खदान के लिए करार किया है। एपल का भी उसी कंपनी से करार है। अमेरिका में 2030 तक 22 नए माइनिंग प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

वर्ल्ड इन ब्रीफ

अमेरिका के कई शहरों में मकानों के मूल्य कम हो रहे

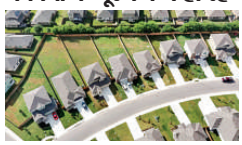

अमेरिका में महामारी के समय अटलांटा, ऑस्टिन, मियामी जैसे शहरों में हाउसिंग मार्केट उफान पर था। कर्ज पर ब्याज दर दो प्रतिशत के आसपास थी। अब मार्केट लड़खड़ा रहा है। पिछले तीन माह में कई शहरों में मकानों के मूल्य चार प्रतिशत तक नीचे आए हैं। 7 प्रतिशत की ऊंची ब्याज दर से प्रॉपर्टी मार्केट प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा गिरावट दक्षिणी इलाकों में आई है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी ठंडे पड़े हैं। 2025 की दूसरी छमाही में निजी उपभोग और इन्वेस्टमेंट की दर 1.2 प्रतिशत रही। इस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में जल्द कटौती करेगा।

ब्रिटेन की विकास दर बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही

ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस साल की दूसरी तिमाही में केवल 0.3 प्रतिशत बढ़ी है। यह जानकारी प्रारंभिक आंकड़ों में दी गई है। पिछली तिमाही के मुकाबले विकास दर की गति धीमी है। उस वक्त 0.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। हालांकि, इतनी कम विकास दर को पूर्व अनुमानों से बेहतर बताया जा रहा है। सर्विस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन से यह दर हासिल हो सकी है। वैसे, ब्रिटेन की लेबर सरकार मामूली बढ़ोतरी का भी स्वागत करेगी। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने आर्थिक विकास को अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखा है।

यूरोप के कई देशों में गर्मी से जंगलों में आग भड़की

यूरोप के कई देश तापमान में बढ़ोतरी के कारण जंगलों की आग से जूझ रहे हैं। ग्रीस के तीसरे सबसे बड़े शहर पत्रास के कई इलाकों को खाली कराया गया है। जंगल की आग शहर के बाहरी इलाकों तक पहुंच गई है। पिछले कुछ समय से ग्रीस में कई इलाके जंगलों की आग से प्रभावित हो रहे हैं। कई यूरोपीय देशों में तापमान 40 डिग्री सेंटिग्रेड से ऊपर पहुंच गया है। यूरोपियन फॉरेस्ट फायर इंफॉरमेशन सिस्टम के अनुसार इस साल यूरोप में अब तक जंगलों की आग पिछले साल के मुकाबले दोगुना आंधक इलाके में फैली है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

टेक्नोलॉजी • म्यूजिक-फिल्म से ज्यादा कमाई वीडियो गेम से हो रही

ब्रिटेन वीडियो गेमिंग की सुपरपावर बन रहा है

दुनिया में वीडियो गेमिंग से हर साल 17.50 लाख करोड़ रुपए की आय होती है। इसमें ब्रिटेन ने खास जगह बना ली है। अमेरिका, जापान के बाद वह गेम्स का तीसरा बड़ा निर्यातक है। अभी हाल में ब्रिटेन के फाल गाइज, लिटिल बिग प्लैनेट, टोटल वार: वार हैमर जैसे गेम चर्चित रहे हैं। ब्रिटेन को फिल्म-म्यूजिक इंडस्ट्री की तुलना में वीडियो गेम्स से अधिक आय (4.3 अरब पौंड) होती है।

1980 के दशक में ब्रिटेन में पर्सनल कंप्यूटर गेम्स से क्रिएटिविटी की शुरुआत हुई थी। उधर, अमेरिका, जापान के मार्केट कंसोल से चल रहे थे। 1997 में डुंडी एबरटे यूनिवर्सिटी ने दुनिया की पहले कंप्यूटर गेम डिग्री लॉन्च की। ब्रिटेन मोबाइल गेम्स बनाने में भी माहिर है। अमेरिका में 2021 में सबसे अधिक कमाने वाला स्पोर्ट्स मोबाइल गेम गोल्फ क्लैश ब्रिटेन के चेशायर में बनाया था। सॉलिटेयर गेम के लिए पॉपुलर ट्रिपलडॉट स्टूडियो लंदन में है। उसने जून में अमेरिकी टेक कंपनी एपलोविन को सात हजार करोड़ रुपए में खरीदा है।

ब्रिटेन का वीडियो गेम एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है। 2016 में उसका निर्यात 28,700 करोड़ रुपए था, वहीं 2021 में 77 हजार करोड़ रुपए हो गया। इंडस्ट्री में 30 हजार लोग काम कर रहे हैं। ब्रिटेन ने गेमिंग का अन्य कामों में भी अच्छा इस्तेमाल किया है। वीआर से डॉक्टर सर्जरी की रिहर्सल करते हैं। तो पायलट विमानों के टेक ऑफ की ट्रेनिंग लेते हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस चिंता और अवसाद जैसी बीमारियों के इलाज में वीडियो गेम्स प्रिस्क्राइब करती है।

17 हजार करोड़ रु. की लागत से बन रहा एक गेम

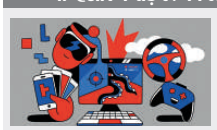

2026 में 17,500 करोड़ रुपए से ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सिक्स्थ गेम बन रहा है। हालांकि जुलाई में माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग डिवीजन में छंटनी की है। इससे ब्रिटेन में प्रोजेक्ट रद्द हो गए हैं। सोनी ने 2024 में लंदन में अपना स्टूडियो बंद कर दिया है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

ओपिनियन • पहले भी सेना लगा चुके

अपराधों में कमी के बावजूद ट्रम्प ने वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड तैनात किए

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन इस सप्ताह वर्तमान राष्ट्रपति के दिखावे का प्रतीक बन गई। 11 अगस्त को राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी राजधानी पर हिंसक गिरोहों, नशेड़ियों, बेघरों का कब्जा हो गया है। इसके बाद वहां नेशनल गार्ड तैनात कर दिए। पुलिस फोर्स का नियंत्रण हाथ में ले लिया।

ट्रम्प द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना के इस्तेमाल का पहला मौका नहीं है। वे इमेग्रेशन छापों के विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल गार्ड तैनात कर चुके हैं। उन्होंने 2020 में वॉशिंगटन में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नेशनल गार्ड का उपयोग किया था।

ट्रम्प ने अपने फैसले को जायज ठहराने के लिए कुछ हिंसक घटनाओं के उदाहरण दिए हैं। उन्होंने वॉशिंगटन की तुलना बगदाद और बोगोटा से की है। वॉशिंगटन 2023 में अमेरिका के सबसे खतरनाक शहरों में शामिल था। लेकिन अब अपराधों में गिरावट आई है। ट्रम्प ने इसका जिक्र नहीं किया है।

ट्रम्प का अड़ंगा

ट्रम्प ने वॉशिंगटन में निर्वाचित सरकार को दरकिनार कर दिया है। संसद में ट्रम्प और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद शहर की सरकार को पुलिस और अन्य सेवाओं पर खर्च की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। इस तरह रिपब्लिकन सांसदों ने वॉशिंगटन में अपराध की समस्या बढ़ाई है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

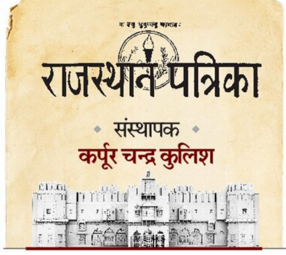

यूरिया संकट: राजनीतिक खींचतान में पिसता किसान

किसानों के लिए समय पर और भरपूर बारिश किसी आशीर्वाद से कम नहीं होती। कर्नाटक में इस बार कृषि की जरूरत के अनुरूप समय पर और भरपूर बारिश हुई तो अच्छी फसल की उम्मीद में किसानों के चेहरे चमक उठे थे। खेतों में हरियाली और बढ़े हुए रकबे की फसलें एक बेहतर भविष्य की आहट दे रही थीं। लेकिन यूरिया की कमी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उर्वरक आपूर्ति को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच आंकड़ों की लड़ाई जारी है।

सत्ता पक्ष-विपक्ष के नेता समस्या के समाधान से ज्यादा एक-दूसरे पर राजनीतिक तीर चलाने में रुचि दिखा रहे हैं। विधानमंडल में भी चर्चा आरोप-प्रत्यारोप तक सिमट कर रह गई। राज्य का कहना है कि यूरिया उपलब्ध कराना केंद्र की जिम्मेदारी है, वह केवल वितरण का काम करता है। उधर, केंद्र का दावा है कि खरीफ सीजन के लिए कर्नाटक को आवश्यकता से भी अधिक यूरिया उपलब्ध कराया गया है। इन दलीलों के बीच सबसे बड़ी कीमत किसान चुका रहे हैं। उन्हें समय पर, रियायती दर पर यूरिया नहीं मिल पा रहा और वे भटकने को मजबूर हैं। यह सर्वविदित है कि कृषि उत्पादन की रीढ़ समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होना है। बुआई का वक्त निकल जाए या फसल को शुरुआती चरण में आवश्यक पोषण न मिले, तो 'का वर्षा जब कृषि सुखानी' की कहावत चरितार्थ होती है। किसानों की पूरी मेहनत और उम्मीदें बेकार हो जाती हैं। यह केवल प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं, बल्कि सीधे किसान की आजीविका और देश की खाद्य सुरक्षा पर चोट है। किसानों के लिए यह मायने नहीं रखता कि दोषी कौन है, उनके लिए महत्त्वपूर्ण यह है कि उनके खेतों तक समय पर खाद पहुंचे। इसीलिए प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि मौजूदा स्टॉक का पारदर्शी और समान वितरण हो, जमाखोरी व कालाबाजारी पर सख्ती से लगाम लगे और पंचायत स्तर तक निगरानी तंत्र सक्रिय किया जाए। दीर्घकालिक समाधान के लिए राज्य को मांग पूर्वानुमान की वैज्ञानिक प्रणाली विकसित करनी होगी। मौसम, फसल चक्र और बाजार के रुझान को ध्यान में रखते हुए समय रहते आपूर्ति की योजना बने। केंद्र और राज्यों के बीच ऐसा समन्वय हो, जिससे हर सीजन में किसानों को राजनीतिक खींचतान की बलि न चढ़ना पड़े।

किसान पहले ही मौसम की अनिश्चितताओं, बाजार के उतार-चढ़ाव और कर्ज के दबाव से जूझते हैं। ऐसे में यूरिया जैसी बुनियादी जरूरत के लिए उन्हें भटकाना, सरकार की न केवल प्रशासनिक असफलता है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ना है। समय पर खाद उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है, उपकार नहीं। जरूरत इस बात की है कि केंद्र और राज्य दोषारोपण में समय गंवाने के बजाय समाधान खोजें। किसानों की मदद सही समय पर हो, तभी उसका असर होगा।

कृष्ण का नेतृत्व है धैर्य, विवेक और स्वावलंबन का प्रतीक, जन्माष्टमी को केवल परंपरा नहीं, प्रेरणा बनाएं

कृष्ण: कर्मयोग के प्रणेता और अन्याय के प्रतिकारक

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महज सनातन धर्म से जुड़ा एक त्योहार-मात्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में रचा-बसा एक लोकपर्व है। जीवन जीना एक श्रेष्ठतम कला है, इस भाव का सही अर्थों में प्रतिमान जिस लोकनायक ने गढ़ा है उसका नाम है- पार्थसारथी श्रीकृष्ण। तमाम संस्कृतियों में कृष्ण अकेले ऐसे लोकनायक हैं जो जीवन की हरेक परिस्थिति को समग्रता से स्वीकार करते हैं और उसे उत्सव में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। कृष्ण आध्यात्मिक क्रांति के यथार्थ द्रष्टा हैं, वे राग, प्रेम, काम, ध्यान, योग, भोग, आत्मा-परमात्मा, युद्ध, कूटनीति और राजनीति आदि विषयों को यथार्थ रूप में स्वीकार करते हैं। जब मन में गहन अंधकार छाया हो, बंधनयुक्त हो, तब कैसे हमारा पुरुषार्थ हमारे अवचेतन में ऐसा रचनात्मक भाव उत्पन्न कर दे कि सारे बंधन टूट जाएं और अज्ञान के तमस का आवरण टूटकर बिखर जाए, असलियत में यही कृष्ण-तत्व की मौजूदगी है और यही जन्माष्टमी है। किंतु समाज में बढ़ते हुए कदाचार और संवेदनशून्यता के इस दौर में कृष्ण तत्व की गैर-मौजूदगी दिखाई देती है।

असल में जब तक हम समग्रता से जीवन जीने वाले कृष्ण को परंपरागत आस्थाओं के तहत केवल जन्माष्टमी पर्व तक सीमित रखेंगे, हमारे अंदर अन्याय के प्रतिकार करने का साहस और कदाचार से जूझने का संकल्प उत्पन्न नहीं हो सकता। कृष्ण के व्यक्तित्व में जड़-सिद्धांतों व पुरातनपंथी मान्यताओं का कोई स्थान नहीं है। कृष्ण सदैव कर्म के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। वह कोई निजी हित साधने या व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए कर्म से प्रेरित नहीं होते, इसलिए दूसरों को भी कर्मफल की चिंता से मुक्ति का संदेश देते हैं। मधुसूदन कृष्ण का व्यक्तित्व बेहद माधुर्य से ओतप्रोत है। अपनी जीवन-यात्रा के किसी न किसी पड़ाव पर पहुंच कर जब व्यक्ति किंकर्तव्यविमूढ़ होकर अवसादग्रस्त हो जाता है, तब कृष्ण संदेश देते हैं कि हे अर्जुन! उठ और अपना कर्म कर, क्योंकि तू तो केवल निमित्तमात्र है, इस संसार में जो कुछ घटित होता है, वह मेरी इच्छा के फलस्वरूप होता है। इसलिए फल की आसक्ति का परित्याग कर अपने कार्य को समर्पण भाव से कर, यही उनका गीता-दर्शन भी है। उनकी कार्यशैली अपने अधिकारों के प्रति सचेत और दुराचारी व्यवस्था के खिलाफ थी। सही अर्थों में अपने कर्मों का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन सीखना और स्वावलंबन की कला को और बेहतर बनाना है तो कृष्ण के कर्मयोग का विश्लेषणात्मक अध्ययन जरूरी है। वे युद्ध लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं किंतु करुणा और प्रेम से भरे हुए हैं। दरअसल प्रेम और उत्सव के जो आयाम राम में नहीं मिलते वे कृष्ण के व्यक्तित्व में जीवंत हो जाते हैं। राम जीवन के किसी मोड़ पर चिंताग्रस्त दिखाई देते हैं, किंतु कृष्ण दुख के महासागर में भी हंसते, नाचते और गाते हुए नजर आते हैं।

असल में, कृष्ण जीवन की हरेक रंगत को पूर्णता के साथ स्वीकार करते हुए उसका आनंद लेते हैं, यही खासियत उनको वैश्विक युग पुरुष बना देती है। वे एक ऐसे युगपुरुष हैं जो 'सेल्फमेड' हैं। सभी जानते हैं कि वे किसी बड़े सम्राट के पुत्र नहीं हैं, उनकी विरासत भी राजशाही नहीं है। उनका जन्म कंस के बंदीगृह में होता है, जन्मते ही उन्हें जान से मारने की साजिश भी थी। बड़े झंझावाती माहौल के बीच उन्हें बचाया जाता है। वासुदेव-देवकी के यहां जन्मते हैं, लेकिन लालन-पालन होता है नंद और यशोदा के यहां। पर, अपने अथक प्रयासों व सतत पुरुषार्थ से युवा होते-होते वे अपने सामाजिक परिवेश में सिद्धपुरुष अथवा अवतार समझे जाने लगते हैं।

कृष्ण ने अगाध आस्था, निष्ठा और आत्मसंयम से आध्यात्मिक तत्व-दर्शन की शिक्षा अंगिरा ऋषि के आश्रम में प्राप्त की, जबकि अनेक विधाओं सहित चौंसठ कलाएं सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में सीखी। इन तमाम विधाओं व कलाओं में उनकी महारत ही उन्हें समकालीन महत्वाकांक्षी युवराजों व क्षत्रपों की ईर्ष्या, साजिश और द्वेष का पात्र बना देती है। लेकिन कृष्ण इन सभी षड्यंत्रकारी ताकतों का प्रत्युत्तर जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक व सहजता से देते हुए जीवन की ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं। कृष्ण के जीवन की ये तमाम गतिविधियां व उनके कार्यों के क्रियान्वयन का तरीका परिचायक है इस बात का, कि ईश्वर ने हरेक मनुष्य को बुद्धिमत्ता के अनेक आयामों से नवाजा है, अपने विवेक के सटीक इस्तेमाल से उसमें साधारण से असाधारण बनने की असीम संभावनाएं हैं। सतत पुरुषार्थ व आत्मानुशासन से कोई भी व्यक्ति जीवन की तमाम विसंगतियों से पार पा सकता है। इतना ही नहीं वह दृढ़ता के साथ कदाचार व अन्याय का प्रतिकार भी सहजापूर्वक कर सकता है। कृष्ण किसी एक संप्रदाय अथवा विचारधारा को धर्म मानकर अपना मत स्पष्ट नहीं करते। वे जिस धर्म की संस्थापना की बात कर रहे हैं, उसमें जड़ता का लेशमात्र भी स्थान नहीं है।

डॉ. विनोद यादव
शिक्षाविद् एवं इतिहासकार
@patrika.com

जन्माष्टमी: आस्था और प्रकृति संरक्षण का संगम

दुनिया भर में करोड़ों भक्तजन भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। इस अवसर पर मंदिरों में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ता है, सड़कों पर रंग-बिरंगी झांकियां सजती हैं और वातावरण संगीत व भजन-कीर्तन से गूंज उठता है। लेकिन इस भक्ति-भावना के बीच, भगवान कृष्ण के संदेश का एक पहलू अक्सर अनदेखा रह जाता है- प्रकृति के प्रति उनका गहरा प्रेम। भागवत पुराण और महाभारत बताते हैं कि कृष्ण का जीवन स्वयं प्रकृति का उत्सव है। वृंदावन में एक बाल गोपाल के रूप में उन्होंने गाय-बछड़ों की सेवा की, यमुना के तटों पर खेले और पशु-पक्षियों से भरे वनों में विचरण किया। यहां तक कि मूसलाधार वर्षा से गांववासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने का चमत्कार इस सत्य की ओर इशारा करता है कि प्रकृति पवित्र है और उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। इस दर्शन को हम धार्मिक पारिस्थितिकी कह सकते हैं। पृथ्वी के साथ सामंजस्य में रहना भक्ति का ही एक रूप है। जन्माष्टमी हमें आध्यात्मिक उत्सव और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को एक साथ जोड़ने का मार्ग दिखाती है।

कृष्ण की प्रतिमाओं की पूजा जन्माष्टमी का एक प्रमुख अनुष्ठान है, जिन्हें बाद में विसर्जित किया जाता है। दुर्भाग्य से, आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी और रासायनिक रंगों से रंगी मूर्तियां नदियों व झीलों को प्रदूषित करती हैं, जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। इसका समाधान है परंपरा की ओर लौटना- प्राकृतिक मिट्टी की मूर्तियां, जिन्हें हल्दी, नील या मेहंदी जैसे पौधों से बने रंगों से सजाया जाए। ये पानी में घुलकर मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती हैं। घर पर बाल्टी में विसर्जन कर, उसी पानी का उपयोग पौधों में करने से प्रदूषण रोका जा सकता है। मुंबई जैसे शहरों में पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियों की लोकप्रियता साबित करती है कि टिकाऊपन भी सुंदर हो सकता है।

जन्माष्टमी भव्य झांकियों से लेकर मंदिरों की मालाओं तक रंगों का उत्सव है। लेकिन इसमें अक्सर प्लास्टिक के फूल, कपड़े, ग्लिटर जैसी चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो नष्ट न होने वाला कचरा बनाती हैं। इसके बजाय ताजे फूल, केले के पत्ते, बांस, जूट और रिसाइकिल कागज से वही सुंदरता पाई जा सकती है। प्रसाद के बिना जन्माष्टमी अधूरी है। लेकिन इसे प्लास्टिक कप या थर्मोकोल प्लेटों में परोसना सृष्टि के प्रति आभार की भावना के विपरीत है। इसके स्थान पर केले के पत्ते, सुपारी के पत्तों से बनी प्लेट या पुनः उपयोग योग्य स्टील के बर्तन बेहतर विकल्प हैं। मेहमानों को अपने बर्तन लाने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। जैविक और स्थानीय सामग्री टिकाऊ खेती के लिए उपयोगी है और कार्बन उत्सर्जन घटाती है। कृष्ण की उदारता के अनुरूप बचा हुआ प्रसाद आश्रयों या सामुदायिक रसोई को दान किया जा सकता है, जबकि जैविक कचरे को खाद में बदला जा सकता है।

मानव पिरामिड बनाकर दही से भरे मिट्टी के मटके को तोड़ने की दही हांडी की परंपरा कृष्ण के माखन-प्रेम की याद दिलाती है। लेकिन कई जगहों पर मिट्टी के मटकों की जगह प्लास्टिक के बर्तन आ गए हैं। फिर से मिट्टी के मटके अपनाना उत्सव को असली रूप में और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगा। मटके के टुकड़ों को इकट्ठा कर पुनः उपयोग करना और स्थल की सफाई करना उत्सव को स्वच्छ रखता है।

जन्माष्टमी एक पर्व से बढ़कर सामुदायिक आंदोलन की शुरुआत बन सकती है। सोचिए, अगर 'कृष्ण उद्यान' लगाया जाए, जिसमें तुलसी, गेंदा और देशी वृक्ष हों या यमुना के प्रति कृष्ण की प्रेमभावना को याद करते हुए नदी किनारे सफाई अभियान हो। डिजिटल निमंत्रण, लाइव-स्ट्रीम कीर्तन और वर्चुअल झांकियां कागज की बर्बादी घटाकर विश्वभर के लोगों को जोड़ सकती हैं। स्कूलों में कृष्ण और प्रकृति के संबंध पर कहानी सत्र आयोजित किए जा सकते हैं, ताकि पर्यावरणीय मूल्य अगली पीढ़ी तक पहुंचें। भारत और विदेश में ये विचार पहले से जड़ पकड़ रहे हैं। गुरुग्राम के मंदिरों में प्रसाद के लिए मिट्टी के कुल्हड़ और कागज के थैले इस्तेमाल होते हैं। कोलकाता में कारीगर प्राकृतिक रंगों से सजी मिट्टी की मूर्तियां बना रहे हैं, जबकि अहमदाबाद में दही हांडी में बायोडिग्रेडेबल मटके उपयोग होते हैं। अमरीका और ब्रिटेन में भक्त मिट्टी की मूर्तियां और ऑनलाइन भक्ति कार्यक्रम अपनाकर अपना पारिस्थितिकी बचा रहे हैं। कृष्ण भक्तों के लिए यह केवल पर्यावरणीय विकल्प नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनिवार्यता है। जन्माष्टमी के दौरान पर्यावरण-अनुकूल तरीके अपनाना, यह दिखाने का तरीका है कि आस्था और प्रकृति-रक्षा साथ-साथ चल सकते हैं। जन्माष्टमी को टिकाऊ तरीके से मनाना, भगवान कृष्ण को एक स्वच्छ, हरा-भरा वृंदावन भेंट करने जैसा है।

डॉ. पंकज जैन
लेखक फ्लेम यूनिवर्सिटी में इंडिया सेंटर के निदेशक हैं।
@patrika.com

बुक इनसाइट

कोलिम्स्की हाइट्स

कोलिम्स्की हाइट्स एक रोमांचक थ्रिलर उपन्यास है, जिसे लियोनल डेविडसन ने लिखा है। यह कहानी जेम्स बॉन्ड स्टाइल की एक इंटेलिजेंस मिशन जैसी है, जिसमें मुख्य पात्र एक युवा, होशियार और साहसी व्यक्ति है जॉनी पोर्टर। वह मूल रूप से अमरीकी है, जो भाषाओं का माहिर है और कठिन परिस्थितियों में खुद को ढालने की जबरदस्त क्षमता रखता है। उसे एक गुप्त वैज्ञानिक प्रयोगशाला में घुसने का मिशन मिलता है जो साइबेरिया के बर्फीले इलाके में स्थित है, जिसे कोलिम्स्की हाइट्स कहा जाता है। कहानी में आगे बढ़ते हुए जॉनी को पहचान छिपानी पड़ती है। कई रूप बदलने पड़ते हैं और रूस के खतरनाक बर्फीले जंगलों में जिंदा रहने के लिए अपनी हर कला का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें जासूसी, वैज्ञानिक रहस्य और रोमांच एक साथ चलते हैं।

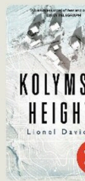

दृष्टिकोण

सोशल मीडिया: आभासी दुनिया का छलावा व अकेलापन

आपस में मिलना-जुलना ही मनुष्य होने की सच्ची पहचान है

आजकल किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाकर देखें तो एक बात सामान्य है। हर कोई अपने गैजेट्स में डूबा रहता है। कोई फोन पर, कोई आईफोन पर, कोई टैब पर तो कोई लैपटॉप पर। चाहे पार्क हो या होटल, पिकनिक हो या सामाजिक उत्सव। औपचारिक बातचीत के बाद सब अपने में डूब जाते हैं। वह सब देखकर ऐसा लगता है कि तकनीक ही सबकुछ हो गई है। आपस में गपियाना-बतियाना, बोलना-हंसना, यह सब बस औपचारिक से हो गए हैं। निभाने भर के लिए।

आपस में मिलना-जुलना मनुष्य होने की सच्ची पहचान है। मगर आजकल इस पहचान को अनदेखा किया जा रहा है। किसी की सच्ची मित्रता और सलाह अगर मिल जाए तो शायद यह एक सौभाग्य सा ही होगा। जब कोई अपना पास होगा तो आभासी दुनिया के लिए सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। तकनीक का गुलाम कौन बनना चाहेगा अगर हमारा कोई साथी हमारे आस-पास हो। जिसने सामाजिक आनंद का रसास्वादन किया है वह इस बात को जरूर महसूस कर सकता है कि आभासी दुनिया की चकाचौंध से बेहतरीन है किसी का साथ मिलना।

आभासी दुनिया तो पल भर का छलावा है। वहां किसी को किसी की क्या पड़ी है भला? इसकी परख के लिए किसी ऐसे आभासी मित्र को निजी संदेश भेजकर देख लीजिए कि- मित्र, मैं अचानक किसी अवसाद में हूं। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?' भले ही वह आपका दस साल से आभासी मित्र होगा, परंतु आपकी इस बात की तह तक जाना तो बहुत दूर की बात है, वह आपका संदेश तक नहीं देखना चाहेगा। कारण साफ है कि आभासी तो आभासी ही है। परदे के पीछे कौन है यह किसे पता? भिगोया-धोया और हो गया वाली मानसिकता में गले तक डूबे हुए आपको अतिरिक्त समय देने का भाव सपने में भी नहीं रखने वाले। उसका एक गंभीर कारण इस मंच की धोखाधड़ी, कपट तथा छल भी है। जब हम किसी के पास बैठकर एक साधारण सी गपशप भी करते हैं तो उसमें जुड़ाव महसूस करते हैं।

देखा जाए तो सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में यही कमी है। तकनीक की आभासी दुनिया से यह सुख और सुकून सुलभ होना संभव नहीं है। हमारे भीतर की रेत को सचमुच का जल यहां से मिलना मुश्किल है। तकनीक की दुनिया का आडंबरी लगाव आगे चलकर कुंठा दे रहा है। भरोसा न हो तो आंकड़े खुद टटोल कर देख लीजिए। पिछले दो दशक से आत्महत्या वाले मामलों में धन-दौलत, सुख-सुविधा सम्पन्न युवा और किशोर ही हैं। कोई कमी नहीं। सबकुछ है। मगर जो है सब मशीनी है। जिससे न आनंद मिल रहा है, न संतोष।

पिछले दिनों आई ग्लोबल स्टेट ऑफ सोशल कनेक्शंस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग चार में से तीन बालिग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इस सर्वे में 145 से अधिक देशों के लोगों को शामिल किया गया था। बड़ी संख्या में लोग अब यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास ऐसे वास्तविक दोस्तों की कमी है, जिनके साथ वे अपनी समस्याएं खुलकर साझा कर सकें। सर्वे में पाया गया कि 'एक साथी की अनुपस्थिति' भविष्य में एक गंभीर संकट बन सकता है, क्योंकि तकनीक के साथ अकेलापन मानव स्वास्थ्य के लिए उतना ही बुरा है, जितना कि एक दिन में दस सिगरेट पीना। शोध से यह भी पता चला है कि अपने समाज के साथ मिलने जुलने और बिताए जाने वाले समय में हर साल तेजी से कमी आ रही है। इस शोध के अनुसार भविष्य में भी इस हालत पर सुधार के कोई आसार नहीं दिखते। एक मनुष्य जब आभासी जगत को चाहने तथा सराहने लगता है तो हताशा, पागलपन और रोग जल्दी जकड़ लेते हैं। आखिरकार हम तकनीक के गुलाम क्यों बने रहना चाहते हैं?

पूनम पांडे
स्वतंत्र लेखिका
@patrika.com

ग्लोबल स्टेट ऑफ सोशल कनेक्शंस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में चार में से तीन बालिग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इस सर्वे में 145 से अधिक देशों के लोगों को शामिल किया गया था।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

भविष्यदृष्टि

कौशल, चरित्र और दृष्टिकोण निर्माण के लिए हो शिक्षा

बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी क्रांति और सामाजिक बदलाव- इन सभी के बीच एक भविष्यदृष्टि (फ्यूचरिस्टिक एप्रोच) अपनाना ही समय की मांग है। भविष्यदृष्टि का अर्थ केवल नए सपने देखना नहीं, बल्कि उन सपनों को साकार करने की ठोस तैयारी करना है। भविष्यदृष्टि अपनाने का अर्थ है कि शिक्षा केवल डिग्री देने वाली प्रक्रिया न होकर कौशल, चरित्र और दृष्टिकोण का निर्माण करे। शिक्षा संस्थानों को युवाओं में आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान क्षमता, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता की भावना विकसित करनी होगी।

नवाचार प्रयोगशालाएं, इन्क्यूबेशन सेंटर, ग्रीन स्टार्टअप कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप को कॉलेज जीवन का हिस्सा बनाया जाए, ताकि छात्र-छात्राएं केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि अवसर निर्माण करने वाले बनें। आज का युवाओं के पास वह ऊर्जा, रचनात्मकता और अनुकूलन क्षमता है जो आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। युवा शक्ति के साथ भविष्य न केवल उज्ज्वल है, बल्कि न्यायपूर्ण, टिकाऊ और प्रेरणादायी भी है। भारतीय युवाओं के पास यह अद्वितीय क्षमता है कि वे भारतीय ज्ञान परंपरा की जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक दुनिया में परिवर्तन और प्रगति के नेतृत्वकर्ता बनें। यही है भविष्यदृष्टि- जो भारत और विश्व, दोनों के लिए नई राह दिखा सकती है।

- **प्रो. हेमंत पारीक,** महासचिव, इंटरनेशनल सोसायटी फॉर लाइफ साइंसेज

ना पाली कोस्ट : दुनिया की खूबसूरत व फोटोजेनिक जगहों में से एक

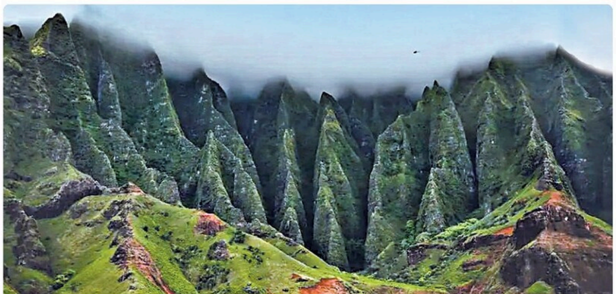

ना पाली कोस्ट, हवाई के काउई द्वीप के उत्तरी तट पर स्थित, दुनिया के सबसे खूबसूरत और फोटोजेनिक स्थलों में से एक है। इसकी खुरदरी और नुकीली चोटियां, गहरी घाटियां और हरियाली से ढकी पहाड़ियां इसे अद्भुत प्राकृतिक स्थल बनाती हैं। यह तटरेखा 4,000 फीट से भी अधिक ऊंची समुद्री चट्टानों से सजी हुई है, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची समुद्री चट्टानों में गिनती दिलाती हैं। यदि आप और करीब से प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं, तो ना पाली स्टेट वाइल्डरनेस पार्क के मार्ग या तटरेखा के नजदीकी हिस्से से भी तस्वीरें ली जा सकती हैं। हवा से उड़ान भरते समय या समुद्र की लहरों के बीच नाव पर खड़े होकर इस भव्य तटरेखा और समुद्री चट्टानों की विशालता और भव्यता को पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है।

फैक्ट फ्रंट

सी बटरफ्लाई: छोटा स्विमिंग स्नेल

सी बटरफ्लाई समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक छोटा-सा स्विमिंग स्नेल है। यह अपनी पंखों जैसी संरचना और पारदर्शी खोल के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे तितली की तरह दिखाता है। यह समुद्री जीव पूरी दुनिया के महासागरों में पाया जाता है, खासकर ठंडे पानी जैसे दक्षिणी महासागर में। हाल के शोधों से पता चला है कि यह नन्हा प्राणी जलवायु परिवर्तन से गंभीर खतरे में है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चिंता का विषय बन गया है। सी बटरफ्लाई का आकार बहुत छोटा होता है, कुछ मिलीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक और इसके पास पंखनुमा पैर होते हैं, जो इसे पानी में तैरने में मदद करते हैं।

छह महीने का रिपोर्ट कार्ड | टैरिफ नीति के फायदे कम, नुकसान का डर ज्यादा, ब्लू-कॉलर वर्ग का भरोसा डगमगाया

ट्रंप की अर्थव्यवस्था: वादों और हकीकत के बीच फंसे वोटर्स

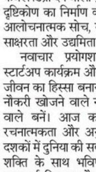

डेविड एम. ड्रकर
राजनीति और नीतियों पर लिखने वाले स्तंभकार
ब्लूमबर्ग
(वाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत)

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के बाद से लगभग हर दिन अर्थव्यवस्था का श्रेय लिया है। पिछले सप्ताह के अंत में, वाइट हाउस ने '200 डेज ऑफ विनिंग: राष्ट्रपति ट्रंप इज कीपिंग हिज प्रॉमिसेज' नामक प्रेस विज्ञप्ति में इसे शानदार सफलता करार दिया। फिर भी कई अमरीकी अब भी मामूली आर्थिक वृद्धि और रोजमर्रा की जरूरतों- किराने से लेकर मकान तक- को वहन करने में कठिनाई के बीच संघर्ष कर रहे हैं। यह एक अहम राजनीतिक सवाल खड़ा करता है कि ट्रंप जो अब छह महीने से अधिक समय से पद पर हैं, को मतदाता कब अपनी वित्तीय परेशानी के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे?

अगस्त की शुरुआत में 'द इकॉनॉमिस्ट' के लिए किए गए यूगव सर्वे में मतदाताओं का नंबर 1 मुद्दा मुद्रास्फीति/कीमतें था, जो 21% पर रहा और यह अगले अहम मुद्दे नौकरियां/अर्थव्यवस्था से 7 प्रतिशत अंक आगे था। इस सर्वे में ट्रंप की नौकरी अनुमोदन दर गिरकर 41% पर आ गई। अर्थव्यवस्था संभालने पर राष्ट्रपति की रेटिंग लगभग समान, 40% रही। ये खराब आंकड़े आंशिक रूप से स्वतंत्र मतदाताओं की नकारात्मक राय से प्रेरित हैं और डेमोक्रेटिक सर्वेक्षणों के हालिया डेटा से मेल खाते हैं।

'थर्ड वे' नामक मध्यमार्गी डेमोक्रेटिक थिंक टैंक के लिए जुलाई के अंत में किए गए सर्वे में ट्रंप की नौकरी अनुमोदन दर यूगव सर्वे से अधिक 45% पर रही। लेकिन 41% पंजीकृत मतदाताओं ने कहा कि राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल 'उम्मीद से बदतर' रहा है और केवल 42% ने उनकी प्रमुख आर्थिक योजना, 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट' को मंजूरी दी, जिसे 4 जुलाई को कानून में बदला गया था। इस सर्वे में स्वतंत्र मतदाताओं में इस एक्ट की स्वीकृति बेहद कम, केवल 32% रही।

इसके अलावा, शुरुआती गर्मियों के डेमोक्रेटिक सर्वे में 58% मतदाताओं ने अर्थव्यवस्था को 'ट्रंप की अर्थव्यवस्था' बताया, न कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को दोषी ठहराया। और अगर ये सर्वे सही हैं, तो ट्रंप के ब्लू-कॉलर समर्थकों का सब्र टूट रहा है। 'द वर्किंग क्लास प्रोजेक्ट' (एक डेमोक्रेटिक सुपर पीएसी द्वारा संचालित पहल) के 30 जुलाई के फोकस ग्रुप विश्लेषण में लिखा गया था- 'वसंत में, कई ब्लू-कॉलर मतदाता ट्रंप की टैरिफ योजना पर उन्हें लाभ देने को तैयार थे- लेकिन गर्मियों तक, कई लोगों ने गंभीर चिंता जताई कि टैरिफ उनके जीवन को महंगा बनाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं।' इन निष्कर्षों को मिलाकर देखा जाए तो संसदीय रिपब्लिकनों की स्थिति गंभीर है। और अगर ऐसी राय मतदाताओं में फैलती है, तो सिर्फ कैपिटल हिल के रिपब्लिकन ही नहीं, बल्कि 2028 में ट्रंप के उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में लगे रिपब्लिकन, खासकर उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस को भी भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

आखिरकार, राष्ट्रपति और उनकी पार्टी का भविष्य सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करेगा कि मतदाता अर्थव्यवस्था और उनकी नीतियों को कैसे देखते हैं, बल्कि इस पर भी कि राजनीतिक विकल्प क्या है। याद कीजिए, 2012 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के पुनर्निर्वाचन से ठीक पहले, बेरोजगारी दर 7.9% पर थी, जो पिछले महीने से एक अंक अधिक थी। यह बहुत से अमरीकियों के बेरोजगार होने का संकेत था- और 2024 के चुनाव दिवस से ठीक पहले की 4.1% दर का लगभग दोगुना। लेकिन रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी, जो पेशे से व्यवसायी और कॉर्पोरेट पुनर्गठन विशेषज्ञ थे, इन नकारात्मक आंकड़ों के बावजूद वाइट हाउस नहीं जीत सके।

अलंकार

प्रधानमंत्री ने आशंकाओं को बढ़ावा देते हुए भी आश्वासन दिया

पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12वीं वर्षगांठ लाल किले से दिया गया उनका स्वतंत्रता दिवस का संबोधन न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डालने के लिए, बल्कि देश के लिए सांप्रदायिक रूप से बहुपक्षीय जनसांख्यिकीय खतरे पर ज़ोर देने के लिए भी उल्लेखनीय था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा करते हुए, श्री मोदी ने यह कहते हुए संघ की बात दोहराई कि एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं।

देश की जनसांख्यिकी को बदलने की "जानबूझकर की गई साजिश" से निपटने के लिए एक उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन का शुभारंभ, विभिन्न समुदायों के बीच जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न दरों और पड़ोसी देशों से अवैध प्रवासियों के "घुसपैठ" की ओर इशारा करके देश को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत करने के एक छिपे हुए प्रयास से अधिक कुछ नहीं है। हालाँकि, भाषण में अर्थव्यवस्था, रक्षा और प्रौद्योगिकी, और युवा सशक्तीकरण सहित सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर काफी ध्यान केंद्रित करते हुए मूलभूत मुद्दों पर भी चर्चा की गई। श्री मोदी ने पिछले वर्ष भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विकासात्मक परिदृश्य में हुए विकास का भी लेखा-जोखा प्रस्तुत किया और आगे क्या होने की उम्मीद है, इसका पूर्वावलोकन किया।

श्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की, और कहा कि यह भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी हथियारों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। उन्होंने इस अवसर पर भारत के विरोधियों, खासकर पाकिस्तान, को चेतावनी भी दी और आतंकवाद व सीमा पार हमलों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर ज़ोर दिया। माओवादी विद्रोह के खिलाफ लड़ाई में मिली हालिया सफलताओं का भी ज़िक्र किया गया। श्री मोदी द्वारा घोषित एक योजना के अनुसार, मिशन सुदर्शन चक्र, एक पूर्णतः स्वदेशी रक्षा प्रणाली, 2035 तक विकसित और तैनात की जाएगी। विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे "एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली" बताया जो "न केवल दुश्मन के हमले को बेअसर करेगी, बल्कि दुश्मन पर कई गुना ज़्यादा वार भी करेगी"। वैश्विक शक्ति समीकरणों में तेज़ी से हो रहे बदलावों के बीच बोलते हुए, श्री मोदी का स्वतंत्रता दिवस संदेश संयुक्त राज्य अमेरिका पर भी लक्षित था, जिसने कई भारतीय उत्पादों पर 50% तक के टैरिफ़ की घोषणा की है। घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देने पर ध्यान केंद्रित करने का वादा करते हुए, श्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति अपनी जागरूकता दिखाई। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार दिवाली 2025 तक लागू कर दिए जाएँगे, जिससे प्रमुख वस्तुओं और सेवाओं पर कर का बोझ कम होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

एक ओर, श्री मोदी अपनी वैचारिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर, वे देश के सामने मौजूद भौतिक चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि, एक की सफलता दूसरे की कीमत पर ही मिल सकती है।

उग्रवाद की राजनीति, नक्सलवाद का पतन

एमके नारायणन

एक पूर्व निदेशक हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और एक पूर्व के राज्यपाल पश्चिम बंगाल

एक क्रॉस इतिहास, भविष्यवाणियाँ कर रहा है

यह एक खतरनाक काम रहा है। फिर भी सभी प्रकार के नेता भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं, जिनमें से कुछ ही सच साबित होती हैं। आज की दुनिया में, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अनिश्चितता को और बढ़ा रही है, भविष्यवाणियाँ करना और भी खतरनाक हो गया है। इतिहास के अधिकांश समय में, सबसे सुरक्षित भविष्यवाणी यही रही है कि चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसी वे हैं। राजनीतिक नेताओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

विरोधाभासों का एक मामला दुनिया भर में एक चिंता का विषय है कि 11 सितंबर, 2001 को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर हुए हमले के एक चौथाई सदी बाद भी आतंकवाद का खतरा कम होने या कम होने के बजाय अभी भी बरकरार है। 'नकलची हत्याओं' की कई घटनाएं अभी भी हो रही हैं। हाल ही में इस्लामिक स्टेट (आईएस) से प्रेरित वाहनों को टक्कर मारने की घटनाओं में भी तेजी आई है, सबसे चर्चित मामला इस साल 1 जनवरी को अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में हुआ था। न्यू ऑरलियन्स हमले से काफी पहले, आईएस ने पूरे यूरोप में इसी तरह के कई अन्य हमलों की योजना बनाई और उन्हें प्रेरित किया था। आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञों का मानना है कि जिहादी समूह कई देशों में अपने आतंकवादी हमलों को तेज करने लगे हैं। इस बीच, ऑनलाइन अभियान अधिक 'लोन वुल्फ' हमलों को उकसा रहे हैं। इसके साथ ही, दुनिया के कई हिस्सों में इजरायल विरोधी प्रदर्शनों ने आईएस और अल-कायदा प्रायोजित आतंकवादी अभियानों को और बढ़ावा दिया है।

प्रलय की भविष्यवाणियाँ कि कल आतंकवादी पहले से भी ज़्यादा ख़ूँख़ार अभियानों में शामिल होंगे। यह एआई के आगमन का नतीजा है। चेतावनियाँ यह हैं कि एआई-सक्षम आतंकवादी, आतंकवादियों के साथ मिलकर, 'जैविक हथियारों' तक पहुँच बना रहे हैं, जिससे हज़ारों लोग मारे जा सकते हैं। एक और भविष्यवाणी यह है कि गलत दिशा में ले जाई गई एआई सभी मानवीय नियंत्रणों से मुक्त होकर समाज और पूरी दुनिया को अकल्पनीय नुकसान पहुँचा सकती है।

हालाँकि, उपरोक्त परिदृश्य बहुत अलग है हाल ही में भारत में जो कुछ देखा जा रहा है, उसमें उग्रवाद, कम से कम विचारधारा-आधारित आतंकवाद, में गिरावट देखी जा रही है। यह सर्वमान्य धारणा है कि नक्सली या माओवादी हिंसा में वर्तमान गिरावट देश में वैचारिक आतंकवाद के अंत का संकेत है। आमतौर पर मौन रहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वयं संकेत दिया था कि नक्सलवाद का अंत निकट है, और 2026 के मध्य तक नक्सली हिंसा का अंतिम अवसान हो जाएगा। यदि ऐसा है, तो यह उस जीवंत, विचारधारा-आधारित, उग्रवादी आंदोलन का अंत होगा, जिसने अपने उत्कर्ष काल में युवाओं और बुद्धिजीवियों की कल्पना पर कब्ज़ा कर लिया था, और दार्शनिक फ्रांत्ज़ फैनन द्वारा 'धरती के अभागे' कहे जाने वाले लोगों, अर्थात् घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों और शहरों में रहने वाले 'शहरी गरीबों' को भी ऊर्जा प्रदान की थी। हालाँकि, अब तक कई 'झूठे सवेरे' देखे गए हैं (उदाहरण के लिए 1970 के दशक के अंत में और उसके बाद कम से कम दो बार, 1970 के दशक के अंत से पहले)।

कल के वैश्विक आतंकवादियों के बारे में प्रलय की भविष्यवाणियां भारत में हाल ही में देखी जा रही घटनाओं से बहुत भिन्न हैं - उग्रवाद या विचारधारा-उन्मुख आतंकवाद में गिरावट का दौर

20वीं सदी के अंत तक)। हालाँकि, नक्सली हिंसा का उन्मूलन आज तक सामाजिक रूप से कभी घोषित नहीं किया गया था।

क्रांतिकारी जोश बहुत जल्द ही गायब होता दिख रहा था। चारु मजूमदार, कानू सान्याल, सत्यनारायण सिंह और कोंडापल्ली सीतारमैया जैसे क्रांतिकारी नेताओं की प्रशंसा तो हो ही रही थी, लेकिन आंदोलन धीरे-धीरे अपनी चमक खोने लगा था और बेतुकी हिंसा में बदल रहा था—शुरुआत में शहरी इलाकों में, लेकिन उसके तुरंत बाद देश के अंदरूनी जंगलों में भी। एक बार एकीकृत क्रांतिकारी आंदोलन जल्द ही अलग-अलग क्षेत्रीय इकाइयों में बंट गया, हालाँकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) काफी समय तक आंदोलन की अग्रणी शक्ति बनी रही। अखिल भारतीय जोश का अभाव साफ़ दिखाई दे रहा था, और आंदोलन मध्य भारत के पहाड़ी और जंगली इलाकों, खासकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में केंद्रित हो गया।

1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में 'भारत पर वसंत ऋतु की गर्जना' के वादे ने, निस्संदेह, उस समय की पीढ़ी के कुछ सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित किया था, जो क्रांतिकारी जोश से भरे हुए थे (चीन और दक्षिण अमेरिका सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में हुई सफल क्रांतियों के बाद)। उस समय के नायक चीन के चेयरमैन माओ, वियतनाम के हो ची मिन्ह और दक्षिण अमेरिका के चे ग्वेरा जैसे क्रांतिकारी थे। जब बंगाल के चारु मजूमदार को 'नया मसीहा' कहा जा रहा था, तब भी नारा गूंज रहा था, 'चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है।' फिर भी, यह शुरुआती वादा अब धूमिल होने लगा है।

नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान 2024 में शुरू होगा और केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर विभिन्न राज्यों में उग्रवादी नक्सली समूहों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जाएगा। मुठभेड़ों में मारे गए नक्सलियों के आंकड़े अलग-अलग हैं, लेकिन आम तौर पर यह माना जाता है कि कुछ हज़ार नक्सली मारे गए थे। सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पुलिस प्रमुखों ने मारे गए या मारे गए नक्सलियों की संख्या के अपने-अपने आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। लेकिन शायद, इन आंकड़ों का सबसे प्रामाणिक आंकड़ा कभी प्रतिबंधित रहे सीपीआई (माओवादी) द्वारा जारी एक पुस्तिका में मिल सकता है, जिसमें स्वीकार किया गया है कि पिछले वर्ष ही देश भर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में 357 नक्सली मारे गए। इस रिपोर्ट के अनुसार, मारे गए लोगों में एक तिहाई से ज़्यादा महिला कैडर की थीं।

हिंसा का केंद्र दंडकारण्य क्षेत्र था, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और ओडिशा व आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में फैला हुआ था। एम. चंद्रशेखर राव के हटने के बाद से आंतरिक कलह और नेतृत्व संकट की एक श्रृंखला ने क्षेत्र के आकार को और कम कर दिया।

2018 में लक्ष्मण राव उर्फ गणपति।

सतही तौर पर, नक्सलवाद के खिलाफ युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के समान प्रतीत हो सकता है। ट्रम्प का 'आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध', उनके सत्ता में आने के तुरंत बाद शुरू हुआ। दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद संभाला। फिर भी, दोनों में स्पष्ट अंतर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का आक्रमण विचारधारा से प्रेरित उग्रवादियों या आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं, बल्कि उन तत्वों के विरुद्ध था जो 'महाशैतान' पर आक्रमण करने के अलावा किसी अन्य विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए, अमेरिका द्वारा किया गया आक्रमण भारत में अपनाए गए आक्रमण से बिल्कुल अलग था, जहाँ नक्सली रहते थे और ग्रामीणों व उनके जैसे लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। हाल तक, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, क्रूर बल प्रयोग को समाधान के रूप में नहीं देखा जाता था। तुलना करने के लिए, अमेरिका

सोमालिया और यमन में जिहादियों के खिलाफ राष्ट्रपति के हमले - इस तर्क पर आधारित कि जिहादी समूह अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे थे - इसलिए भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ अपनाई गई रणनीति के साथ तुलना करना एक गलती होगी।

भारतीय संदर्भ में घातक बल के प्रयोग पर कई नियंत्रण और संतुलन पहले भी थे और अब भी मौजूद हैं, यहां तक कि उन विरोधियों के खिलाफ भी जो हिंसा के माध्यम से स्थापित व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में विश्वास करते हैं।

नक्सलियों के खिलाफ अभियान और नक्सली हिंसा, मोटे तौर पर, कुछ निश्चित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही की गई है। क्रांतिकारी समूहों को, चाहे वे कितने भी उच्च विचार वाले क्यों न हों और उनकी जो भी शिकायतें हों, स्थापित व्यवस्था को भंग करने से रोकना, दिल्ली या राज्यों में सत्ता में रही किसी भी सरकार का/की निर्धारित उद्देश्य रहा है। बेशक, मूल नक्सलवादी क्रांतिकारी जोश से भरे हुए थे और एक अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध थे। हालाँकि, अपने उद्देश्य में असफल होने पर, उन्होंने जल्द ही अंधाधुंध हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। यह कहने के बाद, यह भी सच है कि अंधाधुंध हिंसा का सहारा लेने के बावजूद, अधिकांश समूहों ने विचारधारा का एक आवरण बनाए रखा।

एक नया शब्द: यह अंतर महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। वर्तमान में, 'शहरी नक्सली' शब्द के दुरुपयोग ने मूल नक्सली आंदोलन को एक विकृत रूप दे दिया है।

1960 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुए 'भारत पर वसंत गरज' की शुरुआत कुछ सिद्धांतों पर आधारित थी, हालाँकि ये सिद्धांत भले ही गलत दिशा में रहे हों। मार्क्सवादी-लेनिनवादी आंदोलन की भी एक सुस्पष्ट संरचना और एक सुदृढ़ दर्शन था।

आज के 'शहरी नक्सलियों' को कमतर नहीं आंकते हुए भी, कम से कम फिलहाल तो, ये बुद्धिजीवियों का एक ढीला-ढाला समूह ही प्रतीत होता है जो कई नीतिगत पहलुओं पर प्रशासन और सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करता है। आज के 'शहरी नक्सलियों' का मूल नक्सलियों से बहुत कम समानता है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

गलत वर्गीकरण के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं और लोगों भी। ऐसे मामलों से निपटने के लिए नीतियों की पहचान, समझ और क्रियान्वयन में असमर्थता, इनसे उत्पन्न जोखिम को और बढ़ा सकती है। उच्च अव्यक्त लागतों से बचने के लिए, संबंधित कारकों की बेहतर समझ आवश्यक है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या अदूरदर्शिता के कारण उत्पन्न होने वाले अंध बिंदुओं से बचना अत्यंत आवश्यक है।

एक प्रतिमान बदलाव

भारत को अपने व्यापार संबंधों और रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है

11 अगस्त को केंद्र सरकार ने... लगभग 28 मिलियन लोगों को आजीविका प्रदान करता है- 7 अगस्त से लागू हुए अमेरिका के 25% के टैरिफ का "साहसपूर्वक सामना" करने के लिए, जिसे व्यापार वार्ता के परिणाम के आधार पर 27 अगस्त को 50% तक बढ़ाया जा सकता है, सरकार को उम्मीद है कि सरकार निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) में " बदलाव" करने पर विचार कर रही है। इसकी घोषणा 2025 के केंद्रीय बजट में की गई थी और इसके लिए चालू वित्त वर्ष के लिए ₹2,250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। EPM, सस्ते निर्यात ऋण तक पहुँच बढ़ाने, गैर-व्यापार बाधाओं को दूर करने और विदेशी खरीदारों से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-मंत्रालयी परियोजना है, जो भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) पर केंद्रित है।

शुरुआत में वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों द्वारा संचालित इस योजना पर अब कपड़ा और मत्स्य पालन मंत्रालयों को भी शामिल करने पर विचार-विमर्श चल रहा है। ये दोनों उद्योग, जो सामूहिक रूप से लगभग 13.5 करोड़ भारतीयों को रोजगार देते हैं, एमएसएमई के सबसे बड़े क्षेत्र में से एक हैं, जिन पर प्रतिबंधों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत के परिधान और समुद्री खाद्य निर्यात में अमेरिका का योगदान आम तौर पर लगभग एक-तिहाई होता है।

अन्य बाज़ारों में भी विविधता लाने की सरकार की अपील इस बात की मौन स्वीकृति है कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत गतिरोध में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत समीकरण किसी भी पक्ष के लिए जीत में तब्दील नहीं हुए हैं। द्विपक्षीय संबंध शीत युद्ध के दौरान के स्तर से भी निचले स्तर पर पहुँच गए हैं, क्योंकि दोनों देश आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य रूप से उतने एक-दूसरे से जुड़े नहीं थे जितने अब हैं। व्यापार और सेवा मार्ग और आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनने में दशकों लगते हैं और उन्हें रातोंरात ख़त्म करना संभव नहीं है। यह यूरोपीय संघ की रूसी तेल पर निर्भरता और चीन से दुर्लभ मृदा तत्वों पर वैश्विक निर्भरता से स्पष्ट है। अप्रैल में श्री ट्रम्प द्वारा "पारस्परिक शुल्क" की घोषणा के बाद से सरकार और एमएसएमई क्षेत्र के हितधारकों के बीच परामर्श चल रहा है, अब अर्थव्यवस्था की रीढ़ की रक्षा के लिए कठोर सरकारी हस्तक्षेप की मांग हो रही है - यह माल निर्यात में लगभग आधे (वित्त वर्ष 2025 में 45.79%) का योगदान देता है और 28 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। शेरी क्षेत्र ने प्री- और पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट पुनर्भुगतान पर 240-दिवसीय स्थगन की मांग की है, जबकि कपड़ा-टाइल्स, परिधान और रत्न और आभूषण क्षेत्र ब्याज अनुदान चाहते हैं। हालाँकि, सरकार ने प्रत्यक्ष सब्सिडी से इनकार किया है। लेकिन अभूतपूर्व चुनौतियों के लिए नए जवाबों की आवश्यकता होती है। सरकार को अपने शस्त्रागार में पड़ोसियों, विशेष रूप से चीन के साथ निकट भविष्य के व्यापार संबंधों में भारी बदलाव को शामिल करना चाहिए,

ब्रिटेन व्यापार समझौते में संहिता और वाणिज्य का संतुलन

सैयद अकबरुद्दीन

एक पूर्व भारतीय हैं स्थायी संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि और वर्तमान में डीन,

कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, हैदराबाद

शिवांगी पांडे

डीन, कौटिल्य के कार्यकारी सहायक हैं पब्लिक स्कूल नीति, हैदराबाद

मैं भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ डिजिटल व्यापार समझौता किंगडम ने नई ज़मीन तोड़ी। भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) एक ऐसा समझौता है जो पहुँच, विश्वसनीयता और पैमाने के लिए कुछ निगरानी उपकरणों का व्यापार करता है। इस व्यापार-समझौते ने एक नीतिगत बहस छेड़ दी है। समर्थक इसे वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक कदम बता रहे हैं। आलोचक इसे डिजिटल संप्रभुता से पीछे हटना कह रहे हैं। ऐसे समझौतों से शायद ही कभी ऐसा नतीजा निकलता है जिसमें विजेता को सब कुछ मिल जाता है। ये आमतौर पर बातचीत के ज़रिए समझौते पर पहुँचते हैं। कुल मिलाकर, लाभ वास्तविक लगते हैं, लेकिन ये ऐसे सुरक्षा उपायों की ज़रूरत का संकेत देते हैं जो उभरते जोखिमों के साथ तालमेल बिठा सकें।

डिजिटल जीत डिजिटल जीत स्पष्ट है। यह समझौता इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों और अनुबंधों को मान्यता देता है और दोनों पक्षों को पारस्परिक मान्यता की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। इससे सॉफ्टवेयर-एज़-ए-सर्विस फर्मों के लिए कागजी कार्रवाई कम हो जाती है और छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए बाधाएँ भी कम हो जाती हैं।

कागज़ रहित व्यापार और इलेक्ट्रॉनिक चालान-प्रक्रिया सीमा पार दस्तावेज़ीकरण और भुगतान को आसान बनाती है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के लिए शून्य सीमा शुल्क की नीतिगत निरंतरता, सॉफ़्टवेयर निर्यात पाइपलाइन की रक्षा करती है, जिसका वाणिज्य मंत्रालय अनुमान लगाता है कि यह सालाना 30 अरब डॉलर का है।

डेटा नवाचार पर सहयोग भी सहायक हो सकता है। पाठ पायलट परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है जो आवश्यकतानुसार नियामक सैंडबॉक्स का उपयोग करती हैं। इससे भुगतान और अन्य डेटा-संचालित फर्मों को पर्यवेक्षण के तहत उपकरणों का परीक्षण और स्केल करने का एक तरीका मिलता है, जिससे विदेशों में विश्वसनीयता बढ़ती है। डिजिटल अध्याय से परे, व्यापक भारत-यूके समझौते से दिन-प्रतिदिन के व्यापार में सुधार की उम्मीद है। उद्योग को उम्मीद है कि जैसे ही यह समझौता लागू होगा, लगभग 99% भारतीय व्यापारिक निर्यात यूके में शुल्क-मुक्त हो सकेगा, जबकि कपड़ा शुल्क में भारी गिरावट आएगी, जिसमें प्रमुख लाइनों पर 12% से शून्य तक की गिरावट शामिल है, जिससे तिरुपुर (तमिलनाडु) और जैसे कपड़ा निर्यात केंद्रों में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी।

लाभ वास्तविक दिखते हैं, लेकिन सुरक्षा उपायों की आवश्यकता का भी संकेत देते हैं

लुधियाना (पंजाब)। विश्लेषकों का मानना है कि ब्रिटिश सार्वजनिक खरीद में भारतीय आईटी आपूर्तिकर्ताओं के लिए और भी नए रास्ते खुल रहे हैं। नियोक्ताओं का कहना है कि छोटे-मोटे कामों के लिए सामाजिक सुरक्षा में छूट से वेतन-भत्तों में लगभग पाँचवाँ हिस्सा कमी आ सकती है। इन कदमों से एक व्यापक और अधिक विश्वसनीय व्यापार गलियारे का वादा किया गया है।

डिजिटल लागतें फिर भी, संभावित डिजिटल लागतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आलोचकों का तर्क है कि भारत ने डिफ़ॉल्ट नियामक उपकरण के रूप में स्रोत-कोड जाँच से हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि समझौते के तहत कोड-निरीक्षण पर प्रतिबंध है। नियामक मामले-दर-मामला आधार पर, जाँच या अदालती प्रक्रिया से जुड़े आधार पर पहुँच की माँग कर सकते हैं।

सरकारी खरीद को डिजिटल व्यापार के दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए सरकार द्वारा खरीदे गए उत्पादों के सोर्स कोड तक किसी भी तरह की पहुँच प्रतिबंधित नहीं है। हालाँकि इस समझौते का उद्देश्य व्यावसायिक विश्वास बढ़ाना है, लेकिन यह आवश्यक हितों का त्याग नहीं करता। एक सामान्य सुरक्षा अपवाद मौजूद है। यह पावर ग्रिड, भुगतान प्रणालियों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर राष्ट्रीय निगरानी बनाए रखता है, भले ही वे निजी स्वामित्व वाले हों। यह प्रतिबंध केवल सुशासन का है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी कार्रवाई इस तरह से न की जाए जिससे व्यापार पर एक अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगे। यदि अतिरिक्त आश्वासन की आवश्यकता हो, तो एक व्यावहारिक कदम यह हो सकता है कि विश्वसनीय प्रयोगशालाओं को कड़े सुरक्षा उपायों के तहत संवेदनशील कोड की समीक्षा के लिए मान्यता दी जाए।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह रुख स्वैच्छिक है। कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं है। भारत तय करता है कि क्या प्रकाशित करना है और किस रूप में। जब वह डेटासेट खोलता है, तो वह मशीन द्वारा पठनीय और पुन: उपयोग में आसान होना चाहिए। यह कोई खाली चेक नहीं है जिससे कोई भी पहुँच की मांग कर सके। भारत सीमा पार डेटा मध्यस्थों के लिए स्पष्ट ऑडिट ट्रेल्स की भी मांग कर सकता है ताकि डेटा के साथ जवाबदेही बनी रहे।

सीमा पार डेटा प्रवाह के लिए कोई "स्वचालित MFN (सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र)" नहीं है। इसके बजाय, समझौता एक अग्रिम समीक्षा तंत्र बनाता है। अगर बाद में कोई पक्ष कड़े डेटा नियमों वाले व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करता है, तो दोनों पक्ष समान शर्तों को बढ़ाने पर विचार-विमर्श करते हैं। बातचीत का वादा होता है, कोई स्वचालित विस्तार नहीं।

पांच वर्षों के भीतर औपचारिक समीक्षा निर्धारित की गई है। चूंकि तीन वर्षों से कम समय में चैटजीपीटी के कई संस्करण सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि एआई तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए भविष्य में होने वाले समझौतों की समीक्षा हर तीन साल में होनी चाहिए ताकि नियमों को जोखिमों के साथ संरेखित किया जा सके।

आधुनिक व्यापार मानदंडों के साथ तालमेल बिठाना भारत की पिछली प्रथाओं से एक बदलाव है, लेकिन वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका चाहने वाले देश के लिए यह उचित भी है। यह भारत के व्यापार संशयवाद से रणनीतिक जुड़ाव की ओर बदलाव को दर्शाता है।

घरेलू नींव आमतौर पर बाहरी नींव को सहारा देती है प्रतिबद्धताएँ। 2023 के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम को अभी भी अंतिम नियमों की अधिसूचना की आवश्यकता है। भविष्य के व्यापार पाठों के लिए उस पर आधारित ढांचे के अनुसार, नियमों में सौदे बंद होने से पहले खुले परामर्श को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है, ताकि इनपुट मांगे जा सकें और चिंताएं पहले ही सामने आ सकें तथा उनका समय पर समाधान किया जा सके।

उठाए जाने वाले कदम: डिजिटल संधियाँ तय करती हैं कि सरकारें क्या विनियमित कर सकती हैं, कंपनियाँ क्या अपेक्षा कर सकती हैं और नागरिक क्या सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। भारत-ब्रिटेन समझौते का अध्याय 12, पहले कदम के रूप में एक मील का पत्थर है।

भविष्य में, भारत को बाज़ार के खुलेपन को नियामक निगरानी के साथ एकीकृत करना चाहिए। यह विश्वसनीय प्रयोगशालाओं को सख्त सुरक्षा उपायों के तहत संवेदनशील कोड की समीक्षा करने के लिए मान्यता दे सकता है और सीमा पार डेटा प्रवाह के लिए ऑडिट ट्रेल्स को भी अनिवार्य बना सकता है। यह व्यापक-आधारित पूर्व-वार्ता परामर्शों को संस्थागत रूप दे सकता है और डिजिटल संधियों की नियमित तीन-वर्षीय समीक्षा निर्धारित कर सकता है। ये सभी कदम दर्शाते हैं कि संप्रभुता और वैश्विक जुड़ाव को विपरीत दिशाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि, इसके बजाय, वे आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान कर सकते हैं।

संपादक के नाम चिठी

आवारा कुत्तों पर नियंत्रण एक पशु अधिकार कार्यकर्ता द्वारा दिया गया बयान कि रेबीज एक ' हल्की बीमारी' है, अपमानजनक है।

रेबीज़ एक जानलेवा वायरस है जिससे मृत्यु दर 100% है। ऐसा बयान एक बेहद लापरवाह रवैये को दर्शाता है, जो काम करने वाले लोगों के लिए आक्रामक गली के कुत्तों से होने वाले खतरे को नज़रअंदाज़ करता है। वे लोग जो अभिजात वर्ग की तरह अपने घरों में खुद को बंद नहीं रख सकते।

हालाँकि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश कि दिल्ली में सभी कुत्तों को आठ हफ़्तों के भीतर पकड़ लिया जाना चाहिए, अव्यावहारिक और अमानवीय है। कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने का वैज्ञानिक तरीका पशु चिकित्सा अधिनियम को लागू करना है। जन्म नियंत्रण नियम। नगर निगम को कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए कल्याणकारी संगठनों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। जन स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में रेबीज और टिटनेस के टीके उपलब्ध हों। उसे एक अभियान भी चलाना चाहिए।

जागरूकता अभियान जो दोनों इंजेक्शन कुत्ते के काटने के 24 घंटे के भीतर दिए जाने चाहिए।

आरती सेठी, नई दिल्ली

घर-घर राशन वितरण

मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब दो महिलाएं जो आमतौर पर राशन की वस्तुओं की बिक्री का काम संभालती हैं,

मेरी सरकारी दुकान एरिया से मुझे फ़ोन आया और बताया कि वे मेरे गेट पर हैं। वे महिला सहकारी स्टोर से थे।

सब कुछ सुचारू रूप से चला, लेकिन महिलाएँ थकी हुई दिख रही थीं और खराब वाई-फाई कनेक्टिविटी से जूझ रही थीं। अगर वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ उठाना है, तो इसे कहा जाता है

' थायुमनवर' 'थित्तम' योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है और उनके पास अपने कार्ड और कंटेनर तैयार होने चाहिए। इस कदम से सरकारी कर्मचारियों के लिए राशन की मोबाइल डिलीवरी बहुत आसान हो जाएगी।

मिनी कृष्णन, चेन्नई

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स | मुंबई | शनिवार, 16 अगस्त 2025

चुनौती नई, संकल्प वही

पीएम मोदी ने दुनिया को दिया स्पष्ट संदेश

आजादी की 79वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से दिया गया भाषण अगर याद रखे जाने लायक कहा जाएगा तो सिर्फ इसलिए नहीं कि यह उनका अब तक का सबसे लंबा भाषण रहा या लाल किले के प्राचीर से उन्होंने लगातार बारहवीं बार राष्ट्र को संबोधित किया, जिसका मौका पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा किसी और प्रधानमंत्री को नहीं मिला। जिन हालात में और जिन चुनौतियों के बीच पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, वे भी इस भाषण को अहम बना रहे थे।

जीएसटी रिफॉर्म्स होंगे

मेक इन इंडिया पर जोर । आज अमेरिका टैरिफ वॉर के जरिये अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को हथियार बनाया हुआ है। इन सबके बीच भारत को तरक्की जारी रखने के लिए रास्ता तलाशना ही होगा। स्वाभाविक ही प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पर खासा जोर दिया। दुनिया जिस तरह से बदल रही है, उसमें यह जरूरी भी है कि दूसरों पर निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जाए।

लक्ष्य पाना संभव । अभी देश की GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान केवल 12% है और ग्लोबल सप्लाई में केवल 2.8%। इसकी तुलना में चीन दुनिया के लिए 28.8% सामान बना रहा है। इस साल अप्रैल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार अगले दो दशकों में मैन्युफैक्चरिंग को GDP के 23% के बराबर करना चाहती है। सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है, वह नामुमकिन बिल्कुल नहीं है।

गुणवत्ता की कद्र । ऑटो इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, खासतौर पर आईफोन का उदाहरण बताता है कि भारत में वैश्विक जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है। एपल करीब 20% आईफोन अब भारत में बना रही है, जबकि कभी चीन इसका केंद्र हुआ करता था।

चुनौतियों पर नजर । अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए पीएम मोदी चुनौतियों की ओर संकेत करना भी नहीं भूले। उन्होंने न केवल किसानों, और मछुआरों की बात की बल्कि सिंधु जल समझौते को मौजूदा स्वरूप में स्वीकार न करने की दो टूक घोषणा भी कर दी। स्पष्ट है कि भारत किसी भी सूरत में अवांछित दबाव को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन इसे लेकर भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि भारत की आत्मनिर्भरता का मतलब बाकी दुनिया से कटना नहीं है। परस्पर सम्मान और सहयोग के आधार पर आगे बढ़ते हुए ही भारत अपनी मंजिल तय करेगा।

अंतर्दृष्टि

तेज भागने के चक्कर में भूल गए कि जाना कहां!

सुंदर चंद ठाकुर

हम सब तेज भाग रहे हैं। किसी को कुछ हासिल करना है, किसी को कुछ साबित करना है, किसी को किसी से आगे निकलना है। सुबह आंख खुलते ही दौड़ शुरू हो जाती है - काम की, समय की, सफलता की, नाम की। पर कभी सोचा है कि ये रेस किसके लिए है? और किस दिशा में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि रास्ता ही भूल गए हैं? या शायद मंजिल ही बदल गई है, पर हम रुके नहीं, जांचने नहीं गए। बस उसी रफ्तार से भागे जा रहे हैं, जैसे बस दौड़ते रहना ही जीवन हो। आज की दुनिया में हर चीज फास्ट हो गई है - फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट डिलीवरी, फास्ट रिजल्ट। धीरे चलने का मतलब है पीछे छूट जाना। ठहरने का मतलब है असफलता। और इस डर में, हम दौड़ते चले जा रहे हैं। पर भीतर कहीं कुछ चुपचाप टूटता जा रहा है।

दौड़ में सबसे पहले जो खोता है, वह है शांति। फिर आता है ध्यान। फिर रिश्ते। और धीरे-धीरे हम खुद को ही खो देते हैं। हम जो बनना चाहते थे, वह छवि पीछे छूट जाती है। हम जिस इंसान को बचाकर रखना चाहते थे वो मासूम, वो संवेदनशील, वो सोचने-समझने वाला इंसान - वह इस तेज रफ्तार में कहीं धुंधला पड़ जाता है। हम सुबह जागते हैं, मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं। हर कोई कुछ कर रहा है - किसी ने कोई बड़ी डील क्लोज की है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई नया बिजनेस लॉन्च कर रहा है और हम बेचैन हो जाते हैं। लगता है हमें भी दौड़ना है। कहीं पीछे न रह जाएं।

लेकिन रुककर पूछने वाला कोई नहीं बचा कि क्या जिस रास्ते पर हम भाग रहे हैं, वह वाकई हमारे लिए है? कभी-कभी सबसे बहादुरी भरा कदम होता है रुक जाना। अपनी रफ्तार को धीमा करना। भीतर की आवाज सुनना। खुद से पूछना - 'क्या मैं खुश हूं?' क्योंकि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। यह एक यात्रा है। और अगर इस यात्रा में आप सिर्फ भागते रहे और नजारे ही नहीं देखे, तो अंत में बस थकान बचेगी, अनुभव नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि हम रफ्तार को सफलता से न जोड़ें। हमें रुककर सोचने की जरूरत है - क्या हम जी रहे हैं या बस दौड़ रहे हैं?

इस बात को समझ लीजिए कि भागने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आखिरी में जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, वह तो एक धीमी नदी है, जो भीतर बहती है। जो जितना शांत होता है, वह उतना गहरा उतरता है। जो जितना धीरे चलता है, वह उतना अधिक देखता है। और जो खुद को पूरे होश में जितना देखने लगे, वही सचमुच और उतना ही जिंदा होता है।

ऑफ़ दि ट्रैक

मन की आवाज़

दिलीप लाल

वर्षों से न्यूरोइंजीनियर उन लोगों की मदद का सपना देख रहे हैं, जो बीमारी या चोट के कारण बोलने में असमर्थ हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का विचार है कि मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगाकर उसके विद्युत संकेत रिकॉर्ड किए जाएं और उन्हें शब्दों में बदला जाए, तो आवाज वापस लाई जा सकती है। हाल ही में Cell पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने इस दिशा में नई प्रगति की है। पहले शोधकर्ता केवल वे शब्द डिकोड कर पाते थे, जिन्हें रोगी बोलने की कोशिश करता था। अब उन्होंने inner speech यानी व्यक्ति के मन में आने वाले शब्द भी सफलतापूर्वक डिकोड किए हैं। यह उपलब्धि BrainGate2 क्लीनिकल ट्रायल का हिस्सा है। इसमें कंप्यूटर ने रिकॉर्डिंग और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदद से लगभग 6,000 शब्द 97.5% सटीकता से पहचाने और उन्हें रोगी की पुरानी आवाज में बदल दिया। शोधकर्ताओं ने अपनी जांच में पाया कि केवल वाक्य की कल्पना करना वास्तविक बोलने से कम थकाने वाला होता है, जिससे मरीज इस प्रणाली का अधिक समय तक उपयोग कर सकते हैं। यह रिसर्च भाषा और विचार के रहस्यों को समझने की दिशा में एक अहम कदम है। शायद अब मन की आवाज भी सुनी जा सकेगी।

देश की लड़कियां शिक्षा में लड़कों से आगे हैं और नौकरी में पीछे

बेटी पढ़ी, फिर कहां गई

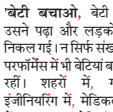

मनीष गुप्ता, न्यूयॉर्क से

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। उसने पढ़ा और लड़कों से आगे निकल गई। न सिर्फ संख्या, बल्कि परफॉर्मेंस में भी बेटियां बाजी मारती रहीं। शहरों में, गांवों में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल कॉलेज में - हर जगह बेटियां छाई रहीं। 'बेटियां फिर से अव्वल' - कई बरसों से ये सुर्खियां हम गर्व से पढ़ते आ रहे हैं। भारत जैसे देश में, जहां परंपरागत रूप से लड़कों को प्राथमिकता दी जाती थी, लड़कियों का आगे निकल जाना एक ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन उनका चमकना धूमकेतु की तरह है। वह चमकती हैं, फिर दिखती नहीं। न बोर्डरूम में, न ऑफिसों में और न उस GDP में, जिसे तरक्की का पैमाना कहा जाता है।

काम के कम मौके । नारियों की भागीदारी U-shaped curve है। कम पढ़ी-लिखी महिलाएं काम करती हैं। जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ती है, नौकरी में भागीदारी गिरती जाती है। और सिर्फ कुछ ही 'एलीट' महिलाएं उस वक्र के ऊपरी छोर तक वापस पहुंच पाती हैं। कारण है - शादी, मातृत्व, समाज की चुप अपेक्षाएं। यह कोई संयोग नहीं, यह हमारी संस्कृति है।

वापसी का अवसर नहीं । लड़कियों की शिक्षा को 'शादी के बाजार' में उनकी 'क्वॉलिटी' बढ़ाने का जरिया मान लिया गया। नौकरी शौक के लिए एक-दो साल कर लो, फिर आराम से घर संभालो! करियर, स्वतंत्रता, अपनी कमाई से जिंदगी जीने का सपना - इन सबको अक्सर 'संस्कारहीनता' का नाम दे दिया जाता है। बहुत-सी शिक्षित महिलाएं खुद भी इसे अपनी नियति मान चुकी हैं।

इंडियन पैराडॉक्स । इस विरोधाभास को विकास विशेषज्ञ 'इंडियन पैराडॉक्स' कहते हैं। एक ओर तो लड़कियां शिक्षा में लड़कों से आगे निकल रही हैं, दूसरी ओर नौकरी की दुनिया में उनकी कम भागीदारी चिंता का विषय है। इसे 'feminization of education, masculinization of work' कहा जाता है।

लगातार गिरावट । विश्वविद्यालयों में महिलाओं की भागीदारी 50% के करीब है, लेकिन औपचारिक रूप से काम करने वाली महिलाओं की संख्या केवल 22% है। चीन में यह आंकड़ा 60% है, अमेरिका में 56% और केन्या में 47%। हमसे आगे तो सऊदी अरब (28%) और बांग्लादेश (36.9%) भी हैं। हैरत की बात है कि 2005 में कामकाजी महिलाओं की संख्या 32% थी और लगातार गिरावट के बाद 2021 में यह 19% रही। यानी शिक्षा बढ़ी, नौकरी कम हुई।

लंबा संघर्ष । लड़कियों को शिक्षा का अधिकार बहुत संघर्ष के बाद मिला है। 1848 में, जब लड़कियों को पढ़ाना गुनाह समझा जाता था, ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने पुणे में पहला कन्या विद्यालय खोला। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नारी शिक्षा की वकालत की। आजादी के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, 'आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं।' उनके कार्यकाल में UGC और Wome's Education Committee बनी।

योजनाएं और कानून । 1968 की पहली शिक्षा नीति ने लैंगिक बराबरी को स्पष्ट लक्ष्य बनाया। 1986 नीति में महिलाओं की व्यावसायिक ट्रेनिंग, साक्षरता को प्राथमिकता दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सर्व शिक्षा अभियान (2001) ने शिक्षा को जन आंदोलन बनाया। मनमोहन सिंह सरकार के समय में RTE Act, कस्तूरबा बालिका विद्यालय और NSIGSE जैसी योजनाओं से स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में गिरावट आई। फिर मोदी सरकार ने 2015 में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया जो आज तक हर जुबान पर है। इतने वर्षों की मेहनत, इतने कानून, योजनाएं और सुधार, इसलिए सवाल और भी तीखा हो जाता है कि बेटियां वर्कफोर्स से गायब क्यों हो रही हैं?

अर्थव्यवस्था का नुकसान । बेटियों के लिए रास्ता न होना राष्ट्रीय संपत्ति का भी नुकसान है। विश्व बैंक कहता है, अगर हम महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 10% बढ़ा दें, तो भारत की GDP 16% तक बढ़ सकती है। McKinsey का अनुमान है कि भारत 770 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में जोड़ सकता है अगर महिला-पुरुष बराबरी हो। हम यह सुनते ही रहते हैं कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनने वाला है। लेकिन क्या कोई महाशक्ति आधी आबादी को घरों में बंद रखकर बनती है?

सबका हित । अब हमें सिर्फ 'बेटी पढ़ाओ' नहीं, 'बेटी को जीने दो, कमाने दो, सपने देखने दो' कहना होगा। और यह काम सिर्फ सरकार का नहीं है - कॉरपोरेट, पंचायत, समाज और खुद महिलाओं को अपनी भागीदारी को प्राथमिकता देनी होगी। जब हम लड़कियों को पढ़ाने में इतना निवेश करते हैं, तो उन्हें ऊंचाई छूने का हक भी दें। यह महिला, पुरुष, परिवार, समाज और देश - सभी के हित में होगा।

(लेखक फिल्मकार, कॉलमनिस्ट और राइटर हैं)

www.nbt.in

यूरोप में कुत्तों की ज़िंदगी

कुत्तों को लेकर इन दिनों मामला गर्म है। पिछले साल जब मैं जर्मनी, इटली और बेल्जियम गया तो वहां कुत्तों का अनुशासन देखकर अचरज में पड़ गया। वहां बुलेट ट्रेन में मेरे साथ वाली सीट पर एक वृद्ध महिला थीं, साथ में एक छोटा सा कुत्ता भी। सफेद रंग के सुंदर से कुत्ते के गले में लाल रिबन चमक रहा था। आशंका हुई कि शायद वह अनजान व्यक्ति को देखकर भौंके या लपके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगभग तीन घंटे के सफर में जिस जगह उसे बिठाया गया, वहां से उठकर इधर उधर भी नहीं गया।

मैनें नोटिस किया कि वह कुत्ता मानों पूरी ट्रेनिंग लेकर आया हो कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। यही बात मैंने जर्मनी के फ्रेंकफर्ट और बर्लिन में भी नोटिस की। लगभग 15 दिन वहां रहने के दौरान मुझे सड़क पर कोई आवारा कुत्ता घूमता नहीं दिखा। सड़क पर जो भी कुत्ता दिखा, वह अपने मालिक के साथ ही था और मालिक की तरह ही बिलकुल साफ। कहीं कोई गंदगी नहीं। ज्यादातर मालिक, जिनमें महिलाएं भी थीं, कुत्तों को अपनी साइकल की आगे लगी टोकरी में बिठाते/बिठातीं या फिर साइकल के पिछले कैरियर में बंधी कुर्सी पर। लेकिन मजाल है कि कुत्ता वहां से हिले-डुले। इसी तरह जब पैदल चल रहे मालिक के साथ कुत्ता होता, तो भी पूरी तरह अनुशासित।

हालत यह थी कि इन देशों में सफर के दौरान मुझे कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज तक सुनाई नहीं दी।

खुद अपनी आंख से

गुलशन राय खत्री

मानों, इन देशों के कुत्ते गूंगे हों। हां जब इटली में पीसा की मीनार के समीप हम लोग सुस्ता रहे थे, तब अचानक कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी तो चौंक कर देखा। वहां दो पिल्ले एक दूसरे से भिड़ने की तैयारी में थे कि उनके मालिकों ने खुद ही उन्हें डांटा और अपनी ओर आने का इशारा किया। वहां भी गजब का अनुशासन। चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह अपने मालिक के पांव के पास आकर बैठ गए।

कुत्तों के इस अनुशासन के बारे में जब वहां लोगों से बात की तो पता चला कि वहां आवारा कुत्ते तो सड़क पर घूमते ही नहीं। जो कुत्ते हैं, वे पालतू हैं और लोग अगर कुत्ते को पालना चाहते हैं तो उन्हें न सिर्फ बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है बल्कि कई कड़े नियमों का पालन भी करना पड़ता है। कुत्ते को ट्रेनिंग देने से लेकर उसे रखने के तौर-तरीके, खाने आदि के नियम पालन के बारे में एक तरह का हलफनामा देना पड़ता है। यही नहीं, अगर कुत्ता कोई ऐसी हरकत करता है, जिससे किसी दूसरे को दिक्कत होती है तो उसके लिए भी मालिक को भारी भरकम हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। अगर कुत्ते ने काट लिया तो फिर तो कुत्ता रखने वाले के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। अपने यहां लोग कुत्तों को सड़क पर इसलिए घुमाते हैं कि वे बाहर ही शौच करें। लेकिन यूरोप में अगर सड़क पर कुत्ता शौच करवाने में मालिक खुद उसे वहां साफ करता नजर आ जाता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

5 पॉइंट

यह चाल तो फेल होगी

तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई-टेक प्रॉडक्ट के लिए जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स की 90% सप्लाई चीन से होती है। इसी एकाधिकार की बदौलत उसने ट्रेड डील में US को झुका दिया। लेकिन, लंबे वक्त में यह लड़ाई चीन के लिए घाटे का सौदा बन सकती है।

1 रेयर नहीं
रेयर अर्थ मिनरल्स इतने भी रेयर नहीं। ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस समेत कई देशों के पास इसका बड़ा भंडार है। चीनी मनमानी बढ़ने पर ये देश अपने यहां उत्पादन शुरू कर सकते हैं, प्रयास भी हो रहे हैं।

2 सरल तकनीक
रेयर अर्थ मिनरल्स की रिफाइनिंग चिप मेकिंग जैसी कठिन नहीं है। बाकी देश प्रॉडक्शन में पीछे है, क्योंकि इसके लिए सस्ता श्रम चाहिए और इसमें पलूशन बहुत होता है। US ने इसी वजह से प्रॉडक्शन रोका था।

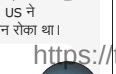

3 विकल्प की तलाश
BMW और Renault ने ऐसी EV की बिक्री शुरू कर दी है, जिनमें रेयर अर्थ इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह कुछ स्टार्टअप्स रेयर अर्थ की रिसाइकलिंग पर काम कर रहे है। दूसरी कंपनियां भी ये विकल्प अपना सकती है।

4 जापान का उदाहरण
2010 में जापान के साथ राजनीतिक तनाव हुआ, तो चीन ने रेयर अर्थ की सप्लाई रोक दी। जापान ने रेयर अर्थ माइन्स में खुद ही निवेश किया। अब चीन से उसका आयात 90% से घटकर 60% हो चुका है।

5 अमेरिका की पहल
अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसी साल कैलिफोर्निया में एक खदान में हिस्सेदारी खरीदी है। 2030 तक 22 नए प्रॉजेक्ट शुरू हो सकते है। एक भी बड़ा प्लेयर आया, तो चीन का दबदबा कम होगा।

प्रस्तुतिः शैलेंद्र पांडेय

चलते-चलते...

एक शोध में पता चला है कि Drosophila subobscura नाम की मक्खियां अपने प्रेम-प्रदर्शन में उल्टी का इस्तेमाल करती हैं। नर मक्खियां भोजन का थोड़ा हिस्सा उगलकर मादा को उपहार देती हैं, जिससे उनके प्रजनन के मौके बढ़ जाते हैं। इसमें fruitless नाम के प्रोटीन का विशेष महत्व है। Science पत्रिका में हाल में यह शोध प्रकाशित हुआ है।

डिजिटल डेटा की मांग सही है SIR

बिहार में चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानी SIR पर चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात रखी। योगेंद्र यादव लगातार SIR और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मसले पर उनसे बात की ***नाइश हसन*** *ने। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश :*

NBT सप्ताह का इंटरव्यू

योगेंद्र यादव

■ SIR को आपने अवैध बताया था। क्या आप इसकी कानूनी वैधता पर सवाल उठाने के पीछे के तर्क को थोड़ा समझा सकते हैं?

भारत का संविधान हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि एक बार जब वह नागरिक मान लिया गया, उसके बाद उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी, जब तक कि वह खुद त्याग न दे या जब तक कोई प्रमाण न मिल जाए कि उसकी नागरिकता अवैध थी। संविधान का आर्टिकल 10 इसका अधिकार देता है। लेकिन SIR ने तो इसे सिर के बल खड़ा कर दिया है। किसी व्यक्ति का नाम पिछले 20 साल से वोटर लिस्ट में था, इसका मतलब है कि उसे भारत का नागरिक माना जा रहा था। आज आप उससे कह रहे हैं कि तुम सबूत लाओ। ये कैसे हो सकता है?

■ क्या आपको लगता है कि SIR मतदाता सूची को सटीक बनाने के बजाय लोगों को वोट देने से वंचित करने का प्रयास है?

कुछ बातों को दर्ज करना जरूरी है। पहला, यह आदेश सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में लागू होगा। दूसरा, यह पुरानी वोटर लिस्ट में संशोधन की प्रक्रिया नहीं है, नए सिरे से कोरे कागज पर वोटर लिस्ट लिखने की प्रक्रिया है। तीसरा, इसमें देश के इतिहास में पहली बार वोटर लिस्ट में होने की जिम्मेदारी एक साधारण नागरिक पर डाली जा रही है। यह अब तक चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वह घर-घर जाकर लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करे। पहली बार वोटर से कहा गया है कि फलां तारीख तक फॉर्म भरो नहीं तो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। चौथी बात, पहली बार प्रत्येक वोटर से कहा जा रहा है कि वह अपनी नागरिकता के सबूत जमा करवाए। पहले सबूत तब दिखाने होते थे जब शक की कोई गुंजाइश हो। इन चारों लिहाज से मैंने कहा कि यह इंटेसिव रिवीजन नहीं इंटेंसिव डिलीशन है। इसका सीधा सा प्रमाण है कि एक महीने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग को बिहार में 65 लाख नाम मिल गए जो वोटर लिस्ट से कटने चाहिए थे। लेकिन एक भी नाम ऐसा नहीं मिला जो वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहिए था।

■ क्या आपको लगता है कि यह संख्या 65 लाख से ज्यादा बढ़ सकती है?

ऐसा होना लाजिमी है क्योंकि SIR के आदेश में लिखा हुआ है। अभी तक तो हमने केवल पहला चरण देखा है, जिसमें जिन लोगों का फॉर्म नहीं मिला, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया था। अब दूसरा चरण शुरू होगा। इसमें जिन लोगों का नाम आज ड्राफ्ट लिस्ट में है उनके सिर पर तीन तलवार और लटक रही है। पहली, इन 7,24,00,000 लोगों में कम से कम 10%, या हो सकता है उससे भी ज्यादा वो नाम हैं जिनके आगे BLO ने लिख दिया है नॉट रेकमेंडेड। यानी BLO ने उनका नाम अपलोड तो कर दिया है लेकिन उनका नाम अंतिम सूची में न रहे इसकी सिफारिश की। उनकी विशेष छानबीन होगी और जाहिर है उसमें से कई नाम कटेंगे। दूसरी, जिनका रेकमेंडेड भी है, उनमें से अधिकांश ने अभी तक कोई दस्तावेज नहीं दिए हैं। अगर चुनाव आयोग की 11 दस्तावेजों की सूची के हिसाब से जाएंगे तो उनमें से आधे लोगों के पास कोई दस्तावेज हैं ही नहीं। अब उनमें से वो लोग बच जाएंगे जिनका नाम 2003 की सूची में था। लेकिन जो 40 साल से कम के हैं, जिनका नाम तब हो ही नहीं सकता था, जो गरीब-मजदूर हैं, अनपढ़ हैं, जिनके पास कोई कागजात नहीं हैं, उनका नाम कटने की सूची में आएगा ही। तीसरी, अगर ड्राफ्ट लिस्ट पर आए किसी भी नाम पर कोई ऐतराज होता है, तो वह भी कटने की श्रेणी में आ सकता है। जाहिर है, ये लिस्ट 65 लाख से ऊपर जानी ही जानी है।

> **आज की दुनिया में किसी भी सूचना को सार्वजनिक करने का मतलब है कि आपने उसे इंटरनेट पर डाल दिया। इंटरनेट पर डालने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आपने इमेज फाइल लगा दी, जिसे कोई सर्च ना कर सके। आप एक ऐसे फॉर्मेट में सारा डेटा डालें, जिसे सर्च किया जा सके। मगर इलेक्शन कमिशन की जिद है कि कुछ भी करेंगे, सर्च लायक नहीं बनाएंगे**

■ राहुल गांधी ने डिजिटल डेटा की मांग की है, आप क्या कहेंगे इस बारे में?

आज की दुनिया में किसी भी सूचना को सार्वजनिक करने का मतलब है कि आपने इंटरनेट पर डाल दिया। इंटरनेट पर डालने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आपने इमेज फाइल लगा दी, जिसको कोई सर्च ना कर सके। आप एक ऐसे फॉर्मेट में सारा डेटा डालें, जिसे सर्च किया जा सके। पर इलेक्शन कमीशन की जिद है कि कुछ भी करेंगे, सर्च लायक नहीं बनाएंगे। पिछले दो-तीन साल से चुनाव आयोग की एक मनःस्थिति यह है कि जितनी कम सूचना दी जाए, उतना अच्छा। परसों ही सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने 45 मिनट तक जिरह की और हर तरह के पैंतरे का इस्तेमाल किया कि किसी तरह उसे कारण न बताने पड़ें। यह तो एक संवैधानिक संस्था के तौर-तरीके नहीं हो सकते। इसलिए राहुल गांधी की मांग बिल्कुल सही है।

■ सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर क्या कहेंगे?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जो मूल सिद्धांत हैं वो उम्मीद जगाते हैं कि पूरी SIR प्रक्रिया की परीक्षा कुछ सिद्धांतों के आधार पर होगी। पहला, पारदर्शिता का सिद्धांत। दूसरा, एक समावेशी प्रक्रिया यानी आधार, जो सबसे ज्यादा लोगों के पास है, उसको शामिल करना पड़ेगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट SIR को लागू करने की प्रक्रिया पर अपनी नजर रखेगा। ये सब अच्छे संकेत हैं।

रीडर्स मेल

▶ ट्रंप का 'टैरिफ बम'

15 अगस्त ट्रंप का नजरिया भारत के प्रति नकारात्मक है। भारी भरकम टैरिफ से होने वाले नुकसान से भारत के साथ-साथ यूरेशिया और यूरोप में मंहगाई, बेरोजगारी और मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और द्विपक्षीय व्यापार समझौते से टैरिफ की अल्पकालिक परेशानी हो सकती है। भारत के कपड़ा, आभूषण, रसायन क्षेत्र, दवा जैसे निर्यात-केंद्रित उद्योगों पर ज्यादा झटका लगेगा। इससे भारत की विकास दर में आधा प्रतिशत गिरावट हो सकती है। भारतीय सामान भारत और अमेरिका में मंहगे हो सकते हैं। भारत के कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। अंग्रेजी उत्पादों का बहिष्कार की संभावना बढ़ेगी। भारत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देगा। आपदा में अवसर का लोकल टू ग्लोबल का भारत लाभ ले सकता है। ऐसे में भारत को साहसिक कदम उठा के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है।

डॉ. मंजु गुप्ता, ईमेल से

▶ ऐसे दें जवाब

ट्रंप ने टैरिफ वार कर भारत की अर्थव्यवस्था को चुनौती दी है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी मान रहा है, वहीं, देश के कई उद्योगपतियों ने एकजुट होकर सरकार का साथ दिया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को आगे बढ़ाने का विश्वास दिलाया है। भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है, लेकिन राजनीतिक अराजकता, भ्रष्टाचार, मुफ्तखोरी अनुशासनहीनता को दूर किए बिना हम सुपर पावर नहीं बन सकते। आत्मनिर्भर भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा बाजार भारत में है। अमेरिका के आईटी सेक्टर में भारतीय प्रतिभाओं की वजह से विकास हो रहा है। सरकार अगर युवा भारत के युवाओं को उनकी योग्यता की सही कीमत दे, तो कोई क्यों अमेरिका जाना चाहेगा।

सुधा चौबे, ईमेल से

आर.एन.आई. बंबईकर संख्या 56 (1) 1952 | नवभारतटाइम्स.कॉम, बोरीवली (पूर्व) बंबई उपनगरीय जिला अंक, कुलमुद्रणालय दादाभाई ऑफ इंडिया लिमिटेड, डी. डी. एम. टावर, पोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनकी ओर से [illegible] | (1) राष्ट्रीय और इंडियन एक्सप्रेस प्रेस, आकुर्ली रोड, लिबर्टी सिनेमा सबवेज़ सामने, कांदिवली (पू.), मुंबई 400101 एवं (2) राष्ट्रीय और इंडियन प्रेस लिमिटेड, पोर्ट ई. ए. डी.डी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, अलंग सेलाइज़ प्रेस, रोहतक, पर्स मुंबई-400708, फोन नं. (022) 2760-9999 / फैक्स (022) 2760 5270 | फोन मुंबई : (022) 66383000, 27735555 | ग्रेटर (022) 66383666, 27735666 फैक्स (022) 27731888, 27731144, कार्टरोड (022) 28872224 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई)** : सुरेश पाटवाड़ा (पै. ओ. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) | कार्यकारी इंडिया: [illegible] | [illegible] | [illegible] |

राष्ट्रीय
सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 16 अगस्त • 2025
www.rashtriyasahara.com

एकता ही हमारी जवाबी कार्रवाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए देश एवं सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' सैन्य अभियान आतंकवाद के खिलाफ मानवता की लड़ाई में एक मिसाल के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा। 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा, 'इस सैन्य अभियान से जुड़ीं उपलब्धियां स्वाधीन भारत के रक्षा इतिहास में एक नये अध्याय का सूत्रपात है तथा विश्व समुदाय ने भारत की इस नीति का संज्ञान लिया है कि भारत आक्रमणकारी नहीं बनेगा, बल्कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा।' राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भारत की इस सामरिक सफलता के साथ ही आर्थिक विकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय खेल नीति, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ, डिजिटल भुगतान की सफलता तथा कृत्रिम मेघा (एआई) के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने नितांत अमानवीय कृत्य किया था, जब कश्मीर घूमने पहुंचे सैलानियों की हत्या कर दी थी। राष्ट्रपति ने इस कायरतापूर्ण कृत्य की भर्त्सना करते हुए कहा कि भारत ने फौलादी संकल्प के साथ निर्णायक तरीके से इसका जवाब दिया।

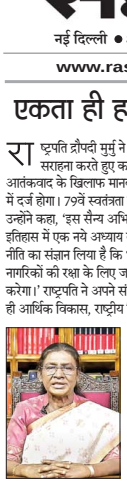

'ऑपरेशन सिंदूर' ने दिखा दिया कि जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, तब हमारे सशस्त्र बदल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम सिद्ध होते हैं। इस सैन्य अभियान ने रेखांकित किया है कि हमारी एकता ही हमारी जवाबी कार्रवाई की सबसे बड़ी विशेषता थी। यही एकता उन सभी तत्वों के लिए सबसे करारा जवाब भी है, जो हमें विभाजित करने पर आमादा दिखलाई पड़ते हैं। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान रणनीतिक स्पष्टता और तकनीकी दक्षता के साथ हमारी सेना ने सीमा पार के आतंकी ठिकानों बेहद सटीकता से निशाना बनाते हुए नष्ट कर दिया था। राष्ट्र के नाम अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देश में मतदाता सूची को लेकर चल रहे विवाद और आरोप-प्रत्यारोप के बीच मतदान के महत्त्व की विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता की प्राप्ति के पश्चात हम ऐसे लोकतंत्र के मार्ग पर बढ़े जिसमें सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार है। हमने लोकतंत्र पर आधारित ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया है, जिनसे लोकतांत्रिक कार्यशैली को मजबूती मिली है। हमारे लिए संविधान और लोकतंत्र सर्वोपरि है।

सहयोगात्मक रुख हो

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है, उसका कारण बताने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि जिन नागरिकों के नाम सूची से किन्हीं कारणों से हटा दिए गए हैं, उनको स्पष्ट कारण पता होना लाजिमी है ताकि वे सुधारात्मक कदम उठा सकें। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर बाइस लाख लोगों को मृत पाया गया है तो उनका नाम, ब्लॉक व सब-डिवीजन स्तर पर क्यों न बताया जाए। मृत, प्रवासी या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर न डालने पर भी पीठ ने सवाल उठाया। जिन पैंसठ लाख लोगों का नाम नई सूची में शामिल नहीं है, उनके हक की बात उठाने वाली विपक्षी पार्टियां निःसंदेह इस फैसले को लेकर उत्साही हैं। यह विवाद लंबा और आक्रामक रहा पर अंततः मतदाताओं के अधिकार की रक्षा होती नजर आ रही है। हालांकि आयोग ने दावों और आपत्तियों के लिए नागरिकों को खासा वक्त दिया था मगर इसमें पारदर्शिता नहीं थी। आयोग ने सारे विवाद के बाद चुनौती देते हुए कहा था कि अगर किसी के पास दो जगह वोट देने का सबूत है, तो शपथ-पत्र के साथ प्रमाण दे। बेशक, विपक्ष को अपनी बात रखने या आयोग पर आरोप मढ़ने से पहले उचित रूप से जांच-परख करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आयोग की जिम्मेदारी है कि देश का कोई नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से न चूके। यकीनन 2003 के बाद अब हो रहा यह पुनरीक्षण आसान नहीं रहा होगा। अवैध मतदाताओं, विदेशियों और मृतकों के नाम हटाना अनावश्यक नहीं कहा जा सकता। पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि साठ फीसद यानी 4.96 करोड़ मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देने हैं। राज्य के सात करोड़ अस्सी लाख से ज्यादा मतदाताओं का लेखा-जोखा संभालने में निर्वाचन आयोग को इसलिए चूक नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह लोक सभा चुनाव के दरम्यान देश भर में विभिन्न चरणों में सफलतापूर्वक चुनाव करवा करके हर पांचवे साल मिसाल कायम करता रहा है। निर्वाचन आयोग को बगैर देरी के पारदर्शितापूर्वक बगैर किसी दबाव के अपनी गरिमा और संवैधानिक अधिकारों का प्रदर्शन करने के प्रति दृढ़ नजर आना होगा। विपक्ष के सारे संदेह अब दूर हो जाने चाहिए। उसको भी अब सहयोगात्मक रवैया इख्तियार में संकोच नहीं करना चाहिए।

कटाक्ष/ कबीरदास

विकास तो हो रहा है

देखिए, देखिए, ये तो विपक्ष वालों की सरासर चीटिंग है। पहले तो खुद ही इसका शोर मचा रहे थे कि विकास कहां है? सिर्फ मुंहजुबानी बताते से क्या होगा, नाप कर दिखाओ। अर्थव्यवस्था का साइज सिकुड़ता क्यों जा रहा है, चलो इतना ही बताओ। और अब जब मोदी जी ने लाल किले से अपने भाषण में नया रिकार्ड बना दिया है, इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी, खुद अपना अब तक का रिकार्ड तोड़ कर दिखा दिया है, एक बार पानी पिया और भाषण एक सौ तीन मिनट पर पहुंचा दिया, तो भाई लोगों ने पैमाना ही बदल दिया। कहते हैं कि लंबा बोले तो, मगर कहा क्या? भाषण की लंबाई का विकास भी कोई विकास है, लल्लू!

खैर, मोदी जी भी कहां सिर्फ भाषण की लंबाई के विकास पर रुकने वाले थे। इसी भाषण में उन्होंने फेंकने की अपनी क्षमता के जैसे विकास का प्रदर्शन किया है, विपक्षी उसे कैसे भूल सकते हैं। गरीबी मिटाने के नाम पर उन्होंने जो ऊंची फेंकी है, उसके सामने ऊंची फेंक के सारे रिकार्ड ध्वस्त हैं, दूसरों के तो दूसरों के, खुद उनके भी। दस साल में 25 करोड़ तो गरीब से गैर-गरीब हो गए, जबकि डेढ़ साल का हिसाब जोड़ना अभी बाकी है। और गरीबी से निकलने वाले, अमीरी में नहीं भी गए हों तब भी, कम से कम निचो-मिडिल क्लास में तो पहुंच ही गए हैं। बेचारी, गरीबी करीब-करीब मिट ही चुकी है। जाहिर है कि मिटने वाली गरीबी में मुफ्त का राशन भकोसने वाले अस्सी करोड़ की गरीबी भी शामिल है। और बेरोजगारी मिटाने के मामले में उनके सामने लंबी फेंक के सारे रिकार्ड ध्वस्त हैं। ऐसी लंबी फेंकी है कि बेरोजगारी का नाम ही मिट गया है। सिर्फ रोजगार का नाम है और वह भी करोड़ों में। और आत्मनिर्भरता? ऐसी दूर की फेंकी है कि वहां तक नीरज चोपड़ा का भाला भी क्या जा पाएगा! यह सब भी तो विकास है। और यह जो लाल किले से मोदी जी का लगातार बारहवां भाषण हुआ, उसका क्या? लगातार बारहवां! यह इंदिरा गांधी के रिकार्ड के मुकाबले, विकास है या नहीं? और हां! लाल किले से बाहरवें भाषण में मोदी जी ने जो आरएसएस का कर्ज अदा किया, उसका क्या? यह मोदी राज और आरएसएस के रिश्ते का विकास है या नहीं? वैसे कहते हैं कि बारह साल में घूरे के दिन भी फिर जाते हैं। लेकिन, यह घूरे का तो विकास ही है।

किला से मैदान तक

सामयिक

प्रेम प्रकाश

भारत ने जिस घटनाचक्र के बीच अपना 79वां स्वाधीनता दिवस मनाया, वह महत्त्वपूर्ण है। पक्ष-विपक्ष की राजनीति से आगे इस बदले देशकाल को देखें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। पहली बात तो यही कि बीते एक दशक में देश का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चरित्र जिस तरह बदला है, उसने एक नये भारत का साक्षात्कार कराया है। दूसरी अहम बात यह कि टकराव और नफरत की सियासत की एक्सपायरी डेट अब नजदीक आ चुकी है।

आज देश के जन-गण-मन को अगर आज कोई बात खींच रही है, तो वो है विरासत के साथ विकास की बात। इस लिहाज से देखें तो लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण का कंपास तो हम समझ पाएंगे ही, साथ ही हम यह भी देख पाएंगे कि दिल्ली से हजार किलोमीटर दूर चुनावी राज्य बिहार में जब मुख्यमंत्री तिरंगा फहराता है, तो उसका फोकस किन बातों पर है। अखबारों और टीवी चैनलों के लिए भले यह सुर्खी हो कि पीएम मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर संसद में अपनी बात कहने के बाद फिर से एक बार अपनी रक्षा प्रतिज्ञा दोहराई है। पर ये बातें बस एक घटनाचक्र का हिस्सा हैं, जिस पर स्वाधीनता दिवस जैसे मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री देश के जवानों और आम जन को एक गर्वीले अहसास से भरते हैं।

बड़ी बातें दूसरी हैं, जिनमें उन्होंने देश की भावी दिशा और ठोस कदमों के बारे में बताया। इस सिलसिले में उन्होंने स्पेस और उद्यम क्षेत्र में सुधार के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया, तो वहीं देश के युवाओं के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी बात कही। इस मौके पर उन्होंने खास तौर पर कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की ओर भी जा रहे हैं, और हम समुद्र के भीतर के तेल और गैस के भंडार को खोजने की दिशा में मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की ये बातें अमेरिका के शुरू किए गए टैरिफ वार के बीच भारत के विवेक और भविष्य के रोडमैप को सामने रखती हैं। उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि विकसित भारत का आधार है आत्मनिर्भर भारत। अगर कोई दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाता है, तो स्वतंत्रता का प्रश्न ही धुंधला पड़ने लगता है। यह भी कहा कि आत्मनिर्भरता केवल आयात, निर्यात, रुपये, पाउंड या डॉलर तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। आत्मनिर्भरता सीधे हमारी ताकत से जुड़ी है।

देश के उद्यम और व्यापार क्षेत्र का भरोसा जीतने और नई चुनौतियों के बीच उनके भरोसे को बहाल रखने के लिए उन्होंने कहा, 'इस बार दोहरी दिवाली मनेगी...पिछले आठ वर्षों में, हमने जीएसटी में एक बड़ा सुधार किया है। अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं।' आर्थिक सुधार के इस बड़े कदम के ऐलान के साथ सरकार इस बात का भरोसा देश को दिला रही है कि नये वैश्विक संकट के बीच बढ़ने की राह उसने खोज ली है। निश्चित रूप से यह रास्ता आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का है।

उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में मंदी की आशंका के बीच एक बड़ा खतरा युवाओं के मनोबल टूटने का है। अगर ऐसा हुआ तो आत्मनिर्भरता तो दूर देश गहरी निराशा के गर्त में डूब जाएगा। लिहाजा, लाल किले की प्राचीर से पीएम ने जब कहा कि आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है, तो साफ लगा कि सरकार अपनी प्रतिबद्धता और प्राथमिकता, दोनों को समझ रही है। पीएम ने युवाओं के लिए जिस योजना की बात कही उसका एक चमकदार पक्ष यह भी है कि इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को 15 हजार रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यही नहीं, जो कंपनियां रोजगार के नये अवसर ज्यादा पैदा करेंगी उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी मिलेगी। जिस एक मुद्दे पर बात करते हुए प्रधानमंत्री सियासी गोटी खेलते साफ नजर आए, वो है देश में घुसपैठियों की समस्या के कारण बदलती डेमोग्राफी की। जिस हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात उन्होंने कही, उसका अर्थ निश्चित तौर पर एक दिन पहले एसआईआर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों से जोड़ा जाएगा। घुसपैठ देश में निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या रही है, पर इससे चुनावी गणित साधने की कोशिश के खतरे भी हम देख चुके हैं। गौरतलब है कि अगले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। गहन मतदाता पुनरीक्षण का मामला भी वहीं से गरमाया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सुनवाई में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की भूमिका और मंशा, दोनों पर सवाल उठे हैं।

चूंकि सारा पेच बिहार की चुनावी राजनीति का है, तो इस 15 अगस्त पर लोगों की निगाह स्वाभाविक तौर पर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण पर भी रही। अच्छी बात यह कि इस चुनावी सूबे के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण को पूरी तरह विकास पर केंद्रित रखा। वे इससे पहले भी लगातार बीते दो दशक में बिहार में आए बदलाव और विकास से जुड़ी उपलब्धियों की बात करते रहे हैं। वैसे इस मौके पर उनकी यह नई घोषणा जरूर प्रदेश के युवाओं को उत्साहित कर गई होगी कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क अब सौ रुपये होगा। यही नहीं, मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क भी नहीं देना होगा। अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के बिहार कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य के युवाओं के लिए निश्चित तौर पर यह बड़ी खुशखबरी है। इस मौके पर नीतीश ने प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया और कहा कि प्रदेश के विकास में केंद्र से मिल रही योजनागत और आर्थिक मदद से बिहार विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। इस बार 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले और पटना के गांधी मैदान में मौसम का रंग जरूर एक जैसा था, पर इस अवसर पर दिए गए दो अहम संबोधनों के बीच जो एक समानता दिखती है कि वह यह कि देश की राजनीति को विकास और युवाओं से दूर करने का जोखिम अब सभी समझते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जातीय और सामाजिक अलगाव के बूते सियासी शह-मात के दिन अब लद चुके हैं।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

> इस वार 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले और पटना के गांधी मैदान में मौसम का रंग जरूर एक जैसा था, पर इस अवसर पर दिए गए दो अहम संबोधनों के बीच जो समानता दिखती है कि वह यह कि अब देश की राजनीति को विकास और युवाओं से दूर करने का जोखिम सभी समझते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जातीय और सामाजिक अलगाव के बूते सियासी शह और मात के दिन अब लद चुके हैं

तबाशीर के फायदे

- वंशलोचन, जिसे कई लोग तवाशीर भी कहते हैं, एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो बांस के तने के अंदर से निकलता है। यह सफेद रंग का होता है, और आम तौर पर पाउडर या छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में मिलता है। इसे 'बैंबू मैनना' या 'बैंबू सिलाइसेस' के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम 'डैम्बुसा अरुंडिनेसिया' है
- वंशलोचन आम तौर पर भारत, फिलीपींस, चीन आदि एशियाई देशों में व्यापक रूप से उगाया जाता है। चरक संहिता और भैषज्य रत्नावली जैसे ग्रंथों में वंशलोचन को अनेक रूपों में उपयोग में लाया जाता है, जैसे सितोपलादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, वंशलोचनादि चूर्ण इत्यादि

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

हमने अंतिम वार घुसपैठिया का शोर पिछले साल झारखंड में चुनाव के पहले सुना था, जब जनजाति समाज की जमीन पर कब्जे की बातें कही गई थीं। भाजपा हारी थी। 2024 के राष्ट्रीय चुनाव में भी अल्पसंख्यकों (आरक्षण और मंगलसूत्र आदि) को लेकर भी ऐसा ही शोर मचा था, लेकिन भाजपा को लोक सभा की 63 सीटें गंवानी पड़ी थीं। अब हम विश्वगुरु का शोर सुन रहे हैं।

सबा नकवी, पत्रकार @_sabanaqvi

समस्या और सुप्रीम कोर्ट

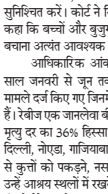

मुद्दा **रजनीश कपूर**

बीती ग्यारह अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया कि दिल्ली सरकार और स्थानीय निकाय अगले छह-आठ सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटा कर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करें, उनकी नसबंदी करें और टीकाकरण सुनिश्चित करें। कोर्ट ने स्थिति को 'बेहद गंभीर' बताते हुए कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को आवारा कुत्तों के हमलों से बचाना अत्यंत आवश्यक है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में इस साल जनवरी से जून तक 35,198 कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए जिनमें 49 रेबीज के मामले भी शामिल हैं। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और भारत वैश्विक रेबीज मृत्यु दर का 36% हिस्सा लेता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में तत्काल प्रभाव से कुत्तों को पकड़ने, नसबंदी और टीकाकरण करने और उन्हें आश्रय स्थलों में रखने की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही कोर्ट ने एक हेल्पलाइन स्थापित करने और आश्रय स्थलों में सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। पशु प्रेमियों, जो जानवरों के कल्याण के प्रति संवेदनशील होते हैं, को इस निर्णय को सकारात्मक कदम के रूप में देखना चाहिए। यह आदेश केवल कुत्तों को सड़कों से हटाने की बात नहीं करता, बल्कि उनके लिए सुरक्षित और मानवीय वातावरण प्रदान करने पर भी जोर देता है। नसबंदी और टीकाकरण जैसे कदम न केवल कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करेंगे, बल्कि उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे। कहना न होगा कि आवारा कुत्ते अक्सर भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी से जूझते हैं। इस कारण आक्रामक हो सकते हैं। आश्रय स्थलों में उन्हें नियमित भोजन, चिकित्सा देखभाल और सुरक्षित स्थान मिलेगा जो उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार को कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। यह न केवल दिल्ली-एनसीआर, बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। कोर्ट ने शुरुआत में 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थलों के निर्माण का आदेश दिया है। दिल्ली में अनुमानित 10 लाख आवारा कुत्तों को देखते हुए यह संख्या अपर्याप्त हो सकती है। फिर, इन आश्रय स्थलों में पशु चिकित्सकों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति भी आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 70% से अधिक कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण रेबीज को नियंत्रित करने में प्रभावी है। गोवा का 'मिशन रेबीज' इस दिशा में सफल उदाहरण है, जिसने रेबीज को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। कोर्ट ने एक हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्देश भी दिया है, जो कुत्तों के काटने की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करे। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि हेल्पलाइन 24/7 सक्रिय रहे। शिकायत मिलने पर चार घंटे के भीतर कार्रवाई हो। रेबीज और कुत्तों के काटने से बचाव के लिए जनता को जागरूक करना आवश्यक है। लोगों को सड़कों पर कुत्तों को भोजन न देने को कहना होगा क्योंकि यह उनकी आबादी को बढ़ाने का कारण बनता है। अभी पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के तहत नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ना अनिवार्य है। यह नियम कई बार प्रभावी नहीं होता क्योंकि यह आक्रामक कुत्तों को नियंत्रित करने में बाधा बनता है।

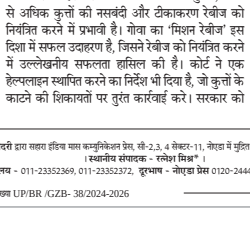

सरकार को नियमों में संशोधन करना चाहिए ताकि खतरनाक कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जा सके। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इस प्रक्रिया में कुत्तों के साथ क्रूरता न हो। आश्रय स्थलों में कुत्तों को पर्याप्त भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए। पशु कल्याण संगठनों को इस प्रक्रिया में शामिल करना जरूरी है ताकि सुनिश्चित हो सके कि कुत्तों के साथ मानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या को हल करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में नीदरलैंड ही ऐसा देश है जहां आपको आवारा कुत्ते नहीं मिलेंगे। नीदरलैंड सरकार ने एक अनूठा नियम लागू किया। किसी भी पालतू पशु की दुकान से खरीदे गए महंगी नस्ल के कुत्तों पर वहां सरकार भारी मात्रा में टैक्स लगाती है। वहीं यदि कोई नागरिक बेघर पशुओं को गोद लेकर अपनाता है, तो उसे आयकर में छूट मिलती है। इस नियम के लागू होते ही लोगों ने अधिक से अधिक बेघर कुत्तों को अपनाना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे नीदरलैंड में आवारा कुत्तों की संख्या घटते-घटते शून्य हो गई। दुनिया भर के पशु प्रेमी संगठनों ने इस कार्यक्रम को सबसे सुरक्षित और असरदार माना है। इस कार्यक्रम से न सिर्फ आवारा कुत्तों की जनसंख्या पर रोक लगती है, बल्कि आम नागरिकों को भी इस समस्या से निजात मिलती है। हमारे देश में ऐसा कब होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

शांति की स्थापना **संत राजिन्दर**

आज हम दुनिया में देखते हैं कि चारों ओर हिंसा और नफरत का माहौल है। एक देश दूसरे देश पर कब्जा करना चाहता है। इसी तरह सामाजिक तौर पर भी उच्च पद को पाने के लिए लोग एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी हम एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में अपने अंदर नफरत और हिंसा की भावना पैदा कर लेते हैं। ऐसे ही एक परिवार में भी सदस्य एक-दूसरे के विचारों से सहमत न होने के कारण आपस में लड़ते-झगड़ते रहते हैं। संतों-महापुरुषों की शिक्षा के अनुसार अगर हमें किसी को अपना बनाना है, तो प्रेम के गुण को हमें अपने अंदर ढालना होगा। अब हमने देखना यह है कि हम अपने बच्चों और पोते-पोतियों को उपहार में क्या देना चाहते हैं? क्या हम उन्हें हिंसा और युद्ध की दुनिया में छोड़ना चाहते हैं? या हम उनके लिए शांति, प्रेम और एकता की दुनिया की कामना करते हैं? चुनाव हमें करना है। आज दुनिया में बच्चे काफी हिंसा से भरपूर माहौल देख रहे हैं। इस करके उन्होंने अपने परिवार के अनेक सदस्यों को खो दिया है। समय आ गया है कि हम खुद पर एक सख्त नजर डालें। समय आ गया है कि हिंसा को न कहने के लिए हम अपने अंदर परिपक्वता और बुद्धि का विकास करें। आइए, हम अपनी ऊर्जा का उपयोग एक शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में करें। हर कोई दुनिया में शांति चाहता है। हम सब अपने महाद्वीपों, देशों, शहरों और अपने घर-परिवारों में शांति चाहते हैं। इन सबसे बढ़ कर हम अपने भीतर शांति चाहते हैं। फिर भी आज हम दुनिया भर में हो रहे अत्याचारों, हिंसा और अपराधों को देखते हैं। हमें देखना यह है कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस समस्या का हम एक समाधान निकाल सकते हैं, जिसे जान कर हमें आश्चर्य होगा कि हमने इसे क्यों अनदेखा कर दिया? एक शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण पहले नींव के पत्थर से शुरू होता है 'स्वयं' से। विश्व शांति की स्थापना में योगदान करने के लिए हमें पहले स्वयं शांति प्राप्त करनी चाहिए। आप पूछ सकते हैं : मैं अकेला व्यक्ति, व्यक्तिगत आंतरिक शांति प्राप्त करके विश्व शांति के लिए क्या योगदान दे सकता हूं? ऐसा करके हम अपने कार्यों से न सिर्फ मानवता, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी फर्क ला सकते हैं।

रीडर्स मेल

चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे का संकट

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे राजनीतिक विवाद ने सत्ता और विपक्ष के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा कर दिया है। चुनाव आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सही मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए है, जिसमें मृत, विस्थापित और फर्जी नाम हटाए गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह कार्रवाई चुनिंदा वोटरों को हटा कर भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, जबकि आयोग ने आरोपों के प्रमाण मांगे हैं। यह स्थिति बताती है कि चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे का संकट कितना गंभीर है। एक ओर चुनाव आयोग के पास कानूनी अधिकार और प्रक्रियात्मक पारदर्शिता है, तो दूसरी ओर विपक्ष को संदेह है कि प्रशासनिक कदम राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लोकतंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता, दोनों की बुनियादी शर्त है कि प्रक्रियाओं पर सभी पक्षों का विश्वास हो। इसलिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग आरोपों की निष्पक्ष जांच करे और विपक्ष अपनी ओर से ठोस प्रमाण पेश करे। आरोप-प्रत्यारोप की बजाय यह समय है कि सभी पक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में योगदान दें।

महेन्द्र तिवारी, ई मेल से

स्वतंत्रता की सार्थकता

आजादी का अर्थ केवल बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदार आचरण भी है। दुर्भाग्य से नई पीढ़ी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम का दर्द नहीं देखा, अक्सर इसका दुरुपयोग करती दिखती है। सार्वजनिक स्थानों, ट्रेनों, बसों और पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक और अन्य कचरे के अंबार हमारी लापरवाही का प्रमाण हैं। कूड़ेदान उपलब्ध होने पर भी लोग कचरा खुले में फेंकते हैं, जिससे पर्यावरण और जीव-जंतुओं को नुकसान होता है। यह प्रवृत्ति न केवल असभ्यता दर्शाती है, बल्कि आजादी के असली मूल्य को भी कमजोर करती है। जरूरी है कि नागरिकों में स्वच्छता के प्रति सजगता और जवाबदेही की भावना विकसित हो। साथ ही, कानूनन सख्ती और जुर्माने की व्यवस्था भी लागू हो ताकि लोग अपना कर्त्तव्य निभाएं। स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब उसके साथ गरिमा, जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जुड़ी हो वरना यह उपलब्धि भी समय के साथ अर्थ खो देगी।

अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

भाजपा की जीत-हार, दोनों

पहली बार देश में कांस्टिट्यूशनल क्लब के सचिव पद पर हुए चुनाव की चर्चा हुई। यह चुनाव भाजपा के दो दिग्गज नेताओं राजीव प्रताप रूड़ी और संजीव बालियान के बीच हुआ। राजीव प्रताप रूड़ी बिहार के छपरा से पांच बार के सांसद हैं, जबकि संजीव बालियान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोक सभा क्षेत्र से दो बार सांसद रह चुके हैं। भाजपा बनाम भाजपा के बीच हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई। अमित शाह का समर्थन बालियान के साथ था, तो सोनिया गांधी एवं समस्त कांग्रेसजनों का समर्थन राजीव प्रताप रूड़ी को प्राप्त हो गया। चुनाव में रूड़ी को मिली जीत को कांग्रेस अपनी जीत समझ रही है। इस चुनाव में भाजपा की जीत और हार, दोनों हुई हैं।

हिमांशु शेखर, गयाजी
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बाराखंभा रोड, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-35, अंक 2
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश

हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर देशवासियों को राष्ट्र नायक के सम्बोधन का इंतजार रहता है। राष्ट्र नायकों की वाणी देशवासियों को बहुत प्रभावित करती रहती है। उनके विचार युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करते रहे हैं। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्र नायक सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख और जनता के हित में कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसा राष्ट्र नायक हो तो उनका संदेश केवल देशवासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए होता है। नरेन्द्र मोदी अपने जीवन में संघर्ष का सामना करते हुए देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। उनके विचारों से जन-जन के हृदय में भारतीय होने का गर्व महसूस होता है और वे लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए जोश से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति यह निश्चित कर लेता है कि उसे कुछ हासिल करना है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। यह लोगों की शक्ति का प्रमाण होता है। देश का निर्माण सरकारें तो करती ही हैं बल्कि देश का निर्माण इसके नागरिकों की ताकत में होता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा अपने सशक्त विचारों और दिन-रात काम करने की शैली ने देशवासियों में आगे बढ़ने का जोश और जज्बा भरा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने 12वें सम्बोधन में भारत को समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की नई दिशा प्रस्तुत की है। उन्होंने तकनीकी प्रगति, आर्थिक आत्मनिर्भरता, देश की सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर अनेक पहलुओं को उजागर किया है। उनका सम्बोधन आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए एक स्पष्ट दिशा और मजबूत संकल्प दर्शाता है।

स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाह्य बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और आत्म-नियंत्रण है, जिसके बिना कोई भी राष्ट्र न तो दीर्घकालीन प्रगति कर सकता है, न ही आत्म-गौरव का अनुभव कर सकता है। भारत एक ऐसा ही राष्ट्र है इसकी जड़ों में संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म की अद्भुत समृद्धता है। इसके पास केवल भौगोलिक विस्तार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गहराई भी है। आज भारत केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करता, बल्कि वह आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान केवल एक आर्थिक योजना नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का घोष है। यह देशवासियों को कहता है कि हम विचारों, तकनीक, संसाधनों और चरित्र में आत्मनिर्भर बनें। आज भारत रक्षा क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान, मिसाइलें और उपग्रह बना रहा है। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में 'इसरो' और 'डीआरडीओ' जैसी संस्थाएं विश्वस्तरीय अनुसंधान कर रही हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियान भारत को केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं बना रहे, बल्कि आत्मविश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र भी बना रहे हैं। यह वही आत्मविश्वास है, जो स्व-नियंत्रण से उपजता है।

> **लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने 12वें सम्बोधन में भारत को समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की नई दिशा प्रस्तुत की है। उन्होंने तकनीकी प्रगति, आर्थिक आत्मनिर्भरता, देश की सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर अनेक पहलुओं को उजागर किया है। उनका सम्बोधन आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए एक स्पष्ट दिशा और मजबूत संकल्प दर्शाता है।**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेमीकंडक्टर उत्पादन में भारत के एक ताकत बनने का उल्लेख किया और घोषणा की कि इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप बनकर तैयार हो जाएगी। देश में सेमीकंडक्टर के 6 यूनिट बनकर तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी डॉलर पर भी निशाना साधा और कहा कि आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपए, पैसे, पाउंड, डॉलर तक सीमित नहीं है। यह कहकर बिना डॉलर के लेन-देन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को दो टूक जवाब दे दिया है कि भारत अपने किसानों, डेयरी उत्पादकों के हितों पर समझौता नहीं करेगा। कोई भी नीति जो भारतीयों के हितों को खतरे में डालती हो मोदी उसके खिलाफ दीवार बनकर खड़ा है। यह ट्रम्प को साफ संदेश है कि भारत टैरिफ को लेकर कोई समझौता नहीं करने वाला। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होते तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा बड़ा फैसला नहीं कर पाते। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि अगर उसने आगे भी हिमाकत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा।

देश के रक्षा बलों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उन्होंने सुदर्शन चक्र परियोजना का ऐलान किया। सुदर्शन चक्र परियोजना न केवल भारत की सुरक्षा करेगी बल्कि दुश्मनों का संहार भी करने में सक्षम होगी। उन्होंने दाम कम दम ज्यादा का नारा देते हुए कहा कि भारत अब सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने सम्बोधन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा का उल्लेख करते हुए संघ को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया। उन्होंने अवैध घुसपैठियों, नक्सलवाद, बेरोजगारी दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने तीन करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने का भी ऐलान किया। उन्होंने जीएसटी रिफार्म की घोषणा करते हुए देशवासियों को भरोसा दिया कि जीएसटी की दरें कम की जाएंगी, ताकि वस्तुएं कम दाम पर मिलें। देश के कई वर्गों खासतौर पर व्यवसायियों और उद्यमियों की मांग रही है कि जीएसटी की दरों की समीक्षा हो और उन्हें तर्कसंगत बनाया जा सके। जीएसटी की दरें कम होने से आम आदमी को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल नारे को जन आंदोलन बनाने की बात कही और देशवासियों को स्वदेशी अपनाने की अपील की। अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब मेड इन इंडिया फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं और भारत अब अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कड़े परिश्रम का आह्वान करते हुए कहा,

''परिश्रम में जो तपा है
उसने ही तो इतिहास रचा है
जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है
उसने ही समय को मोड़ा है।''

प्रधानमंत्री ने भारतीयों को सफलता का मंत्र दे दिया है। अब हर देशवासी का दायित्व है कि वह विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जुट जाएं।

क्या राहुल खोई हुई जमीन हासिल कर पायेंगे?

कलम-दवात

कुमकुम चड्ढा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं, पहले अरुण जेतली प्रकरण और अब "वोट चोरी" वेबसाइट का विवाद। पहले संदर्भ समझिए: लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए 'झूठ बोलना' जैसा शब्द बहुत कठोर है। इसलिए इसे 'तथ्यों में उलझन' कहना ज़्यादा उचित होगा। सौभाग्य से गांधी ने यह टिप्पणी संसद के बाहर की, वरना उन पर सदन को गुमराह करने का आरोप लग सकता था।

पार्टी के एक सम्मेलन में भाषण देते हुए गांधी ने अरुण जेतली की कथित 'धमकी' का ज़िक्र करते हुए कहा-मुझे याद है, जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था, अरुण जेतली जी को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा, 'अगर तुम सरकार का विरोध जारी रखोंगे और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ोंगे तो हमें तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। गांधी ने आगे कहा-मैंने उनकी ओर देखकर जवाब दिया, 'शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम कायर नहीं हैं। हम कभी झुकते नहीं, अंग्रेज जैसे महाशक्ति हमें नहीं झुका पाए तो आप कौन होते हैं?' मगर यहां एक बड़ा विरोधाभास है- जानबूझकर या अनजाने में कहना मुश्किल है। सच यह है कि किसानों का आंदोलन, जेतली के निधन के एक साल बाद हुआ था।

बात को यहीं न छोड़ते हुए, दिवंगत केंद्रीय मंत्री के बेटे रोहन जेतली ने राहुल गांधी के दावे को 'पूरी तरह झूठा और तथ्यों से रहित' बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी 'बिना तथ्यों के बयान देने का इतिहास' रखते हैं। रोहन ने कहा-मेरे पिता का निधन 2019 में हुआ, जबकि कृषि कानून 2020 में लाए गए। यह न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए बेहद गैर-जिम्मेदाराना भी है।

भाजपा ने भी राहुल गांधी के बयान को 'फेक न्यूज' और 'बेसिर-पैर की आरोपबाज़ी' करार दिया। पार्टी ने तथ्य रखते हुए बताया कि कृषि विधेयक का मसौदा 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया गया और सितंबर 2020 में इन्हें कानून का रूप दिया गया, जबकि अरुण जेतली का निधन 24 अगस्त 2019 को हो गया था। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा-यह सुझाव देना कि अरुण जेतली जी ने किसी भी तरह उनसे संपर्क किया, तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। आइए तथ्यों पर टिकें और अपनी सुविधा के लिए समय रेखा को न बदलें।

वहीं, कांग्रेस ने अपने नेता के बयान का बचाव करते हुए कहा कि भले ही कृषि कानून जेतली के निधन के एक वर्ष बाद लाए गए हों लेकिन वे भाजपा सरकार के "लंबे, सोचे-समझे, किसान विरोधी एजेंडे की परिणति" थे। हालांकि पार्टी यह भूल गई या शायद भूलने का चुनाव किया कि निधन से कुछ माह पहले ही जेतली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उसी वर्ष, उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण केंद्रीय वित्त मंत्री का पद छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में जेतली ने कहा था कि वे पिछले 18 महीनों से गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है। यह पत्र मई 2019 में लिखा गया था। साधारण गणना से 18 महीने पीछे जाने पर समय शुरुआती 2018 का बनता है। ऐसे में कांग्रेस का यह तर्क कि आंदोलन एक लंबी लड़ाई की परिणति था, टिकता नहीं है। यह सही है कि आंदोलन केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयकों का मसौदा मंजूर होने से पहले शुरू हो गया था लेकिन यह निश्चित रूप से उस समय नहीं था जब जेतली राजनीतिक रूप से सक्रिय थे।

जून 2020 में मोदी मंत्रिमंडल ने तीन कार्यकारी आदेश पेश किए, जिन्हें सितंबर में लोकसभा से पारित कराया गया। इसके तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफ़ा दे दिया, यह कहते हुए कि यह कानून 'किसान विरोधी' हैं। किसान भी सड़कों पर उतर आए, रेल की पटरियां और राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले राजमार्ग ट्रकों, ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टर्स से अवरुद्ध कर दिए। समय-रेखा की गड़बड़ी से अलग, गांधी का दिवंगत जेतली के राजनीतिक अंदाज का आंकलन भी चूक गया। जेतली एक अलग ही किस्म के राजनेता थे, इतने परिष्कृत कि 'धमकी' जैसे हथकंडों का इस्तेमाल करना उनके स्वभाव में नहीं था। राजनीति में और उसके बाहर, जिन्हें लोग जेतली के रूप में जानते थे, वे कोई ऐसे दबंग नहीं थे जो किसी को बुलाकर अंजाम की चेतावनी दें, जैसा कि गांधी के बयान से प्रतीत होता है। अगर ऐसा करना होता तो जेतली इतने कुशल थे कि संदेश अप्रत्यक्ष रूप से भिजवा देते, बजाय खुले तौर पर टकराव में आने के और जहां तक परिणामों की बात है, उनमें भी गांधी को पहले से चेताने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

रोहन जेतली ने विपक्ष के नेता के पद से जुड़ी जिम्मेदारियों के संदर्भ में बिल्कुल सटीक टिप्पणी की- इस पद के लिए परिपक्वता और गंभीरता चाहिए, न कि तात्कालिक, लापरवाह बयान, जैसा कि गांधी अक्सर देते हैं। हां, मगर सड़क की राजनीति में गांधी माहिर हैं। वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो सीधे जनभावनाओं को छूते हैं। हाल ही में उन्होंने एक वेब पेज शुरू किया, जहां लोग पंजीकरण कर चुनाव आयोग (ईसीआई) से 'वोट चोरी' के ख़िलाफ जवाबदेही तय करने और डिजिटल मतदाता सूची लागू करने की मांग का समर्थन कर सकते हैं। गांधी ने कहा-हमारी चुनाव आयोग से मांग साफ है- पारदर्शिता दिखाइए और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक कीजिए, ताकि जनता और राजनीतिक दल खुद इसका ऑडिट कर सकें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे वेबसाइट पर पंजीकरण कर इस मांग का समर्थन करें। पोर्टल पर एक संदेश भी है जिसमें लिखा गया है कि वोट हमारे लोकतंत्र की नींव है लेकिन यह 'भाजपा द्वारा सुनियोजित हमले' के तहत है और इसमें चुनाव आयोग 'सहयोगी' है।

संदेश में कहा गया है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पहले भी चेतावनी दे चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। अब हमारे पास सबूत है। हम इस वोट चोरी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ें और लोकतंत्र की रक्षा करें। हालांकि, इस अभियान के बीच एक कांग्रेस मंत्री द्वारा पार्टी हाईकमान को निशाना बनाना, एक अलग मामला है। फिर भी 'वोट चोरी' अभियान जनता के बीच असर डालने की संभावना रखता है ठीक वैसे ही जैसे पिछली लोकसभा चुनाव में 'संविधान बचाओ' का नारा गूंजा था। 2024 में गांधी ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ जेब में संविधान की प्रति रखकर भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। संविधान की प्रति हाथ में लेकर गांधी ने दलितों, आदिवासियों, गरीबों और अल्पसंख्यकों से अपील की थी कि वे 'इस संविधान की रक्षा करें।' उस समय उन्होंने 2024 का चुनाव 'लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव' करार दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। यह प्रचार भाजपा के खिलाफ असरदार साबित हुआ 'एक ओर नरेंद्र मोदी जी और भाजपा हैं जो इसे (संविधान) खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस है जो संविधान की रक्षा कर रही है,' गांधी ने तब कहा था।

भाजपा बहुमत से पीछे रह गई और सरकार बनाने के लिए अन्य दलों का समर्थन लेना पड़ा। वहीं इंडिया गठबंधन ने 200 से अधिक सीटें जीतीं और कांग्रेस अकेले 99 सीटों पर पहुंची। चुनाव के बाद भी कांग्रेस नेताओं द्वारा संविधान का मुद्दा उठाना पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और भाजपा को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया। इसलिए, भले ही जेतली वाले मुद्दे पर गांधी कमजोर स्थिति में हों, वे 'वोट की चोरी' अभियान के जरिए पिछले साल के 'संविधान बचाओ' की तरह, खोई हुई ज़मीन फिर हासिल कर सकते हैं। असली परीक्षा होगी इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव।

'हिमगिरि' और 'उदयगिरि'

आकाश चोपड़ा

आईएनएस उदयगिरि को मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने बनाया गया है, जबकि हिमगिरि को कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। खास बात यह है कि उदयगिरि नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो का 100वां डिजाइन किया गया जहाज है। करीब 6700 टन वजनी ये जहाज शिवालिक क्लास से बड़े और ज्यादा उन्नत हैं। दोनों एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल से लैस हैं, जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। प्रत्येक जहाज का विस्थापन लगभग 6,700 टन है और इसका डिज़ाइन ऐसा है कि रडार सिग्नल कम दिखाई देता है। भारतीय नौसेना भारत में निर्मित दो उन्नत युद्धपोत उदयगिरि और हिमगिरि को नौसेना में शामिल करेगी

भारतीय नौसेना लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है जो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के लिए चिंता का कारण बन रही है। भारतीय नौसेना पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरह के खतरों को संभालने वाली एक बहुआयामी ताकत के रूप में विकसित हुई है। पश्चिमी हिंद महासागर में रुकवाटों से वैश्विक शिपिंग की सुरक्षा के लिहाज से इसके सक्रिय काउंटर-पायरेसी ऑपरेशन और हाल ही में की गई तैनाती ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकारोक्ति अर्जित की है। इसके अलावा पाकिस्तान की नौसेना क्षमता भारत के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। भारतीय नौसेना के बेड़े में 26 अगस्त को एक साथ दो बेहद आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स (रडार को चकमा देने वाले युद्धपोत) उदयगिरि (एफ35) और हिमगिरि (एफ34) शामिल होंगे। यह पहली बार होगा जब देश के दो बड़े शिपयार्ड में बने इस तरह के युद्धपोत एक साथ नौसेना में शामिल किए जाएंगे।

ये जहाज एक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित होते हैं जो नियंत्रित-पिच प्रोपेलर को चलाने के लिए डीजल इंजन और गैस टर्बाइन दोनों का उपयोग करती है। इन जहाजों का प्रबंधन एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। उनकी हथियार प्रणालियों में सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, 76 मिमी मुख्य तोप, 30 मिमी और 12.7 मिमी निकट हथियार प्रणालियां तथा पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण शामिल हैं। इनका डिजाइन ऐसा है कि ये रडार को चकमा देने में सक्षम हैं। इनमें डीजल इंजन और गैस टर्बाइन दोनों लगे हैं, आधुनिक मिसाइलें, तोप और पनडुब्बी रोधी हथियार भी हैं। दोनों भारतीय नौसेना के नेक्स्ट-जनरेशन स्टील्थ वॉरशिप हैं जो प्रोजेक्ट 17ए के तहत बनाए गए हैं। इन युद्धपोत के निर्माण में 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया जिससे 4,000 से ज्यादा लोगों को सीधी और 10,000 से ज्यादा को अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलीं। 'उदयगिरि' और 'हिमगिरि' का जलावतरण जहाज डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नौसेना इसके बाद अन्य स्वदेशी पोतों जैसे विध्वंसक आईएनएस सूरत, फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरि, पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर, एएसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्नाला और डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार का जलावतरण 2025 में करेगी।

नौसेना के मुताबिक यह युद्धपोत भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाने का मौका है, इन जहाजों के शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। इन दोनों युद्धपोत के आने से भारत न सिर्फ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की निगरानी कर सकेगा, बल्कि मलक्का जलडमरूमध्य तक चीनी जहाजों की हर हलचल पर नजर रख पाएगा। यह हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश भी है। चीन हाल के वर्षों में हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, खासकर श्रीलंका, मालदीव और अफ्रीकी तटों पर बंदरगाहों के जरिये। वहीं पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर चीन की नौसैनिक गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय रही हैं। हिमगिरि और उदयगिरि सिर्फ युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत के आत्मबल, तकनीकी प्रगति और वैश्विक ताकत बनने की दिशा में एक और मजबूत कदम है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

देश के लिए रोल मॉडल बना पंजाब

भगवंत मान
(मुख्यमंत्री, पंजाब)

भारत ने आज आजाद, संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में 78 वर्ष पूरे कर लिए हैं। महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नायकों के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। भ्रष्टाचार और नशे की लत के प्रति कोई रियायत न बरतने की नीति को सख्ती से अपनाया गया है।

इस पवित्र अवसर पर मैं देश-विदेश में बसे पंजाबियों की ओर से समस्त देशवासियों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। मैं आप सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबियों की अनूठी और अद्वितीय भूमिका किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि यह तथ्य रिकॉर्ड में दर्ज है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी जान न्यौछावर करने वालों में 80 प्रतिशत से अधिक पंजाबी थे। यहां तक कि पंजाबियों द्वारा देश की आजादी के लिए चलाए गए आंदोलनों ने सदियों पुराने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। भाई महाराज सिंह पहले पंजाबी योद्धा थे, जिन्होंने इस नेक कार्य के लिए शहादत दी थी।

हमारे महान शहीद और धरती के सपूत शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, लाला लाजपत राय, शहीद उधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा, दीवान सिंह कालापानी, बाबा राम सिंह, सोहन सिंह भकना और कई अन्य अनाम नायकों ने आजादी के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने खून का एक-एक कतरा बहा दिया।

यहां मैं अपने पंजाबी भाइयों की प्रशंसा करना चाहता हूं, जो कठिन परिश्रम के साथ भारत की आजादी की रक्षा करने और सामूहिक विकास, शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत करने में शानदार योगदान दे रहे हैं। यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि जब भी हमारे देश की संप्रभुता को बाहरी या आंतरिक हमलों से खतरा हुआ, हमारे बहादुर पंजाबी देश की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए जान हथेली पर रखकर डट गए। उदाहरण के लिए, 1965 और 1971 की भारत-पाक युद्धों, कारगिल युद्ध, कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में घुसपैठ को रोकने में बहादुर पंजाबी सैनिकों ने हमेशा वीरता का प्रदर्शन किया है।

यह सत्य किसी से छिपा नहीं है कि राज्य के मेहनती किसानों ने देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे मेहनती किसानों ने देश को भोजन प्रदान करने के लिए राज्य के प्राकृतिक संसाधनों, जैसे उपजाऊ मिट्टी और पानी, का भी बलिदान दिया है।

लेकिन यह दुखद है कि आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद भगत सिंह व बाबा साहब डॉ. बी.आर. आंबेडकर जैसे महान राष्ट्रीय नायकों के सपने अभी भी अधूरे हैं।

वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनने के साथ पंजाब में बदलाव की हवा की गूंज सुनाई दी। हमारी सरकार ने न केवल राज्य के लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, बल्कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का भी संकल्प लिया।

हमने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक बुराइयों से मुक्त एक नया पंजाब सृजित करने का संकल्प लिया था और राज्य को तीव्र विकास के पथ पर डाल दिया है। पंजाब को विकास की तेज गति पर लाने के लिए 'आप' सरकार ने व्यापक नीतियां और कार्यक्रम तैयार कर साहसिक पहल की हैं, जिन्होंने हमें विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

पंजाबियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की पहली योजना है। यह योजना पंजाब के प्रत्येक परिवार के लिए 10 लाख रुपए तक का नकद रहित चिकित्सा उपचार प्रदान करती है।

'हिंद दी चादर' (मानवता के रक्षक) श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहादत दिवस के पवित्र अवसर को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाने के लिए ऐतिहासिक समारोह आयोजित किए जाएंगे। देश की एकता और अखंडता की रक्षा में सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और यहां तक कि अग्निवीर जवानों के अतुलनीय योगदान को मान्यता देते हुए राज्य सरकार, जवान के ड्यूटी के दौरान शहीद होने की स्थिति में परिवार को एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देती है। अब तक राज्य के युवाओं को 54,000 से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं। इससे पंजाब के युवा पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बने हैं।

राज्य सरकार ने 2022 में लोगों को मुफ्त बिजली देने की गारंटी की शुरुआत की थी और तब से पंजाब के 90 प्रतिशत घरों को बिजली मुफ्त मिल रही है और उनके बिजली बिल शून्य आ रहे हैं। जब मैंने पद संभाला था, तब राज्य में सिंचाई के लिए केवल 21 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था, जबकि अब 63 प्रतिशत नहरी पानी सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा है, जो गर्व की बात है।

पंजाब सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 'पंजाब शिक्षा क्रांति' की शुरुआत की है। इसके साथ ही राज्य सरकार 118 सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूलों को 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाओं और खेल मैदानों से लैस हैं।

लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने पंजाब भर में 881 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए हैं, जिससे राज्य के स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में क्रांति आई है। अब पंजाब में ऐसे 200 और क्लीनिक खोले जा रहे हैं, क्योंकि राज्य में रोजाना लगभग 70,000 मरीज इन क्लीनिकों का लाभ उठा रहे हैं।

पंजाब सरकार राज्य में निवेश और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

राजस्व विभाग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाने तथा जनसेवाओं को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने 'ईजी रजिस्ट्री' और 'ईजी जमा बंदी पोर्टल' शुरू किया है।

सीमा पार से नशों की आपूर्ति को रोकने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सीमावर्ती जिलों में एंटी ड्रोन सिस्टम-बाज आंख की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस सिस्टम को तैनात करने वाला पंजाब, देश का पहला राज्य बन गया है।

इस पवित्र अवसर पर आइए, हम पंजाब को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए स्वयं को पुन: समर्पित करें, जो गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक बुराइयों से मुक्त हो।

अंत में, मैं सभी पंजाबियों को न्योता देता हूं कि वे पंजाब को एक बार फिर समृद्ध और देश का अग्रणी राज्य बनाने के सफर में सक्रिय भूमिका निभाएं।

-जय हिंद

समृद्धि और आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हिमाचल प्रदेश

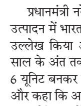

ठा. सुखविंदर सिंह सुक्खू

मुख्यमंत्री (हि.प्र.)

79वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की आजादी, एकता और अखंडता वर्षों के संघर्ष और वीर सपूतों के असंख्य बलिदानों का प्रतिफल है।

यह गर्व की बात है कि हिमाचल के वीर सपूतों ने 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और 23 कीर्ति चक्र जीते हैं। देश का पहला परमवीर चक्र, प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। इसके बाद, कर्नल डी.एस. थापा, कैप्टन विक्रम बतरा, तथा सूबेदार मेजर संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

वर्ष 2023 में गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना हमने अपने संसाधनों से सफलतापूर्वक किया। हमने आपदा के फौरन बाद युद्धस्तर पर राहत और पुनर्वास के कार्य शुरू किए तथा वर्ष 2023 की तरह इस बार भी आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसे 25 गुना तक बढ़ाया गया है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में राजनीतिक, आर्थिक और प्राकृतिक आपदा जैसी गम्भीर चुनौतियों का मजबूती से सामना किया है। हिमाचल के विकास और खुशहाली के लिए हमारी सरकार ने ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है। हमने दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी बहुमूल्य सुधार किए हैं। हिमाचल देश का पहला राज्य है जो दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रहा है। वर्तमान में लगभग 38,400 किसानों से प्रतिदिन औसतन 2.25 लाख लीटर गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। हमने डॉ. वाई.एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू कर पात्र विद्यार्थियों को देश-विदेश में शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत ब्याज़ पर 20 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत 32,000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है। पहली से आठवीं कक्षा के 5.35 लाख बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की पहल की गई है। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना शुरू की है जिसके पहले चरण में ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत उपदान का प्रावधान है। दूसरे चरण में निजी भूमि पर 100 से 500 किलोवॉट तक के सोलर पैनल लगाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। तीसरे चरण में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है।

महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देने के लिए हमने 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना शुरू कर 1500 रुपये मासिक सम्मान राशि देना आरंभ किया है। एक ऐतिहासिक पहल के तहत रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत शिमला स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पैशिलिटीज़ से की गई है। कैंसर मरीज़ों के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयों का प्रावधान किया गया है। हमीरपुर में उत्कृष्ट कैंसर अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। आईजीएमसी शिमला में नए कैंसर अस्पताल भवन और ट्रॉमा सेंटर की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। हमारी सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अनूठी पहल की है जिसके तहत मैं खुद और मेरे मंत्रिमण्डल के सहयोगी दूर-दराज क्षेत्रों में लोगों से मिलते हैं व उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करते हैं।

हम आपकी उम्मीदों के अनुसार और आपके सहयोग से अपने इस सुंदर पहाड़ी राज्य को विकास के नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अंत में, मैं एक बार पून: आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं तथा समस्त प्रदेशवासियों के सुखमय और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।

जय हिन्द, जय हिमाचल।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

पांच श्रेष्ठ घोषणाएं

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ऐतिहासिक और अनुकरणीय है। ऐतहासिक इसलिए कि लगातार 12वीं बार उन्होंने लाल किले से भाषण दिया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लाल किले से 17 बार देश को संबोधित करने का मौका मिला है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अब तक का सबसे लंबा, 103 मिनट का भाषण दिया है। यह भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण है। यह भाषण इसलिए अनुकरणीय है, क्योंकि इसमें जो घोषणाएं शामिल हैं, उनकी देश को बड़ी जरूरत है। विशेष रूप से सुदर्शन चक्र अभियान की घोषणा आज के समय में विशेष मायने रखती है। आज सीमाओं पर भारत की चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रतिकूल पड़ोसियों का यहां नाम लेना उचित नहीं है, पर इस देश का जन-जन जानता है कि देश की सुरक्षा को सतत सुनिश्चित रखना आवश्यक है। सुरक्षा के इस नए अभियान का नाम बहुत सोचकर सुदर्शन चक्र रखा गया है, इस चक्र को अमोघ माना जाता है और यह भी ध्यान देने की बात है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी इस बार स्वतंत्रता दिवस के ठीक अगले दिन पड़ रही है।

भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कवच के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सुदर्शन चक्र नामक एक मिशन शुरू करेगा। देश की सुरक्षा जरूरतों को आज हर कोई समझ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारी जो बढ़त रही, वह वास्तव में आधुनिक तकनीक का कमाल है। इस कमाल ने हमें मिसाइलों और घातक ड्रोन की बौछारों से बचाया है। भारत जिस प्रकार का देश है, उसे किसी पर प्रहार करने की क्षमता से ज्यादा ध्यान अपनी सुरक्षा के अत्याधुनिक इंतजामों पर देना चाहिए। अगर हमारे सुरक्षा इंतजामों ने किसी भी प्रकार के हमलों से हमें बचा लिया, तो इससे ज्यादा सुखद बात और कुछ न होगी। यह बहुत प्रशंसनीय है कि सुदर्शन चक्र अभियान भारत को आयरन डोम से लैस करेगा। यह हमें सीमाओं और सीमा के अंदर भी सुरक्षा देगा। लाल किले के प्राचीर से दूसरी अहम घोषणा जीएसटी सुधार से ताल्लुक रखती है। यह एक तरह से दिवाली उपहार की तरह है, महंगाई दर भले ही 1.55 हो गई है, पर बहुत लोगों को राहत का एहसास नहीं हुआ है। रोजमर्रा के उत्पादों पर जीएसटी को जब घटाया जाएगा, तब लोगों को राहत का एहसास होगा। कहना न होगा कि जीएसटी में कमी का लोगों को महीनों से इंतजार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले के प्राचीर से दिया गया 12वां भाषण इसलिए अनुकरणीय है, क्योंकि इसमें जो घोषणाएं शामिल हैं, उनकी देश को बड़ी जरूरत है।

तीसरी घोषणा उचित ही रोजगार को लेकर है। देश में रोजगार की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में, रोजगार योजना की घोषणा स्वागत-योग्य है। यदि यह योजना जमीन पर साकार हुई, तो देश में अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा हो सकती हैं। प्रधानमंत्री की चौथी घोषणा उच्च-स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने की है। सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध प्रवास से निजात पाना जरूरी हो गया है। भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और इसे अपनी भूमि पर किसी भी प्रकार के जनसांख्यिकीय असंतुलन से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री की पांचवीं घोषणा भी बहुत कारगर है। साल 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को दस गुना तक बढ़ा देना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 10 नए परमाणु रिएक्टरों पर काम चल रहा है। घोषणाएं और भी हैं, पर इन पांच विशेष घोषणाओं को अगर हमने साकार कर दिखाया, तो देश को बहुत मजबूती मिलेगी।

मन-जन को मार्ग दिखाते माधव

स्वामी चिदानन्द सरस्वती | आध्यात्मिक गुरु

यहां स्कैन करें

जीवन का रथ जब धर्म के सारथी के हाथों में हो, तो उसे कोई डिगा नहीं सकता। धर्म-रक्षा हथियारों से ही नहीं, करुणा, ज्ञान व कर्म के संतुलन से होती है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विशेष :

भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की अर्द्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र का वह क्षण कितना पावन था, जब मथुरा के कारागार में अंधकार और आतंक के बीच प्रकाश का अवतरण हुआ। चारों ओर कंस के अत्याचार, भय, अधर्म की गहराती हुई छाया थी, धर्म की नींव डगमगा रही थी, ऐसे में मानवता के सारथी ने जन्म लिया- *परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे !*

श्रीकृष्ण का जन्म एक युग-परिवर्तक के रूप में हुआ। बाल्यकाल से लेकर अंतिम क्षण तक उन्होंने इहलौकिक दुनिया को मानवता, प्रकृति, पर्यावरण, न्याय और प्रेम का मार्ग दिखाया, जो युगों-युगों से आज तक अमर है। गोकुल और वृंदावन की पावन गलियों में जो उन्होंने बाल-लीलाएं कीं, उन सबमें एक सार्वकालिक संदेश छिपा है। यमुना नदी का कालिय दमन केवल विषैले नाग पर विजय की कथा नहीं है, बल्कि वह प्रदूषित जल को शुद्ध करने का प्रतीक है। यमुना तो ब्रजवासियों के जीवन का आधार थी, उसका विषहरण यह स्मरण दिलाता है कि जल केवल संसाधन नहीं, जीवन का प्राण है और उसका संरक्षण प्रत्येक मानव का सर्वोच्च धर्म है।

गोवर्धन पूजा का प्रसंग भी गहन पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। देवराज इंद्र की पूजा के स्थान पर पर्वत, गौ और वन की पूजा करके श्रीकृष्ण ने यह संदेश दिया कि हमारी आस्था केवल देवताओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह प्रकृति भी पूज्य है। गोवर्धन पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, बल्कि जल, वनस्पति, पशु-पक्षियों और ग्रामवासियों के जीवन का स्रोत था। आज जब वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन हमें घेर रहे हैं, तब श्रीकृष्ण की उस शिक्षा और संदेश पर गौर करना और भी आवश्यक हो जाता है।

श्रीकृष्ण का जीवन सामाजिक न्याय की स्थापना का जीवंत उदाहरण है। कंस का अंत केवल एक अत्याचारी शासक का पतन नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश का संदेश था। सुदामा के साथ उनका मित्रत्व व्यवहार दर्शाता है कि सच्चा संबंध धन और पद से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से निर्धारित होता है। विदुर के घर भोजन करना, द्रौपदी की लाज की रक्षा करना, ग्वाल-बालों के साथ समान भाव से खेलना, ये सब उनके जीवन के वे प्रसंग हैं, जो समाज में समानता, नारी सम्मान और मानवीय करुणा के आदर्श स्थापित करते हैं।

वह वास्तव में रणभूमि के सारथी के साथ-साथ मानव जीवन के सारथी भी हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने अर्जुन के विचार, संकल्प और धर्मबोध को दिशा दी थी। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में अर्जुन का मोह, भ्रम और शोक देखकर उन्होंने जो *गीता* का उपदेश दिया, वह उपदेश समूची मानवता का शाश्वत मार्गदर्शक बन गया। *गीता* में उन्होंने उद्घोष किया, *कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,* अर्थात कर्म करना हमारा धर्म है, फल की चिंता हमें विचलित न करे। यह केवल युद्ध की परिस्थिति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होने वाला सिद्धांत है। *गीता* का कर्मयोग हमें कर्तव्य-पालन का मार्ग दिखाता है, भक्तियोग हमें ईश्वर से प्रेम का संदेश देता है, और ज्ञानयोग हमें आत्मबोध की ओर ले जाता है। यह त्रिवेणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी पांच हजार वर्ष पूर्व थी।

यदि आज के युग में श्रीकृष्ण अवतरित होते, तो निश्चत रूप से वह नदियों को बचाने के लिए जनआंदोलन का नेतृत्व करते। वृक्षारोपण को जन-उत्सव बनाते। गौ-सेवा और जैविक खेती को कृषि-क्रांति का आधार बनाते। वह युवाओं को केवल करियर नहीं, बल्कि चरित्र-निर्माण का मार्ग सिखाते। राजनीति में धर्म और सेवा को पुनर्स्थापित करते, और अर्थव्यवस्था में नैतिकता और पर्यावरणीय संतुलन का समावेश कराते। इसलिए श्रीकृष्ण का नाम और उनका स्मरण मन और शरीर, दोनों के लिए अमृत है। रासलीला में संगीत, नृत्य और भक्ति का संगम केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह जीवन में उत्साह, सृजनात्मकता और सामंजस्य का प्रतीक है।

श्रीकृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का रथ जब धर्म के सारथी के हाथों में होता है, तब उसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। वह स्मरण दिलाते हैं कि धर्म की रक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि करुणा, ज्ञान और कर्म के संतुलन से होती है। आज जब यह पृथ्वी प्रदूषण और संघर्ष की आग में झुलस रही है, तब श्रीकृष्ण का बहुआयामी सारथ्य, मानवता, प्रकृति और पर्यावरण के रक्षक के रूप में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि हम उनके जीवन के आदर्शों को अपनाएं, तो हम न केवल स्वयं का उत्थान करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और सुंदर संसार छोड़कर जाएंगे।

श्रीकृष्ण केवल रणभूमि के नायक नहीं हैं, बल्कि वह प्रेम, करुणा और सत्य के पथ-प्रदर्शक हैं। वह संपूर्ण मानवता के दीपक हैं, प्रकृति के रक्षक हैं, और पर्यावरण के संतुलन के दूत हैं। युग चाहे कोई भी हो, जब भी जीवन का रथ डगमगाने लगे, तो कृष्ण का सारथ्य ही हमें विजय और शांति की ओर ले जाता है। जब भी हम यशोदा-नंदन का नाम सुनते हैं, तो मन में कई भावचित्र एक साथ उभरते हैं- बांसुरी बजाते मुरलीधर, माखन चुराते नटखट कन्हैया, गायों को चराते गोपाल, रास रचाते माधव, और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी, परंतु यदि हम केवल श्रीकृष्ण को युद्धभूमि के योद्धा के रूप में देखें, तो यह उनके विराट व्यक्तित्व का केवल एक अंश है।

श्रीकृष्ण जीवन के सारथी हैं, हमारे विचारों, निर्णयों, भावनाओं और कर्मों के मार्गदर्शक हैं। उनका जीवन केवल गाथा नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक अमर दिशा-सूचक है, जिसमें हरेक युग के लिए शिक्षा, प्रेरणा और समाधान निहित हैं। उनका जन्म अन्याय और अधर्म से घिरे समय में हुआ, और उन्होंने अपने कर्म, ज्ञान और करुणा से समाज में नई चेतना का संचार किया। आज जब दुनिया स्वार्थ, भौतिकवाद और पर्यावरण संकट से जूझ रही है, तब श्रीकृष्ण का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि धर्म, सत्य, करुणा और प्रकृति-प्रेम ही वह मार्ग है, जो मानवता को संतुलन, शांति और स्थायी सुख की ओर ले जा सकता है।

इसलिए आज आह्वान कीजिए, माधव फिर आ जाओ, दुनिया की पददलित मानवता तुम्हें जगह-जगह से पुकार रही।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सूफी संतों से फिल्म शोले तक भारत और ईरान का रिश्ता

नगमा सहर | वरिष्ठ टीवी पत्रकार

यहां स्कैन करें

कल, जब *शोले* के पचास बरस पूरे हुए, तो सबने इसके जादू को याद किया, लेकिन जब ईरानी दूतावास ने एक्स पर *शोले* को याद किया, तो वह बेहद खास एहसास दे गया। ईरानी दूतावास ने अपनी पोस्ट में कहा, '*शोले* के पचास साल, ईरान को अब भी याद है।' सबको याद है कि इस फिल्म का जादू ईरान में ऐसे सिर चढ़कर बोल रहा था कि गब्बर सिंह वहां जब्बार सिंह बन गए और मशहूर ईरानी एक्टर नाविद मोहम्मदजादेह ने गब्बर के किरदार को अपने रोल में ढाला था।

यह एक्स पोस्ट महज एक टिप्पणी नहीं है, यह ईरान और हिन्दुस्तान के गहरे तहजीबी रिश्तों की याद दिलाती है। वह रिश्ता, जो हिन्दुस्तान की सरजमीन पर सूफी दरवेशों की आमद से लेकर संगीत और दम पुख्त व बिरयानी के जायके से होते हुए चाबहार बंदरगाह तक पहुंचता है। भारत और ईरान के कारोबारी और सांस्कृतिक संबंध सैकड़ों साल पुराने हैं। हिन्दुस्तान में सूफी सिलसिला ईरान के सूफी संतों के जरिये फैला और फला-फूला। ख्वाजा मोइनउद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला शुरू किया, अजमेर में बसे, जहां ख्वाजा साहब की दरगाह पर आज भी सभी मजहबों के लाखों लोग अपनी दुआओं के साथ पहुंचते हैं। ख्वाजा मोइनउद्दीन चिश्ती के अलावा मीर अली हमदानी ने कश्मीर में 'पर्शियन कल्चर' फैलाया, तो अमीर खुसरो ने यहां के संगीत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। मकबूल सूफी संत मखदूम अशरफ 13वीं सदी में ईरान से भारत आए और फिर यहीं बस गए। लखनऊ के पास कायम उनकी मजार भारत और ईरान की साझा तहजीब की गवाह है। मखदूम अशरफ ने चिश्ती और कादरी सिलसिले को भारत में आगे बढ़ाया था।

शोले का जादू ईरान में ऐसे सिर चढ़कर बोल रहा था कि ईरानी एक्टर नाविद मोहम्मदजादेह ने गब्बर के किरदार को अपने रोल में ढाला था।

गौर कीजिए, सन् 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के जनक रूहोल्लाह खोमेनी यूपी के बाराबंकी के रहने वाले थे। खोमेनी के पूर्वज 1830 ईस्वी में इराक के नजफ चले गए और फिर ईरान के खोमेन में जा बसे। दोनों मुल्कों के लोगों के घुलने-मिलने का सिलसिला भाषा और खान-पान में ऐसा घुला, जैसे दूध में शक्कर। मुगलों के दरबार में शाही खाने पर ईरान के मसालों और जायके का खूब असर था। वहीं से धीमी आंच पर दम पुख्त होने का सलीका आया, पिस्ता, बादाम जैसे मेवे व जाफरान का इस्तेमाल आया और बिरयानी भी। कबाब और नान की जड़ें भी ईरान में ही हैं।

करीब 532 ईस्वी पूर्व जब फारस के बादशाह डेरियस (दारा) ने पश्चिमोत्तर भारत को अपने कब्जे में लिया, तो अपने साथ वह अनार, पिस्ता, बादाम व गुलाब जल लेकर आए और यहां उनका परिचय हुआ चावल से, जो बाद में ईरानी दस्तरख्वान का जरूरी हिस्सा बन गया। मुगल दरबार में लगभग 600 साल तक फारसी दरबार की जुबान रही। हिंदी और फारसी का मिला-जुला रूप ही उर्दू है। ऐसे अनेक शब्द हैं, जो हिन्दुस्तानी भाषा में यूं समा गए हैं कि लगता ही नहीं, उनकी जड़ें फारसी में हैं। जैसे, सब्ज, यानी हरा फारसी का लफ्ज है और इसी से सब्जी शब्द बना, यानी हरी तरकारी। नाश्ता, मेहरबान, बाजार, होशियार, बाग, दरवाजा, परेशान ऐसे कई शब्द हैं, जिनकी जड़ें फारसी में हैं।

इसी तरह, खुदा शब्द भी फारसी है। हिन्दुस्तान के मुसलमान कुछ साल पहले तक विदा होते वक्त 'खुदा हाफिज' का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। अब इसकी जगह अरबी असर में 'अल्लाह हाफिज' ने ले ली। यहां पहले ईरान की संस्कृति का असर अरब से ज्यादा था। हमारी सीमाएं भी पास थीं, पर पिछले एक दशक में अरब देशों से बढ़ती करीबी के असर में खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज होता चला गया।

एक और चीज, जो नई दिल्ली और तेहरान के गहरे ताल्लुकात की मिसाल है, वह है चाबहार बंदरगाह। इस बंदरगाह के जरिये पाकिस्तान को दरगुजर करते हुए हिन्दुस्तान को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा रास्ता मिलता है। भू-राजनीतिक मजबूरियों और विदेश नीति में सामयिक संतुलन बनाए रखने के कारण भारत और ईरान के आर्थिक-राजनीतिक संबंध अभी सीमित हैं, क्योंकि यह इजरायल और अमेरिका के साथ हमारे संबंधों के आड़े आता है, मगर तहजीबी रिश्ते ऐसी मजबूरियां कहां देखते हैं! ईरानी दूतावास का *शोले* प्रेम इसकी मुनादी करता है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले

17 अगस्त, 1950

आजादी की जिम्मेदारी

हमारी आजादी की तीसरी वर्षगांठ आई और चली गई। हर साल की तरह धूमधाम और दूसरे सब रस्म-रिवाज इस साल भी हुए, परन्तु इस साल वातावरण में एक गंभीरता मालूम पड़ती थी। इस अवसर पर हुए भाषणों में भी आनन्द और उमंग के बजाय कर्तव्य-पालन की प्रेरणा की ही झांकी अधिक मिली। इसे यथार्थ की प्रतीति ही समझना चाहिए, और इससे हतोत्साह होने के बजाय इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि मृग-मरीचिका में हम नहीं पड़े हुए हैं, बल्कि प्रस्तुत कठिनाइयों का हमें भान है...।

स्वतन्त्रता दिवस पर दो मुख्य भाषण राष्ट्र ने सुने। एक प्रातःकाल ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय पताका लहराते हुए प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का, दूसरा सायंकाल रेडियो पर राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का। दोनों भाषणों का ढंग भिन्न होते हुए भी सार एक ही था कि आजादी के साथ जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आई है, जिसका हमने खयाल न किया तो आजादी का सुखोपभोग हम नहीं कर सकते। नेहरूजी के भाषण में व्यथा, आवेग, आश्वासन और चेतावनी का सम्मिश्रण उनके हृदय में सुलग रही देशहित की आग का निदर्शक है। आज की स्थिति पर उन्हें संतोष नहीं। अन्न की कमी, चीजों की महंगाई और शरणार्थियों की दुरवस्था उन्हें कचोट रही है। यह देखकर उनका सन्तुलन जवाब देता हुआ मालूम पड़ता है कि हमारे ही देशवासी अपनी आर्थिक-समृद्धि या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की हीन भावनाओं से स्थिति को कठिन से कठिनतर और जटिल से जटिलतर बना रहे हैं। आजादी की नींव पर ही कुठाराघात करने वाले इस दुष्कृत्य से उन्हें विरत करने के लिए नेहरूजी ने समझाने से लेकर धमकी तक का सहारा लिया है, जिसे कुछ लोग उनका पदाभिमान भी कह सकते हैं। परन्तु नेहरूजी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमेशा सत्तारूढ़ बने रहने की उनकी इच्छा है, न यह संभव ही है; सरकार की आलोचना करने तथा उसे पलट देने का लोगों को पूरा हक हैं; परन्तु सरकार की आलोचना और उसे उलटना एक बात है तथा ऐसी बातें करना जिनसे आजादी की नींव पर ही कुठाराघात हो बिलकुल दूसरी; और जबतक उनके हाथ में शासन है, ऐसी बातों का उन्हें मुकाबला करना ही होगा जो आजादी की नींव पर ही कुठाराघात करती हैं।

मनसा वाचा कर्मणा

गीता सा उपदेश कहां

मेरा शरीर मां के दूध पर जितना पला है, उससे कहीं अधिक मेरा हृदय और बुद्धि, दोनों *गीता* के दूध से पोषित हुए हैं। जहां हार्दिक संबंध होता है, वहां तर्क की गुंजाइश नहीं रहती। तर्क को काटकर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो पंखों से ही मैं *गीता*-गगन में यथाशक्ति उड़ान भरता रहता हूं। *गीता* महाभारत के मध्य भाग में एक ऊंचे दीपक की तरह स्थित है, जिसका प्रकाश सारे महाभारत पर पड़ रहा है। एक ओर छह पर्व और दूसरी ओर बारह पर्व, इनके मध्य भाग में, उसी तरह एक ओर सात अक्षौहिणी सेना और दूसरी ओर ग्यारह अक्षौहिणी, इनके भी मध्य में *गीता* का उपदेश दिया जा रहा है।

महाभारत और *रामायण* हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं। उनमें वर्णित व्यक्ति हमारे जीवन में एकरूप हो गए हैं। राम, सीता, धर्मराज, द्रौपदी, भीष्म, हनुमान आदि के चरित्रों ने सारे भारतीय जीवन को हजारों वर्षों से मंत्रमुग्ध-सा कर रखा है। संसार के अन्यान्य महाकाव्यों के पात्र इस तरह लोक-जीवनमें घुले-मिले नहीं दिखाई देते।

यह तो सभी जानते हैं कि गीता श्रीकृष्ण ने कही। उस महान सिखावन को सुनने वाला भक्त अर्जुन इस सिखावन से इतना समरस हो गया कि उसे भी 'कृष्ण' संज्ञा मिल गई। भगवान और भक्त की यह हृदयता प्रकट करते हुए व्यासदेव इतने एकरस हो गए कि लोग उन्हें भी 'कृष्ण' नाम से जानने लगे। कहने वाला कृष्ण, सुनने वाला कृष्ण, रचने वाला कृष्ण, इस तरह इन तीनों में मानो अद्वैत उत्पन्न हो गया, मानो तीनों की समाधि लग गई। *गीता* के अभ्यासी को ऐसी ही एकाग्रता चाहिए।...

अर्जुन को स्वधर्म विगुण मालूम होने लगा, तो श्रीकृष्ण ने उन्होंने ज्ञान दिया। दूसरे का धर्म भले ही श्रेष्ठ मालूम हो, उसे ग्रहण करने में मेरा कल्याण नहीं है। सूर्य का प्रकाश मुझे प्रिय है। सूर्य मुझे वंदनीय भी है। परंतु इसलिए यदि मैं पृथ्वी पर रहना छोड़कर उनके पास जाना चाहूंगा, तो जलकर खाक हो जाऊंगा। मछलियों से यदि कोई कहे कि पानी से दूध कीमती है, तुम दूध में रहने चलो, तो क्या मछलियां उसे मंजूर करेंगी? मछलियां तो पानी में ही जी सकती हैं, दूध में मर जाएंगी।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

दूसरे का धर्म सरल मालूम हो, तब भी उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत बार सरलता आभास मात्र ही होती है। घर-गृहस्थी में बाल-बच्चों की ठीक संभाल नहीं की जाती, इसलिए ऊबकर यदि कोई गृहस्थ संन्यास ले ले, तो वह ढोंग होगा। मौका पाते ही उसकी वासनाएं जोर पकड़ेंगी। संसार का बोझ उठाया नहीं जाता, इसलिए जंगल में जाने वाला पहले वहां छोटी-सी कुटिया बनाएगा। फिर उसकी रक्षा के लिए बाड़ लगाएगा। ऐसा करते-करते वहां भी संसार खड़ा करने की नौबत आ जाएगी। यदि सचमुच मन में वैराग्य-वृत्ति हो, तो फिर संन्यास भी कौन कठिन बात है?

अर्जुन को स्वधर्म विगुण मालूम होने लगा, तो श्रीकृष्ण ने उन्होंने ज्ञान दिया। दूसरे का धर्म भले ही श्रेष्ठ मालूम हो, उसे ग्रहण करने में मेरा कल्याण नहीं है।

आचार्य विनोबा भावे

गैरी कॉस्पोरोव | पूर्व विश्व चैंपियन, शतरंज

व्लादिमीर पुतिन ताकतवर से दबते हैं और कमजोर को दबाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति आक्रांता रूस को दबाने के बजाय पीड़ित यूक्रेन को ही दबा रहे हैं। ऐसे में, रूस अपने हमले बढ़ाएगा ही।

अनुलोम-विलोम
विकसित भारत- 2047

विकसित बनने की ओर बढ़ता भारत

भारत ने 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने तक देश को विकसित बना लेने का संकल्प ले रखा है। अनेक क्षेत्र में विकास की बयार बह रही है। पिछले कुछ सालों में ही इसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जगह बनाते हुए चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। इसकी गति निरंतर बनी हुई है और अब जर्मनी को पछाड़कर तीसरे पर काबिज होने के लिए कुलांचे भर रहा है। वह दिन दूर नहीं, जब आप और हम गर्व से कह सकेंगे कि हमारा देश भी सर्वोच्च अर्थव्यवस्थाओं की तिकड़ी में शामिल हो गया है।

इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह एक व्यापक विजन योजना है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना है। विकसित भारत के चार स्तंभ- युवा, गरीब, महिला और किसान हैं। इसके लिए आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा, पर्यावरणीय स्थिरता, औद्योगिक आधुनिकीकरण और सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान विकास गतिविधियों के अलावा भविष्य में भी व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है।

भारत ने सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए 7-8 प्रतिशत वार्षिक जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा है। देश के नीति आयोग के अनुसार, हमारी जीडीपी 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। दूसरा कदम सामाजिक समता की दिशा में है। इसके तहत गरीबी उन्मूलन, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास चल रहे हैं। तीसरे कदम के रूप में औद्योगिक आधुनिकीकरण है, जिसके तहत 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत योगदान करने के लिए विनिर्माण को बढ़ावा देना एक प्रमुख लक्ष्य है। चौथे में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर आगे निकलना है। इसमें पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान विकास में तीव्रता लाने के लिए सभी क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया पहल, फिनटेक अपनाने, ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल सेवाओं जैसे बुनियादी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। पांचवें कदम में पर्यावरण क्षेत्र पर नजर है। भारत ने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन इंडिया मिशन जैसी पहल नवीकरणीय ऊर्जा और सतत शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इन पहलों पर दृढ़ता से काम कर देश जरूर विकसित देशों की पांत में खड़ा हो सकेगा, जिसका हम सबको इंतजार है।

रवि रंजन कुमार, टिप्पणीकार

इस लक्ष्य को पाना अभी आसान नहीं

हमारे देश ने आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बन जाने का लक्ष्य बना रखा है। लेकिन जिस रफ्तार से हमारा विकास हो रहा है, उससे इतनी कम अवधि में इस लक्ष्य को प्राप्त करना टेढ़ी खीर लगता है। वैसे तो इस लक्ष्य को पाने में अनेकानेक चुनौतियां सामने हैं, लेकिन इसका अंदाजा हम पांच चुनौतियों से ही लगा सकते हैं। देश में आर्थिक विषमताएं, बुनियादी ढांचे में कमी, नीति अनिश्चितता, पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं, कौशल विकास, ग्रामीण युवा व वैश्विक खतरे जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।

इसे विस्तार से देखें तो भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है, जो आर्थिक असमानता को बढ़ाती ही जा रही है। इससे सामाजिक अशांति और विकास में बाधा आ सकती है। इस खाई को पाटना तो दूर, कम करने की दिशा में भी काम होता नहीं दिख रहा है। नतीजतन, यह लगातार सामाजिक विषमता को भी बढ़ा रही है, जिससे समाज में कई स्तरों पर तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। दूसरे देश में बुनियादी ढांचे में भारी कमी देखी जा रही है। सड़क, बिजली, पानी, और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी विकास की राह में एक बड़ी बाधा है। जो बिजली, पानी, परिवहन की सेवाएं उपलब्ध भी हैं तो उन्हें सरकारों द्वारा अपनी साख बचाने के लिए मुफ्त में बांटी जा रही है। तीसरी बाधा नीतिगत अनिश्चितता है। देश में नियमों और नीतियों में लगातार बदलाव से निवेशकों का भरोसा कम होता है और विकास धीमा हो जाता है। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका दुष्प्रभाव दिख भी रहा है। चौथे स्तर पर पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं। जलवायु परिवर्तन समेत अनेक प्रकार के प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याएं भारत के विकास के लिए खतरा हैं। पांचवें, कौशल विकास की दिशा में गति का काफी मंथर होना बड़ी बाधा है। भारत की युवा आबादी को आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि वे बेहतर रोजगार पा सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार को एक समावेशी और टिकाऊ विकास रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसमें सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों, कौशल विकास, निर्यात को बढ़ावा देने, ग्रामीण विकास एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जो फिलहाल तो बहुत दूर की कौड़ी ही लगती है।

गोपी मिश्र, सामाजिक कार्यकर्ता

संपादकीय जागरण

शनिवार, 16 अगस्त, 2025 : भाद्रपद कृष्ण - 8 वि. 2082

स्वतंत्रता सुख और शांति की जननी है

आत्मनिर्भरता का उद्घोष

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री के संबोधन की प्रतीक्षा रहती ही है। इस बार अधिक थी, क्योंकि देश घरेलू और बाहरी मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना करने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खुली धमकियों का भी सामना कर रहा है। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन चुनौतियों से पार पाने का संकल्प व्यक्त कर उनसे निपटने के उपाय भी बताए और इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इन घोषणाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत संकटकाल में अपनी शक्ति को पहचान रहा है और हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। इसका संकेत आतंक के आका और भारत के शत्रु पाकिस्तान से स्थगित सिंधु जल समझौते के संदर्भ में खून और पानी साथ नहीं बहने, दीवाली पर जीएसटी का नया स्वरूप लाने, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने, अपना फाइटर जेट बनाने, सेमीकंडक्टर निर्माण में अग्रणी बनने समेत अन्य अनेक घोषणाओं से मिलता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ कदम उठाने की भी है। पीएम के संबोधन में आपरेशन सिंदूर की विशेष चर्चा आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य ही थी।

लाल किले से प्रधानमंत्री के लंबे संबोधन का सार यही है कि भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए कमर कस चुका है। यदि प्रधानमंत्री की घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए किसी को सबसे अधिक सक्रियता दिखानी होगी तो वह है नौकरशाही। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सत्तारूढ़ नेता तमाम घोषणाएं करते हैं, लेकिन नौकरशाही उनके अनुरूप पूरी इच्छाशक्ति और ईमानदारी नहीं दिखाती। यह किसी से छिपा नहीं कि जहां कई घोषणाओं पर एक हद तक अमल हुआ है और उनका लाभ भी मिला है, वहीं कई योजनाएं आधी-अधूरी ही हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो कुछ कहा और जो योजनाएं शुरू करने की घोषणा की, यदि उन पर 60-70 प्रतिशत भी क्रियान्वयन हो सके तो देश के आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनने का रास्ता आसान हो जाएगा और ट्रंप सरीखे मतलबी नेताओं को सही तरह जवाब भी दिया जा सकेगा। ट्रंप भारत को अपना मित्र देश बताते हैं, लेकिन वे उसे धमकाने में भी लगे हैं। चूंकि वे अपनी हद पार कर गए हैं, इसलिए उनकी धमकियों के आगे झुकने का प्रश्न ही नहीं। यह संदेश मोदी सरकार के साथ-साथ देश को भी देना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इससे बच रहे हैं। यह तो राजनीतिक क्षुद्रता ही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर लाल किले पर आयोजित समारोह का बहिष्कार किया। ऐसा तो लोग मोहल्ला समितियों के समारोह में भी नहीं करते।

आपसी सहयोग जरूरी

स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यमुना की सफाई का संकल्प दोहराया है। उनका यह कहना सही है कि यमुना को स्वच्छ व अविरल बनाने का काम दिल्ली की आत्मा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। यह नदी दिल्ली की पहचान है। इससे दिल्लीवासियों की प्यास बुझती है। इसके बाद भी हम लोगों ने इसकी पवित्रता का ध्यान नहीं रखा। लापरवाही व स्वार्थ की वजह से यह गंदे नाले में परिवर्तित हो गई। दिल्ली में लगभग 22 किमी के हिस्से में यह सबसे अधिक प्रदूषित है। इसका मुख्य कारण यहां के नालों के माध्यम से नदी में गिरने वाला गंदा पानी है।

> यमुना को स्वच्छ व अविरल बनाने के लिए केंद्र के साथ ही दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश को मिलकर काम करना होगा

हरियाणा व उत्तर प्रदेश के शहरों की गंदगी व औद्योगिक इकाइयों का अपशिष्ट नदी में गिर रहा है। यमुना की सफाई को लेकर पिछले कई वर्षों से राजनीति हो रही है। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा बना था। चुनावी वादे के अनुसार सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। इससे नदी के साफ होने की उम्मीद बंधी है। यमुना को स्वच्छ व अविरल बनाने के लिए केंद्र के साथ ही दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश को मिलकर काम करना होगा। पिछले माह गृहमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भी इस बात पर जोर दिया गया है। संबंधित राज्यों को मिलकर नदी में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के साथ ही पर्यावरणीय प्रवाह बढ़ाने के लिए काम करना होगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या भारत ट्रंप की टैरिफ नीति का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में सक्षम दिख रहा है?

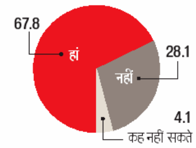

आज का सवाल

क्या लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आर्थिक सुधारों के नए दौर की शुरुआत का परिचायक है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

ट्रंप की धमकी को धता बताए भारत

आदित्य सिन्हा

ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य तत्व है। दबाव में अमेरिका से समझौता भविष्य के किसी संकट से निपटने की भारत की क्षमताओं को कमजोर करेगा

यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत रियायती दरों पर रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है। इसने भारत को बड़ी आर्थिक बढ़त दिलाई है। भारत जिस ब्रेंट क्रूड के अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर तेल की खरीद करता आया है, उससे कहीं कम कीमत पर वह रूस से रोजाना 17 से 19 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। इससे भारत के लिए घरेलू ईंधन कीमतों को नियंत्रण में रखने, महंगाई पर लगाम लगाने और विकास के लिए राजकोषीय गुंजाइश बढ़ाने में मदद मिली है। यह कोई अवसरवादी नीति नहीं, बल्कि अस्थिर वैश्विक बाजार में राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक सुनियोजित कदम है। भारत को हो रहा यह लाभ अमेरिका को खटक रहा है। इसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ के 25 प्रतिशत अतिरिक्त हर्जाना लगाने की भी घोषणा की है। यह 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त है। ट्रंप की भारत पर हर्जाना लगाने के पीछे की दलील बेमानी दिखती है, क्योंकि रूसी तेल खरीदने को लेकर तो वे भारत पर ऊंचे टैरिफ और हर्जाना लगाते हैं, लेकिन मास्को से सर्वाधिक मात्रा में तेल खरीद रहे चीन को अनदेखा कर देते हैं। इस मामले में भारत को जिस प्रकार निशाना बनाया जा रहा है, उससे यह केवल एक वाणिज्यिक विवाद न रहकर हमारे संप्रभु नीति निर्माण को भी चुनौती देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव तब बना रहे हैं, जब उनका दावा है कि रूस के साथ उनकी बात सही दिशा में जा रही है। भारत को उनके द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद तेल की कीमतों से लेकर अमेरिकी बाजारों तक में हलचल देखने को मिली है। ऐसी परिस्थितियों में भारत द्वारा तेल खरीद के फैसले का राजनीतिकरण व्यापक ऊर्जा स्थिरता के परिदृश्य को चोट पहुंचा सकता है। वैसे भी यह रुख-रवैया अपनी सुविधा के अनुसार अपनाया जा रहा है। यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब डालर का व्यापार किया। जबकि 2024 में ही यूरोप ने रूस से रिकार्ड मात्रा में 1.65 करोड़ टन एलएनजी आयात की। इससे नई दिल्ली में यही धारणा मजबूत हो रही है कि भारत को राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है, जबकि पश्चिमी सहयोगियों को अमेरिका ने छूट दे रखी है।

देखा जाए तो रूसी तेल खरीदकर भारत ने केवल अपनी अर्थव्यवस्था को ही फायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि वैश्विक मुद्रास्फीतिक दबाव को भी नियंत्रित रखने में सहायक बना है। भारत रूसी तेल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा खपा रहा है। यदि भारत ऐसा नहीं करता तो लाजिस्टिक्स एवं अन्य बढ़ी हुई लागतों के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती थी। दुनिया पहले से ही ऊर्जा, खाद्य और परिवहन के स्तर पर महंगाई से परेशान है, तब भारत द्वारा रूसी आयात के अभाव में इस परेशानी में और बढ़ोतरी होना तय था। वैश्विक हालात बद से बदतर होते जाते।

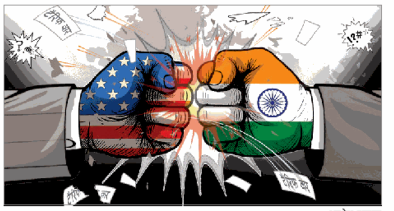

अवधेश राजपूत

घरेलू मोर्चे पर भी रूसी आयात घटाने का अर्थ होगा महंगी पश्चिमी एशियाई आपूर्ति बढ़ाना, ढुलाई की ऊंची लागत झेलना और रिफाइनरियों में इस नई खेप को शोधित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करना। इसका परिणाम या तो उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की ऊंची कीमतों के रूप में निकलेगा या फिर सरकार को तेल सब्सिडी बढ़ानी होगी, जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च के लिए उसकी राजकोषीय गुंजाइश घटेगी। इस मुद्दे से जुड़े राजनीतिक पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताता है और चीन की एक काट के रूप में देखता है। क्या कोई अपने रणनीतिक साझेदार को टैरिफ लगाने-बढ़ाने की धमकियां देता है और उसकी ऊर्जा नीति को लेकर सार्वजनिक प्रलाप करता है। इस तरह के आक्रामक कदम रक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग में दशकों के बने भरोसे पर आघात करते हैं। इससे वाशिंगटन के साथ भावी सक्रियता को लेकर भी भारत और सतर्कता बरतेगा, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में आ रही तेजी निस्तेज पड़ेगी।

इतिहास साक्षी है कि भारत ने सदैव अपनी विदेश नीति स्वायत्तता की रक्षा की है। महाशक्तियों के दबाव वाले दौर में भी भारत झुका नहीं। विदेश नीति में भारत का यह स्वतंत्र रवैया यूक्रेन युद्ध में भी रेखांकित हुआ, जब पश्चिमी देशों द्वारा उकसावे के बावजूद भारत अपने रुख पर अडिग रहा। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने यह उल्लेख भी किया कि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में प्रत्येक देश अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि पारंपरिक खाड़ी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यूरोप का रुख किए जाने से उपजी परिस्थितियों में ही रूस से आयात बढ़ा और अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देश किस तरह खुद रूस से ऊर्जा खरीदारी कर इस मामले में दोहरे रवैये का परिचय दे रहे हैं।

यदि वर्तमान परिस्थितियों में भारत और चीन रूसी तेल का आयात बंद कर दें तो कच्चे तेल की कीमतों में एकाएक 20 डालर प्रति बैरल तक की बढ़ोतरी संभव है। विश्व लंबे समय तक ऊंची कीमतों के दौर को झेलने के साथ आपूर्ति में भी गतिरोध झेलने को विवश होगा। सस्ते रूसी तेल के केवल वाणिज्यिक लाभ ही नहीं, बल्कि यह भारत के वृहद आर्थिक स्थायित्व का भी एक मजबूत स्तंभ है, जो वैश्विक बाजार को भी संतुलन प्रदान कर रहा है। किसी तरह के राजनीतिक दबाव में इससे किनारा करना आर्थिक दृढ़ता और रणनीतिक स्वायत्तता दोनों को क्षति पहुंचाएगा।

जब वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य अस्थिरता एवं अनिश्चितता से जूझ रहा है और ओपेक प्लस देश आपूर्ति में संभावित समायोजन के संकेत दे रहे हैं और बाजार कूटनीतिक घटनाक्रमों से प्रभावित हो रहे हैं, तब भारत को अपने आर्थिक एवं रणनीतिक लचीलेपन को हर हाल में कायम रखना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य तत्व है और किसी तरह के दबाव में उससे समझौता भविष्य के किसी संकट से निपटने की भारत की क्षमताओं को कमजोर करेगा। ऊर्जा नीति में स्वतंत्र रुख-रवैया घरेलू स्थायित्व को सुरक्षा कवच प्रदान करने के साथ ही अमेरिका-भारत संबंधों की दूरगामी सेहत के भी अनुकूल होगा।

(लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

पूंजी के खेल का शिकार बनता मनुष्य

क्षमा शर्मा

पैसे कमाने के लिए कंपनियां लोगों की चाहत को भुनाने और उन्हें सब्जबाग दिखाने का धंधा कर रही हैं

विज्ञान की दुनिया बेशुमार चमत्कारों से भरी है, लेकिन ये चमत्कार किसी परी या बौने की जादुई छड़ी से न होकर विज्ञान आधारित नियमों के अनुसार ही होते हैं। हाल में अमेरिका में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया, जिसे तीस साल पहले सुरक्षित भ्रूण से दुनिया में लाया गया है। इसे दुनिया का सबसे बूढ़ा बच्चा बताया जा रहा है। इसी तरह दुनिया से गायब वुली वोल्फ की वापसी हो चुकी है। डोडो और डायनासोर के बारे में भी कहा जा रहा है कि एक बार वे फिर धरती पर विचरेंगे। विशालकाय हाथी मैमथ को भी वापस लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत-सी लुप्त प्रजातियों की वापसी चकित करती है। क्लोनिंग के जरिए जन्मी डाली भेड़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक व्यक्ति ने भी लाखों डालर खर्च करके अपने मृत डागी का क्लोन बनवाया था। विज्ञान के जरिए ही मनुष्य चांद तक पहुंचा। अब मंगल ग्रह पर जाने की सोच रहा है। विज्ञान ऐसी तमाम बातों को भी खोजने की कोशिश कर चुका है, जिनमें सफलता नहीं मिली। जैसे कि रसायनशास्त्र के विकास के बारे में कहा जाता है कि उसका विकास अमृत और सोने की खोज के बारे में हुआ। अमृत भारतीय मनीषा में भी बहुत जगह बनाता है। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान यह निकला भी था और देवताओं और दानवों में इसके अधिकार के लिए युद्ध हुआ था।

मनुष्य मृत्यु से बहुत डरता है। वह हमेशा जीवित रहना चाहता है। चिकित्सा विज्ञान ने उसे अब लंबी आयु भी प्रदान की है, लेकिन मृत्यु पर विजय अभी तक नहीं पाई जा सकी है। स्पेन के एक गांव में लोगों से कहा जाता है कि उन्हें मरना नहीं है। इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहें। एक ऐसी कथा भी है कि एक राजा ने अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। फिर वह ऐसे स्थान पर पहुंचा, जहां लोग अमर थे। वे जीवन से ऊब चुके थे। मरना चाहते थे, लेकिन मर नहीं सकते थे। यह दुनिया विविध विचारों से भरी हुई है। अभी पिछले दिनों खबर आई कि जर्मनी की एक बायो लैब शवों को सुरक्षित करना चाहती है, ताकि भविष्य में यदि विज्ञान का इतना विकास हो जाए कि मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सके, तो इन्हें फिर से जीवित किया जा सकेगा। यह लैब इसके लिए दो लाख डालर लेगी। अब तक छह सौ से अधिक लोगों ने उसके यहां बुकिंग कराई है। इसे क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम दिया गया है। इस प्रक्रिया के बारे में लैब ने बताया है कि मृत्यु के बाद शरीर को बेहद ठंडे तापमान पर सुरक्षित किया जाएगा, ताकि शरीर के ऊतकों को कोई नुकसान न पहुंचे और वापस वे जीवित किए जा सकें। बायो लैब का कहना है कि उसे व्यक्ति के इस दुनिया से जाने के बाद फौरन सूचना मिलनी चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में देरी ठीक नहीं होगी। यह दुनिया की पहली ऐसी लैब बताई जा रही है। जल्दी ही यह लैब अमेरिका में भी अपना काम शुरू करने वाली है।

लोगों में अमरता की बढ़ती चाहत ● प्रतीकात्मक

यह भी कहा जा रहा है कि मृत दिमाग को दोबारा से काम के योग्य बनाना असंभव है, क्योंकि दिमाग की संरचना बहुत जटिल होती है। इसे अब तक समझा नहीं जा सका है। मान लीजिए ये लोग पांच सौ साल बाद जीवित हो भी गए, तो क्या उस बदली हुई दुनिया से दोबारा तालमेल बिठा पाएंगे? बहुत साल पहले मन्मथनाथ गुप्त का एक उपन्यास पढ़ा था, जिसमें एक व्यक्ति मृत्यु के बहुत साल बाद जीवित हो जाता है। वह बदली हुई दुनिया को चकित नजर से देखता है।

भारत में तमाम लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। वे सोचते हैं कि मनुष्य की मृत्यु का मतलब है, पुराने कपड़ों को बदलना, क्योंकि फिर से मनुष्य जन्म लेगा। यहां तो लोग जीवन-मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए मोक्ष की कल्पना भी करते हैं, लेकिन अन्य बहुत से पंथों में लोग मानते हैं कि जीवन सिर्फ एक बार ही मिलता है। इसलिए वे लंबी उम्र तक जीना चाहते हैं। इसके लिए तरह-तरह के प्रयास करते हैं। जीवन खत्म हो जाए, तो दोबारा कैसे जीवित हों, इसकी कल्पना इसी सोच का परिणाम है। यह एक तरह से अमरता की चाहत ही है। इसीलिए कंपनियां पैसा कमाने के लिए इस सोच का फायदा उठाती हैं। कमाल यह है कि यूरोप के बहुत से देशों में इच्छामृत्यु वैध है। वहां ऐसे अस्पताल हैं, जहां आप चाहें तो इच्छामृत्यु प्राप्त कर सकते हैं। आस्ट्रेलिया के एक विज्ञानी ने सौ वर्ष की उम्र में स्विट्जरलैंड में जाकर इच्छामृत्यु प्राप्त की थी। दूसरी तरफ ऐसी कंपनियां हैं, जो शवों को सुरक्षित करना चाहती हैं। जाहिर है कि ये सब पैसा कमाने का धंधा है। पूंजी के इस खेल में अंततः शिकार मनुष्य ही बनता है।

विज्ञानियों ने अपने अथक परिश्रम से हमें चांद पर पहुंचाया है, लेकिन बीच में कुछ कंपनियां मैदान में आ गई हैं। चांद पर जमीनें बेची जाने लगी हैं। बताया जाता है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद पर जमीन खरीदी थी और अक्सर वे उसे दूरबीन के जरिए देखते थे। दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे, जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी होगी। आखिर चांद ने अपनी जमीन का मालिकाना हक किसे दिया, कब दिया, लेकिन जिसे कहते हैं न कि बस एक आइडिया को बेचना है, तो उसे सफलतापूर्वक बेच दिया गया। व्यापारियों की तिजोरियां भर गईं। अब भी भर रही होंगी। मृत्यु के बाद जीवन को बेचना भी एक ऐसा ही आइडिया है।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्वयं का निर्माता है इंसान

जीवन में आने वाली परिस्थितियां कई बार हमारे वश में नहीं होतीं। बीमारियां, संकट, महामारियां, प्राकृतिक आपदाएं या अन्य अनचाहे प्रसंग हमारे जीवन में दस्तक दे ही देते हैं। इन परिस्थितियों के बीच हम कैसा सोचते हैं, किस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, किस तरह का व्यवहार और कर्म करते हैं-यही हमारी नियति को गढ़ता है। मनुष्य के भीतर अपार संभावनाएं हैं। उसका मस्तिष्क, उसकी चेतना और उसकी भावनाएं ही भविष्य की दिशा तय करती हैं। यदि हम नकारात्मक सोच में फंसते हैं, तो वही सोच हमारी वास्तविकता बन जाती है, लेकिन यदि हम आशा, धैर्य और सकारात्मकता का दीपक जलाते हैं, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, हम उनका सामना कर लेते हैं। यही कारण है कि ऋषियों और दार्शनिकों ने बार-बार कहा है-तुम वही बनते हो, जैसा तुम सोचते हो। हर इंसान खुद अपना निर्माता है।

जीवन का प्रत्येक क्षण हमें अवसर देता है कि हम अपनी दिशा स्वयं चुनें। किसी भी इंसान का जीवन पहले से पूरी तरह तय नहीं है। हमारे सोच और कर्म ही हमारे आने वाले कल की पटकथा तैयार करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम निराशा और हताशा के अंधेरों में खोने के बजाय आत्मविश्वास, संयम और विवेक का सहारा लें। वास्तविक शक्ति हमारे भीतर है। जब तक हम अपनी आंतरिक क्षमताओं को नहीं पहचानते और उन्हें सही दिशा में नहीं लगाते, तब तक बाहरी साधन भी हमें सफलता और संतोष नहीं दे सकते। इसलिए जीवन की डोर अपने हाथ में लें। अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए, कर्मों को सजगता से कीजिए और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, तो नियति हमारी लेखनी से ही लिखी जाती है। वास्तव में हर व्यक्ति अपनी नियति का लेखक है-जितना सजग, उतना सफल। जितना सचेत, उतना समर्थ।

ललित गर्ग

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

एकजुट होने का समय

''राष्ट्रपति की कामना'' शीर्षक से प्रकाशित अग्रलेख राष्ट्रपति के अभिभाषण का सटीक विश्लेषण करता है। राष्ट्र के नाम अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देश की प्रगति, सुशासन और भ्रष्टाचार-निरोध की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि शासन-प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है, जो सुशासन के लिए सबसे बड़ी बाधा है। सभी राजनीतिक दल विकास, जनकल्याण और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। दलगत हितों के कारण देशहित के मुद्दों को दरकिनार करना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। आखिर क्यों सभी दल भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के लिए एकजुट नहीं हो सकते? देश में तकनीकी प्रगति और प्रशासनिक सुधारों की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन ठोस न्यायिक सुधार अब तक लागू नहीं हो पाए हैं। न्यायिक सुधार की दिशा में ठोस कदम न उठाना एक गंभीर विडंबना है, जिस पर गहन विचार आवश्यक है। पिछले एक दशक में देश ने आर्थिक, तकनीकी और अवसंरचनात्मक विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन वर्तमान वैश्विक तनावपूर्ण परिस्थितियों ने नई चुनौतियां भी सामने रख दी हैं। इनसे निपटने के लिए विदेशी कूटनीति के साथ-साथ आंतरिक एकजुटता अनिवार्य है। दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक शक्तियां अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर धूमिल कर रही हैं, जो राष्ट्रहित के विपरीत है। जनता को इस स्थिति को भली-भांति समझना होगा और लोकतंत्र में अपने मताधिकार के माध्यम से ऐसे तत्वों को सबक सिखाना होगा। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर भ्रष्टाचार-मुक्त, सुशासित और एकजुट भारत का निर्माण करेंगे, ताकि राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध न हो और आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत और समृद्ध देश विरासत में मिले।

budawanwalas55@gmail.com

दुख का कारण अंतहीन कामनाएं

मानव शरीर में मन का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। मानव-मन में विविध प्रकार की विचार-लहरियां जागृत होती हैं। उठने वाले विचारों की लहरें शुभ भी होती हैं और अशुभ भी। शुभत्व से परिपूर्ण विचार लहरें अशुभत्व से ओत-प्रोत हैं तो जीवन के विकास की जो दिशाएं हैं, वे धूमिल हो जाती हैं। मानव को चाहिए कि वह अपने मन का उपयोग सम्यक प्रकार से करे। मन चंचल है, भागता-दौड़ता रहता है, तरह-तरह के विचार इसमें उभरते रहते हैं, क्या करें, हम तो इस मन के मारे मर गए। बड़ा नटखट है यह मन। इस मन ने हमें परेशान करके रख दिया है। मानव की कामनाएं आकाशवत अनंत हैं। जिस तरह से आकाश का अंत नहीं है, उसी तरह से कामनाओं का भी अंत नहीं है। इच्छाओं, कामनाओं को अनंत आकाश की तरह अनंत बताया है। संसार में कोई भी व्यक्ति इच्छाओं से, कामनाओं से शून्य नहीं है। आवश्यक की आड़ में अनावश्यक कामनाओं को मन में पाल लेने का अर्थ अपने मस्तिष्क को विविध प्रकार के तनावों से आवृत करना है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

विभाजन की त्रासदी

'आंसू छलकाने वाली विभाजन की त्रासदी' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में डा. केएल जुनेजा ने मानवीय दर्द और विस्थापन की पीड़ा को बखूबी चित्रित किया, परंतु विश्लेषण में उस राजनीतिक और प्रशासनिक दूरदृष्टि की कमी का पहलू छूट गया, जिसने इस त्रासदी को टालने का अवसर खो दिया। विभाजन केवल भावनाओं का विस्फोट नहीं था, बल्कि यह नीति निर्धारण की विफलता और तत्कालीन नेतृत्व की अधूरी तैयारियों का परिणाम था, जिसमें सीमांकन, जनगणना और पुनर्वास के वैज्ञानिक व व्यवस्थित उपाय नदारद थे। इस त्रासदी का गहरा विश्लेषण हमें बताता है कि जब निर्णय भावनाओं और दबाव में लिए जाते हैं, तो उनके परिणाम पीढ़ियों तक समाज की चेतना को झकझोरते रहते हैं। राजनीतिक नेतृत्व ने समयबद्ध चरणों में स्थानांतरण और संवाद की प्रक्रिया अपनाई होती तो हिंसा, पलायन और लाशों के काफिलों की भयावह तस्वीरें शायद इतिहास का हिस्सा न बनतीं। भविष्य में ऐसे घटनाक्रमों से बचने के लिए केवल भावनात्मक एकता के नारे काफी नहीं हैं, इसके लिए बहुस्तरीय नीति, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संवाद का स्थायी ढांचा आवश्यक है। इतिहास का उद्देश्य केवल स्मरण नहीं, बल्कि चेतावनी भी है कि सीमाएं नक्शों पर खींची जाती हैं, दिलों में नहीं। जब तक हम राजनीतिक निर्णयों में विवेक और मानवीय संवेदनाओं का संतुलन नहीं साधते, तब तक विकास की कोई भी परिभाषा अधूरी ही रहेगी।

अवनीश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

पोस्ट

डेमोग्राफी बदलने की साजिश पर निर्णायक प्रहार होना ही चाहिए। आंतरिक और बाह्य, दोनों तरह की सुरक्षा के लिए यह अभियान अनिवार्य है। सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो कुछ कहा है, अगर उसका आधा भी जमीनी स्तर पर लागू होता है, तो हमें उस अमेरिका को धन्यवाद कहना चाहिए, जिसने अपनी धौंस और धूर्तता से हमें दबाने की कोशिश की है। सुशांत सरीन@sushantsareen

मैंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में लाइसेंस-परमिट-कोटा राज की शुरुआत होते देखा और अब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन उम्मीद करता हूं कि मरने से पहले इसका पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। प्रधानमंत्री को सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामना। डा. अरविंद विरमानी@dravirmani

आपरेशन सिंदूर, सेमीकंडक्टर, जीएसटी-आर्थिक सुधार, घुसपैठ के खिलाफ डेमोग्राफी मिशन, जेट इंजन और तकनीक में आत्मनिर्भरता का मोदी का मंत्र देश का भाग्य बदलने वाला है। तुषार गुप्ता@Tushar15_

जनपथ

'चक्र सुदर्शन' जब चले करे शत्रु संहार,
'भार्गवास्त्र'- 'नागास्त्र' से तीखी होगी धार।
तीखी होगी धार न इनका कोई सानी,
अगर चले 'ब्रह्मोस' न दुश्मन मांगे पानी।
करवाए 'आकाश तीर' के हमने दर्शन,
रोए मियां मुनीर देख अब 'चक्र सुदर्शन'!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : **0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90** समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 30
****

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 16 अगस्त, 2025

दैनिक जागरण
स्वतंत्रता सुख और शांति की जननी है

आत्मनिर्भरता का उद्घोष

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री के संबोधन की प्रतीक्षा रहती ही है। इस बार अधिक थी, क्योंकि देश घरेलू और बाहरी मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना करने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खुली धमकियों का भी सामना कर रहा है। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन चुनौतियों से पार पाने का संकल्प व्यक्त करते हुए उनसे निपटने के उपाय भी बताए और इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इन घोषणाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत संकटकाल में अपनी शक्ति को पहचान रहा है और हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। इसका संकेत आतंक के आका और भारत के शत्रु पाकिस्तान से स्थगित सिंधु जल समझौते के संदर्भ में खून और पानी साथ नहीं बहने, दीवाली पर जीएसटी का नया स्वरूप लाने, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने, अपना फाइटर जेट बनाने, सेमीकंडक्टर निर्माण में अग्रणी बनने समेत अन्य अनेक घोषणाओं से मिलता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ कदम उठाने की भी है। पीएम के संबोधन में आपरेशन सिंदूर की विशेष चर्चा आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य ही थी।

लाल किले से प्रधानमंत्री के लंबे संबोधन का सार यही है कि भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए कमर कस चुका है। यदि प्रधानमंत्री की घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए किसी को सबसे अधिक सक्रियता दिखानी होगी तो वह है नौकरशाही। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सत्तारूढ़ नेता तमाम घोषणाएं करते हैं, लेकिन नौकरशाही उनके अनुरूप पूरी इच्छाशक्ति और ईमानदारी नहीं दिखाती। यह किसी से छिपा नहीं कि जहां कई घोषणाओं पर एक हद तक अमल हुआ है और उनका लाभ भी मिला है, वहीं कई योजनाएं आधी-अधूरी ही हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो कुछ कहा और जो योजनाएं शुरू करने की घोषणा की, यदि उन पर 60-70 प्रतिशत भी क्रियान्वयन हो सके तो देश के आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनने का रास्ता आसान हो जाएगा और ट्रंप सरीखे मतलबी नेताओं को सही तरह जवाब भी दिया जा सकेगा। ट्रंप भारत को अपना मित्र देश बताते हैं, लेकिन वे उसे धमकाने में भी लगे हैं। चूंकि वे अपनी हद पार कर गए हैं, इसलिए उनकी धमकियों के आगे झुकने का प्रश्न ही नहीं। यह संदेश मोदी सरकार के साथ-साथ देश को भी देना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इससे बच रहे हैं। यह तो राजनीतिक क्षुद्रता ही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर लाल किले पर आयोजित समारोह का बहिष्कार किया। ऐसा तो लोग मोहल्ला समितियों के समारोह में भी नहीं करते।

पंचायतों से उम्मीद

उत्तराखंड के बारह जिलों में ग्राम पंचायतों के साथ ही जिला और क्षेत्र पंचायतों को भी नये मुखिया मिल गए हैं। इसी के साथ तीनों स्तर की पंचायतें जल्द अपना कार्य शुरू कर देंगी। इससे उम्मीद है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में न केवल पूर्व से चल रहे विकास कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी तेजी से हो सकेगा। पंचायतों को ग्राम्य विकास की रीढ़ माना गया है, इसलिए उनका सुदृढ़ होना बेहद जरूरी है।

> पंचायतों के सक्रिय होने से ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व से चल रहे विकास कार्यों को तो गति मिलेगी ही, नई योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन भी हो सकेगा

अच्छी बात है कि इस बार तीनों स्तर पर पंचायतों को युवा एवं पढ़े-लिखे प्रतिनिधि मिले हैं। उनमें से कई तो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में भी पारंगत हैं। उनसे नई सोच के साथ कार्य करने और ग्रामीण समाज को नई दिशा देने की भी उम्मीद की जाती है। पंचायत प्रतिनिधि गांव एवं क्षेत्र की जरूरतों को गहराई से समझते हैं। वह जानते हैं कि क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए किस तरह योजनाओं का क्रियान्वयन जरूरी है। क्षेत्रवासियों के मनोभावों को न तो उनसे बेहतर अधिकारी समझ सकते हैं, न विधायक और सांसद ही। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों से अपेक्षायें अधिक होना भी लाजिमी है। वर्तमान में सरकार भी ग्रामीण अंचल के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सीमांत क्षेत्र के गांवों का विकास तो सरकार की प्राथमिकताओं में है। ऐसे में पंचायतों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पंचायतें इस भूमिका का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगी और अपनी विकासात्मक कार्यप्रणाली से प्रदेश को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगी।

ट्रंप की धमकी को धता बताए भारत

आदित्य सिन्हा

ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य तत्व है। दबाव में अमेरिका से समझौता भविष्य के किसी संकट से निपटने की भारत की क्षमताओं को कमजोर करेगा

यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत रियायती दरों पर रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है। इसने भारत को बड़ी आर्थिक बढ़त दिलाई है। भारत जिस ब्रेंट क्रूड के अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर तेल की खरीद करता आया है, उससे कहीं कम कीमत पर वह रूस से रोजाना 17 से 19 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। इससे भारत के लिए घरेलू ईंधन कीमतों को नियंत्रण में रखने, महंगाई पर लगाम लगाने और विकास के लिए राजकोषीय गुंजाइश बढ़ाने में मदद मिली है। यह कोई अवसरवादी नीति नहीं, बल्कि अस्थिर वैश्विक बाजार में राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक सुनियोजित कदम है। भारत को हो रहा यह लाभ अमेरिका को खटक रहा है। इसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ के 25 प्रतिशत अतिरिक्त हर्जाना लगाने की भी घोषणा की है। यह 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त है। ट्रंप की भारत पर हर्जाना लगाने के पीछे की दलील बेमानी दिखती है, क्योंकि रूसी तेल खरीदने को लेकर तो वे भारत पर ऊंचे टैरिफ और हर्जाना लगाते हैं, लेकिन मास्को से सर्वाधिक मात्रा में तेल खरीद रहे चीन को अनदेखा कर देते हैं। इस मामले में भारत को जिस प्रकार निशाना बनाया जा रहा है, उससे यह केवल एक वाणिज्यिक विवाद न रहकर हमारे संप्रभु नीति निर्माण को भी चुनौती देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव तब बना रहे हैं, जब उनका दावा है कि रूस के साथ उनकी बात सही दिशा में जा रही है। भारत को उनके द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद तेल की कीमतों से लेकर अमेरिकी बाजारों तक में हलचल देखने को मिली है। ऐसी परिस्थितियों में भारत द्वारा तेल खरीद के फैसले का राजनीतिकरण ऊर्जा स्थिरता के परिदृश्य को चोट पहुंचा सकता है। वैसे भी यह रुख-रवैया अपनी सुविधा के अनुसार अपनाया जा रहा है। यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस से 67.5 अरब डालर का व्यापार किया। जबकि 2024 में यूरोप ने रूस से रिकार्ड मात्रा में 1.65 करोड़ टन एलएनजी आयात की। इससे नई दिल्ली में यही धारणा मजबूत हो रही है कि भारत को राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है, जबकि पश्चिमी सहयोगियों को अमेरिका ने छूट दे रखी है।

देखा जाए तो रूसी तेल खरीदकर भारत ने केवल अपनी अर्थव्यवस्था को ही फायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि वैश्विक मुद्रास्फीतिक दबाव को भी नियंत्रित रखने में सहायक बना है। भारत रूसी तेल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा खपा रहा है। यदि भारत ऐसा नहीं करता तो लाजिस्टिक्स एवं अन्य बढ़ी हुई लागतों के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती थी। दुनिया पहले से ही ऊर्जा, खाद्य और परिवहन के स्तर पर महंगाई से परेशान है, तब भारत द्वारा रूसी आयात के अभाव में इस परेशानी में बढ़ोतरी होना तय था।

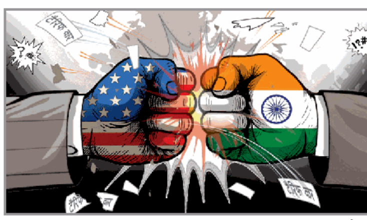

अवधेश राजपूत

घरेलू मोर्चे पर भी रूसी आयात घटाने का अर्थ होगा महंगी पश्चिमी एशियाई आपूर्ति बढ़ाना, ढुलाई की ऊंची लागत झेलना और रिफाइनरियों में इस नई खेप को शोधित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करना। इसका परिणाम या तो उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की ऊंची कीमतों के रूप में निकलेगा या फिर सरकार को तेल सब्सिडी बढ़ानी होगी, जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च के लिए उसकी राजकोषीय गुंजाइश घटेगी। इस मुद्दे से जुड़े राजनीतिक पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताता है और चीन की एक काट के रूप में देखता है। क्या कोई अपने रणनीतिक साझेदार को टैरिफ लगाने-बढ़ाने की धमकियां देता है और उसकी ऊर्जा नीति को लेकर सार्वजनिक प्रलाप करता है। इस तरह के आक्रामक कदम रक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग में दशकों के बने भरोसे पर आघात करते हैं। इससे वाशिंगटन के साथ भावी सक्रियता को लेकर भी भारत और सतर्कता बरतेगा, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में आ रही तेजी निस्तेज पड़ेगी।

इतिहास साक्षी है कि भारत ने सदैव अपनी विदेश नीति स्वायत्तता की रक्षा की है। महाशक्तियों के दबाव वाले दौर में भी भारत झुका नहीं। विदेश नीति में भारत का यह स्वतंत्र रवैया यूक्रेन युद्ध में भी रेखांकित हुआ, जब पश्चिमी देशों द्वारा उकसावे के बावजूद भारत अपने रुख पर अडिग रहा। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने यह उल्लेख भी किया कि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में प्रत्येक देश अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि पारंपरिक खाड़ी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यूरोप का रुख किए जाने से उपजी परिस्थितियों में ही रूस से आयात बढ़ा और अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देश किस तरह खुद रूस से ऊर्जा खरीदारी कर इस मामले में दोहरे रवैये का परिचय दे रहे हैं।

यदि वर्तमान परिस्थितियों में भारत और चीन रूसी तेल का आयात बंद कर दें तो कच्चे तेल की कीमतों में एकाएक 20 डालर प्रति बैरल तक की बढ़ोतरी संभव है। विश्व लंबे समय तक ऊंची कीमतों के दौर को झेलने के साथ आपूर्ति में भी गतिरोध झेलने को विवश होगा। सस्ते रूसी तेल के केवल वाणिज्यिक लाभ ही नहीं, बल्कि यह भारत के वृहद आर्थिक स्थायित्व का भी एक मजबूत स्तंभ है, जो वैश्विक बाजार को भी संतुलन प्रदान कर रहा है। किसी तरह के राजनीतिक दबाव में इससे किनारा करना आर्थिक दृढ़ता और रणनीतिक स्वायत्तता दोनों को क्षति पहुंचाएगा।

जब वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य अस्थिरता एवं अनिश्चितता से जूझ रहा है और ओपेक प्लस देश आपूर्ति में संभावित समायोजन के संकेत दे रहे हैं और बाजार कूटनीतिक घटनाक्रमों से प्रभावित हो रहे हैं, तब भारत को अपने आर्थिक एवं रणनीतिक लचीलेपन को हर हाल में कायम रखना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य तत्व है और किसी तरह के दबाव में उससे समझौता भविष्य के किसी संकट से निपटने की भारत की क्षमताओं को कमजोर करेगा। ऊर्जा नीति में स्वतंत्र रुख-रवैया घरेलू स्थायित्व को सुरक्षा कवच प्रदान करने के साथ ही अमेरिका-भारत संबंधों की दूरगामी सेहत के भी अनुकूल होगा।

(लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

पूंजी के खेल का शिकार बनता मनुष्य

क्षमा शर्मा

पैसे कमाने के लिए कंपनियां लोगों की चाहत को भुनाने और उन्हें सब्जबाग दिखाने का धंधा कर रही हैं

विज्ञान की दुनिया बेशुमार चमत्कारों से भरी है, लेकिन ये चमत्कार किसी परी या बौने की जादुई छड़ी से न होकर विज्ञान आधारित नियमों के अनुसार ही होते हैं। हाल में अमेरिका में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया, जिसे तीस साल पहले सुरक्षित भ्रूण से दुनिया में लाया गया है। इसे दुनिया का सबसे बूढ़ा बच्चा बताया जा रहा है। इसी तरह दुनिया से गायब वुली वोल्फ की वापसी हो चुकी है। डोडो और डायनासोर के बारे में भी कहा जा रहा है कि एक बार वे फिर धरती पर विचरेंगे। विशालकाय हाथी मैमथ को भी वापस लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत-सी लुप्त प्रजातियों की वापसी चकित करती है। क्लोनिंग के जरिए जन्मी डाली भेड़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक व्यक्ति ने भी लाखों डालर खर्च करके अपने मृत डागी का क्लोन बनवाया था। विज्ञान के जरिए ही मनुष्य चांद तक पहुंचा। अब मंगल ग्रह पर जाने की सोच रहा है। विज्ञान ऐसी तमाम बातों को भी खोजने की कोशिश कर चुका है, जिनमें सफलता नहीं मिली। जैसे कि रसायनशास्त्र के विकास के बारे में कहा जाता है कि उसका विकास अमृत और सोने की खोज के बारे में हुआ। अमृत भारतीय मनीषा में भी बहुत जगह बनाता है। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान यह निकला भी था और देवताओं और दानवों में इसके अधिकार के लिए युद्ध हुआ था।

मनुष्य मृत्यु से बहुत डरता है। वह हमेशा जीवित रहना चाहता है। चिकित्सा विज्ञान ने उसे अब लंबी आयु भी प्रदान की है, लेकिन मृत्यु पर विजय अभी तक नहीं पाई जा सकी है। स्पेन के एक गांव में लोगों से कहा जाता है कि उन्हें मरना नहीं है। इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहें। एक ऐसी कथा भी है कि एक राजा ने अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। फिर वह ऐसे स्थान पर पहुंचा, जहां लोग अमर थे। वे जीवन से ऊब चुके थे। मरना चाहते थे, लेकिन मर नहीं सकते थे। यह दुनिया विविध विचारों से भरी हुई है। अभी पिछले दिनों खबर आई कि जर्मनी की एक बायो लैब शवों को सुरक्षित करना चाहती है, ताकि भविष्य में यदि विज्ञान का इतना विकास हो जाए कि मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सके, तो इन्हें फिर से जीवित किया जा सकेगा। यह लैब इसके लिए दो लाख डालर लेगी। अब तक छह सौ से अधिक लोगों ने उसके यहां बुकिंग कराई है। इसे क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम दिया गया है। इस प्रक्रिया के बारे में लैब ने बताया है कि मृत्यु के बाद शरीर को बेहद ठंडे तापमान पर सुरक्षित किया जाएगा, ताकि शरीर के ऊतकों को कोई नुकसान न पहुंचे और वापस वे जीवित किए जा सकें। बायो लैब का कहना है कि उसे व्यक्ति के इस दुनिया से जाने के बाद फौरन सूचना मिलनी चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में देरी ठीक नहीं होगी। यह दुनिया की पहली ऐसी लैब बताई जा रही है। जल्दी ही यह लैब अमेरिका में भी अपना काम शुरू करने वाली है।

लोगों में अमरता की बढ़ती चाहत। प्रतीकात्मक

यह भी कहा जा रहा है कि मृत दिमाग को दोबारा से काम के योग्य बनाना असंभव है, क्योंकि दिमाग की संरचना बहुत जटिल होती है। इसे अब तक समझा नहीं जा सका है। मान लीजिए ये लोग पांच सौ साल बाद जीवित हो भी गए, तो क्या उस बदली हुई दुनिया से दोबारा तालमेल बिठा पाएंगे? बहुत साल पहले मन्मथनाथ गुप्त का एक उपन्यास पढ़ा था, जिसमें एक व्यक्ति मृत्यु के बहुत साल बाद जीवित हो जाता है। वह बदली हुई दुनिया को चकित नजर से देखता है।

भारत में तमाम लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। वे सोचते हैं कि मनुष्य की मृत्यु का मतलब है, पुराने कपड़ों को बदलना, क्योंकि फिर से मनुष्य जन्म लेगा। यहां तो लोग जीवन-मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए मोक्ष की कल्पना भी करते हैं, लेकिन अन्य बहुत से पंथों में लोग मानते हैं कि जीवन सिर्फ एक बार ही मिलता है। इसलिए वे लंबी उम्र तक जीना चाहते हैं। इसके लिए तरह-तरह के प्रयास करते हैं। जीवन खत्म हो जाए, तो दोबारा कैसे जीवित हों, इसकी कल्पना इसी सोच का परिणाम है। यह एक तरह से अमरता की चाहत ही है। इसीलिए कंपनियां पैसा कमाने के लिए इस सोच का फायदा उठाती हैं। कमाल यह है कि यूरोप के बहुत से देशों में इच्छामृत्यु वैध है। वहां ऐसे अस्पताल हैं, जहां आप चाहें तो इच्छामृत्यु प्राप्त कर सकते हैं। आस्ट्रेलिया के एक विज्ञानी ने सौ वर्ष की उम्र में स्विट्जरलैंड में जाकर इच्छामृत्यु प्राप्त की थी। दूसरी तरफ ऐसी कंपनियां हैं, जो शवों को सुरक्षित करना चाहती हैं। जाहिर है कि ये सब पैसा कमाने का धंधा है। पूंजी के इस खेल में अंततः शिकार मनुष्य ही बनता है।

विज्ञानियों ने अपने अथक परिश्रम से हमें चांद पर पहुंचाया है, लेकिन बीच में कुछ कंपनियां मैदान में आ गई हैं। चांद पर जमीनें बेची जाने लगी हैं। बताया जाता है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद पर जमीन खरीदी थी और अक्सर वे उसे दूरबीन के जरिए देखते थे। दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे, जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी होगी। आखिर चांद ने अपनी जमीन का मालिकाना हक किसे दिया, कब दिया, लेकिन जिसे कहते हैं न कि बस एक आइडिया को बेचना है, तो उसे सफलतापूर्वक बेच दिया गया। व्यापारियों की तिजोरियां भर गईं। अब भी भर रही होंगी। मृत्यु के बाद जीवन को बेचना भी एक ऐसा ही आइडिया है।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्वयं का निर्माता है इंसान

जीवन में आने वाली परिस्थितियां कई बार हमारे वश में नहीं होतीं। बीमारियां, संकट, महामारियां, प्राकृतिक आपदाएं या अन्य अनचाहे प्रसंग हमारे जीवन में दस्तक दे ही देते हैं। इन परिस्थितियों में हम कैसा सोचते हैं, किस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, किस तरह का व्यवहार और कर्म करते हैं-यही हमारी नियति को गढ़ता है। मनुष्य के भीतर अपार संभावनाएं हैं। उसका मस्तिष्क, उसकी चेतना और उसकी भावनाएं ही भविष्य की दिशा तय करती हैं। यदि हम नकारात्मक सोच में फंसते हैं, तो वही सोच हमारी वास्तविकता बन जाती है, लेकिन यदि हम आशा, धैर्य और सकारात्मकता का दीपक जलाते हैं, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, हम उनका सामना कर लेते हैं। यही कारण है कि ऋषियों और दार्शनिकों ने बार-बार कहा है-तुम वही बनते हो, जैसा तुम सोचते हो। हर इंसान खुद अपना निर्माता है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

जीवन का प्रत्येक क्षण हमें अवसर देता है कि हम अपनी दिशा स्वयं चुनें। किसी भी इंसान का जीवन पहले से पूरी तरह तय नहीं है। हमारे सोच और कर्म ही हमारे आने वाले कल की पटकथा तैयार करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम निराशा और हताशा के अंधेरों में खोने के बजाय आत्मविश्वास, संयम और विवेक का सहारा लें। वास्तविक शक्ति हमारे भीतर है। जब तक हम अपनी आंतरिक क्षमताओं को नहीं पहचानते और उन्हें सही दिशा में नहीं लगाते, तब तक बाहरी साधन भी हमें सफलता और संतोष नहीं दे सकते। इसलिए जीवन की डोर अपने हाथ में लें। अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए, कर्मों को सजगता से कीजिए और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, तो नियति हमारी लेखनी से ही लिखी जाती है। हर व्यक्ति अपनी नियति का लेखक है-जितना सजग, उतना सफल। जितना सचेत, उतना समर्थ।

ललित गर्ग

न्यूट्रिनो की विचित्र दुनिया

प्रदीप

> न्यूट्रिनो कण सूर्य से निकलकर पृथ्वी से होकर बहुत बड़ी मात्रा में गुजरते हैं। इनमें सूर्य की जानकारी भी समाहित होती है

हमारे विराट ब्रह्मांड में अरबों-खरबों कण लगातार विचरण करते रहते हैं। इन कणों में से एक कण, जो बहुत ही विचित्र, रहस्यमय और अदृश्य होता है, उसे 'न्यूट्रिनो' कहते हैं। न्यूट्रिनो एक ऐसा कण है, जो अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण विज्ञानियों के लिए अपनी खोज के समय से ही से चुनौती और आकर्षण का केंद्र रहा है। ये कण हमारे सौरमंडल के मुखिया सूरज के भी भीतर गहराई में जन्म लेते हैं, जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। न्यूट्रिनो सूर्य से निकलकर पृथ्वी से होकर बहुत बड़ी मात्रा में गुजरते हैं। इनमें सूर्य की जानकारी भी समाहित होती है।

यूनिवर्सिटी आफ मेलबर्न और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों ने अपने एक नए शोधपत्र में यह दिखाया है कि किस प्रकार से वर्तमान में निर्माणाधीन डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट (डीयूएनई) परियोजना हमें सूर्य के संदेशवाहकों 'न्यूट्रिनो' के सबसे गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगी। न्यूट्रिनो एक मूलभूत कण है, जिसके बारे में 1930 में पहली बार विज्ञानियों को संकेत मिले थे। इसका नाम ग्रीक शब्द 'न्यू' (नई) और 'ट्रिनो' (तीन) से लिया गया है, क्योंकि ये तीन तरह के होते हैं। ये कण अपनी मौजूदगी के बहुत कम साक्ष्य छोड़ते हैं, जिससे इन्हें पहचानना और इनका अध्ययन करना काफी कठिन होता है। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान बहुत कम होता है और इसकी गति प्रकाश की गति के लगभग बराबर होती है, जिसकी बदौलत यह भारी कणों से कहीं ज्यादा तेजी से यात्रा कर पाते हैं।

वर्ष 1956 में शोधकर्ताओं ने न्यूट्रिनो का प्रत्यक्ष रूप से पता लगाया था और जल्द ही यह भी साबित हो गया कि सूर्य से भारी मात्रा में न्यूट्रिनो निकलते हैं- हर सेकंड करोड़ों की संख्या में ये कण पृथ्वी से होकर गुजरते हैं, लेकिन हमें इसका कोई अनुभव नहीं होता। न्यूट्रिनो तीन तरह के होते हैं- इलेक्ट्रान न्यूट्रिनो, म्यूआन न्यूट्रिनो और टाऊ न्यूट्रिनो। सूर्य से सिर्फ इलेक्ट्रान न्यूट्रिनो निकलते हैं, लेकिन लंबी यात्रा के दौरान वे अन्य प्रकारों में बदल जाते हैं, जिन्हें शुरुआती प्रयोगों में नहीं पकड़ा जा सका था।

2001 में कनाडा के एसएनओ वेधशाला ने एक प्रयोग के माध्यम से यह साबित कर दिया कि न्यूट्रिनो प्रकार बदलते हैं-इस प्रक्रिया को 'न्यूट्रिनो आस्सीलेशन' कहा जाता है। अब अमेरिका में निर्माणाधीन डीयूएनई परियोजना, जो 70,000 टन द्रव आर्गन का प्रयोग करेगी, इन न्यूट्रिनो कणों का अत्यधिक सटीकता से विश्लेषण कर पाएगी। तीन अरब अमेरिकी डालर से अधिक लागत वाली डीयूएनई सभी तरह के न्यूट्रिनो का मापन करेगी और उनके परिवर्तन की दर को समझने में सहायता करेगी। इससे न सिर्फ सूर्य के भीतरी रहस्यों की जानकारी मिलेगी, बल्कि यह भी पता चलेगा कि न्यूट्रिनो कैसे और क्यों प्रकार बदलते हैं।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

मेलबाक्स

एकजुट होने का समय

''राष्ट्रपति की कामना'' शीर्षक से प्रकाशित अग्रलेख राष्ट्रपति के अभिभाषण का सटीक विश्लेषण करता है। राष्ट्र के नाम अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देश की प्रगति, सुशासन और भ्रष्टाचार-निरोध की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि शासन-प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है, जो सुशासन के लिए सबसे बड़ी बाधा है। सभी राजनीतिक दल विकास, जनकल्याण और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। दलगत हितों के कारण देशहित के मुद्दों को दरकिनार करना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। आखिर क्यों सभी दल भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के लिए एकजुट नहीं हो सकते? देश में तकनीकी प्रगति और प्रशासनिक सुधारों की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन ठोस न्यायिक सुधार अब तक लागू नहीं हो पाए हैं। न्यायिक सुधार की दिशा में ठोस कदम न उठाना एक गंभीर विडंबना है, जिस पर गहन विचार आवश्यक है। पिछले एक दशक में देश ने आर्थिक, तकनीकी और अवसंरचनात्मक विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन वर्तमान वैश्विक तनावपूर्ण परिस्थितियों ने नई चुनौतियां भी सामने रख दी हैं। इनसे निपटने के लिए विदेशी कूटनीति के साथ-साथ आंतरिक एकजुटता अनिवार्य है। दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक शक्तियां अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर धूमिल कर रही हैं, जो राष्ट्रहित के विपरीत है। जनता को इस स्थिति को भली-भांति समझना होगा और लोकतंत्र में अपने मताधिकार के माध्यम से ऐसे तत्वों को सबक सिखाना होगा। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर भ्रष्टाचार-मुक्त, सुशासित और एकजुट भारत का निर्माण करेंगे, ताकि राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध न हो और आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत और समृद्ध देश विरासत में मिले।

budawanwalas55@gmail.com

डालर मुक्तता की लहर

दशकों से डालर का इस्तेमाल पूरी दुनिया पर वर्चस्व जमाने के एक हथियार के रूप में किया गया है। एक स्थिर और मजबूत मुद्रा, दुनिया के अधिकांश देशों के साथ केवल आयात-निर्यात ही नहीं, बल्कि बड़े कर्ज के लेन-देन, बड़ी बैंकें एवं वित्तीय संस्थाएं, आधुनिक तकनीक, लोकतांत्रिक प्रणाली के फायदे, आक्रामक नीतियां-इन सभी कारणों से डालर का दबदबा पूरी दुनिया में स्थापित हुआ है, लेकिन अब दुनिया तेजी से बदल रही है। कई कारणों से डालर का प्रभाव-या उसकी एकाधिकार जैसी स्थिति-डगमगाती नजर आ रही है। इस विपरीत प्रवृत्ति को अब पूरी दुनिया में ''डीडालराइजेशन'' (डालर मुक्तता) के नाम से जाना जा रहा है। दरअसल पहले भी कुछ समय तक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक-वित्तीय लेन-देन अन्य मुद्राओं में होते थे। 1970 में दुनिया के देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का 85 प्रतिशत हिस्सा डालर में रखा जाता था, जो 2023 में घटकर 58 प्रतिशत रह गया है। आज आस्ट्रेलियाई डालर और कैनेडियन डालर को लोकप्रियता मिल रही है। डालर का विकल्प तैयार करने की पहल रूस और चीन ने की है। 2014 में रूस ने क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद आर्थिक प्रतिबंधों का सामना किया। तभी से रूस ने डीडालराइजेशन अभियान शुरू कर दिया। 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, जिससे इस अभियान को असली गति मिली। 2015 में रूस और चीन के बीच 90 प्रतिशत व्यापार डालर में होता था, जो 2024 में घटकर 10 प्रतिशत रह गया। इसी तरह 2024 में रूस और ईरान के बीच 95 प्रतिशत व्यापार उनकी स्थानीय मुद्राओं-रूबल और रियाल-में हुआ। इन देशों ने खुले तौर पर डालर से दूरी बना ली है। इन्होंने दुनिया की मान्यता प्राप्त मुद्रा प्रणाली स्विफ्ट को भी अस्वीकार कर दिया। इसके जवाब में रूस ने 2014 में अपनी प्रणाली विकसित की, जिसमें अमेरिका को छोड़कर जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन, यूरोपीय संघ, रूस और ईरान जैसे सात बड़े देश शामिल हैं। इसका सीधा मतलब है कि आने वाला समय अमेरिकी डालर के लिए कठिन साबित होगा।

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****